सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2011-12 प्रतिवेदन का संख्या - 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2011-12 प्रतिवेदन का संख्या - 1

विषयसूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii

अध्याय - 1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड का परिचय	1.1	1
प्रस्तावना	1.1.1	1
चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सांराश	1.2	1
बजट आकलन के साथ वास्तविक	1.2.1	3
झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन	1.2.2	4
राज्य के संसाधन	1.3	5
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.3.1	5
राज्य की विशेष जरूरतों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	1.3.2	7
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.3.3	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.4	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.4.1	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.4.2	12
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.4.3	12
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	13
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.5.1	13
कार्य कलापों के संदर्भ में कुल व्यय	1.5.2	14
राजस्व व्यय	1.5.3	15
पूँजीगत व्यय	1.5.4	16
वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय	1.5.5	16
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.5.6	19
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली	1.5.7	20
व्यय की गुणवत्ता	1.6	22
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.6.1	22
कुल व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.6.2	23
सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.7	25
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.7.1	26
अपूर्ण परियोजनायें	1.7.2	26
निवेश एवं वापसी	1.7.3	26
राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1.7.4	27
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.7.5	28
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.8	29
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.8.1	29
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.8.2	31
ऋण धारणीयता	1.8.3	31
राजकोषीय असंतुलन	1.9	33
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.9.1	33
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण	1.9.2	35
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.10	36

विषयसूची

अध्याय - 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	2.1	39
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	39
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	39
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.4	40
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	40
निरंतर बचतें	2.4.2	42
2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	2.4.3	42
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	2.4.4	43
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान	2.4.5	44
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.4.6	44
वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित	2.4.7	44
प्रत्यार्पित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं हुई	2.4.8	44
व्यय का वेग	2.4.9	44
विभागीय आँकड़ों का असमायोजन	2.5	45
लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अधीन प्रावधान	2.6	46
निष्कर्ष	2.7	47
अनुशंसाएँ	2.8	47

अध्याय - 3: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	3.1	49
ए.सी. विपत्र के आहरण का झुकाव	3.2	50
ए.सी. विपत्र से योजना निधि का आहरण	3.3	51
पूँजीगत कार्यों के लिये ए.सी. विपत्रों से निधि का अनाधिकृत आहरण	3.4	52
वित्तीय वर्ष के अन्त में ए.सी. विपत्र का आहरण	3.5	53
ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण की पुनरावृति	3.6	54
ए.सी. विपत्र के द्वारा आहरित निधि को बैंक खाते में रखना	3.7	54
लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव	3.8	55
निष्कर्ष	3.9	56
अनुशंसाएँ	3.10	56

अध्याय - 4: वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना		
भुगतित अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.1	57
स्वायत निकाय/प्राधिकरण द्वारा लेखों का विलंबित प्रस्तुतीकरण	4.2	58
धारा 14 एव 15 के अन्तर्गत स्वायत निकाय/प्राधिकरण	4.2.1	58
धारा 19 एवं 20 (i) के अन्तर्गत स्वायत निकाय/प्राधिकरण	4.2.2	58
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि	4.3	59
व्यक्तिगत जमा लेखा	4.4	60
सहायता अनुदान का संवितरण	4.5	60
निष्कर्ष	4.6	60
अनुशंसाएँ	4.7	61

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-ए	झारखण्ड का परिचय	63
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	64
परिशिष्ट- 1.1 पार्ट-सी	वित्त लेखे की अभिन्यास	64
परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-ए	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	65
परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-बी	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007	66
परिशिष्ट- 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	67
परिशिष्ट- 1.4 पार्ट-ए	वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	70
परिशिष्ट- 1.4 पार्ट-बी	31 मार्च 2012 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	74
परिशिष्ट- 1.5	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण	76
परिशिष्ट- 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों विनियोग की विवरणी	77
परिशिष्ट- 2.2	वर्ष 2011-12 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 10 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	79
परिशिष्ट- 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	83
परिशिष्ट- 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	84
परिशिष्ट- 2.5	निधि का अधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनयोग	86
परिशिष्ट- 2.6	वास्तविक बचत से अधिक राशि (प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख अधिक)	87
परिशिष्ट- 2.7	₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत, जो अभ्यर्पित नहीं की गई, की विवरणी	88
परिशिष्ट- 2.8	30 और 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि के मामले	89
परिशिष्ट- 2.9	वर्ष के अंत में व्यय की वेग	91
परिशिष्ट- 2.10	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत कार्यक्रम निधियों का बजट	92
परिशिष्ट- 3.1	चयनित विभागों में बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए सी विपत्र)	93
परिशिष्ट- 3.2	वर्ष 2009-12 के दौरान ए सी विपत्र (नमूना जॉच) से निधियों का आहरण	94
परिशिष्ट- 3.3	आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण	96
परिशिष्ट- 3.4	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का बार-बार आहरण	97
परिशिष्ट- 3.5	झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ	99
परिशिष्ट- 4.1	झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ	100
परिशिष्ट- 4.2	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित किये गये इकाईयों की सूची	101
परिशिष्ट- 4.3	हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि मामलों का विभागवार ब्यौरा	104
परिशिष्ट- 5.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	105

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच में पाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। आवश्यकता अनुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से भी प्राप्त की गई है।

3. अध्याय 3 में तीन चयनित विभागों के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम समाहित है।

4. अध्याय 4 वित्तीय प्रतिवेदन वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड सरकार के मार्च 2012 का समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2007, बजट दस्तावेजों, मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.), आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) का प्रतिवेदन एवं विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय आँकड़ों पर आधारित है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संगठित है।

अध्याय 1 वित्तीय लेखाओं की लेखा परीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2012 को सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति, प्रतिबद्ध व्यय की वास्तविकता के सापेक्ष बजट आकलन और ऋण प्रतिरूपों पर एक अंतर्दृष्टि के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों से राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (भा.स.) से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करती है ।

अध्याय 2 विनियोजन लेखाओं के लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों की अनुदान-वार विवरणी प्रस्तुत करने एवं आवंटित संसाधनों के सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करती है।

अध्याय 3 तीन विभागों क्रमशः शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं गृह विभाग जिसमें वृहद ए.सी.विपत्र बकाया था, के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तुत करती है।

अध्याय 4 झारखण्ड सरकार की विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है।

प्रतिवेदन निष्कर्षों के समर्थन में सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समानुक्रमित की गई आकड़ों का संकलन भी है। प्रतिवेदन के अन्त में ***परिशिष्ट 5.1*** प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दों एवं संक्षिप्त रूपों का शब्दावली प्रस्तुत करती है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

अध्याय 1

राजकोषीय अनुशासन : राज्य सरकार ने 2011-12 में राजकोषीय स्थिति सुधारने में सफल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 22,420 करोड़) 19.4 *प्रतिशत* बढ़ी है जबकि राजस्व व्यय (₹ 20,992 करोड़) 17 *प्रतिशत* से बढ़ा है। फलस्वरूप, वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व आधिक्य ₹ 1,428 करोड़ से बढ़ा है।

तथापि, राजस्व आधिक्य मध्यकालीन राजकोषीय नीति के लक्ष्य ₹ 5,379 करोड़ की तुलना में कम था। राजकोषीय घाटा (₹ 1,924 करोड़) भी वर्ष 2011-12 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 1.54 *प्रतिशत* रहा जो ते.वि.आ. के अनुशंसा के अन्दर (तीन *प्रतिशत*) था। यद्यपि, वर्ष 2011-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में वृद्धि ते.वि.आ. मानदण्ड 14.14 *प्रतिशत* के सापेक्ष 12.1 *प्रतिशत* रहा।

वर्ष 2011-12 के दौरान, वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आकलन से ₹ 5,326 करोड़ कम रहा। राज्य के स्वयं का कर एवं कर भिन्न राजस्व का समावेशन 45 *प्रतिशत* था, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान का समावेशन 55 *प्रतिशत* रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 86 *प्रतिशत* था। इसकी वृद्धि स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर से काफी अधिक थी। योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) और गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 36 *प्रतिशत* एवं 64 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में यो.रा.व्य. 27 *प्रतिशत* से और गै.यो.रा.व्य. 12 *प्रतिशत* से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता कुल राजस्व व्यय का 22 *प्रतिशत* था।

पूँजीगत व्ययः वर्ष 2011-12 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 3,159 करोड़) वर्ष 2011-12 के सापेक्ष ₹ 495 करोड़ बढ़ा। तथापि, इसका *प्रतिशत* वर्ष 2009-10 के दौरान, 15 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व एवं प्राथमिक आधिक्य के बावजूद, 13 *प्रतिशत* पर स्थिर रहा। पूंजीगत व्यय से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत* एम.टी.एफ.पी के 3.15 *प्रतिशत* के अनुमान के सापेक्ष 2.54 *प्रतिशत* रहा।

विकास व्यय पर जोर : कुल विकास व्यय वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 15 *प्रतिशत* के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 54 *प्रतिशत* थी, जबकि विकासात्मक पूँजीगत व्यय केवल 13 *प्रतिशत* थी।

सरकारी निवेशों की समीक्षा : सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों (31 मार्च, 2012 तक ₹ 182.57 करोड़) पर प्रतिफल विगत पाँच वर्षों के दौरान एक *प्रतिशत* से भी कम थी, जबकि 2007-12 के दौरान, सरकारी उधारों पर व्यय अपेक्षाकृत काफी अधिक थी (औसत ब्याज दर 7.42 *प्रतिशत* से 8.03 *प्रतिशत*)।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का हस्तांतरण : राज्य बजट के बाहर, भारत सरकार वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 4,194.42 करोड़ का हस्तांतरण सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। चूंकि वार्षिक वित्त लेखे ऐसे निधियों के प्रवाह को

अधिग्रहण नहीं करती है, अतएव, राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय इस सीमा तक कम हो जाता है। इसके अलावा, अभिकरणों को निधियों का सीधा हस्तांतरण जबतक इसमें समरूप लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं होता है, उन अभिकरणों द्वारा निधियों का अनुचित अनुप्रयोग के खतरों को भी बढ़ाती है।

राजकोषीय दायित्व : राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 30,664 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष सात *प्रतिशत* बढ़ा। राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. के 28 *प्रतिशत* से धीरे-धीरे घटकर 24.7 *प्रतिशत* (ते.वि.आ. के वर्ष के लिए 28.5 *प्रतिशत* की अनुशंसा के विरूद्ध) हो गया।

ऋण धारणीयता : वर्ष 2007-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा/आधिक्य के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में (-)₹ 2,022 करोड़ से ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वर्ष 2010-11 में ₹ 1,825 करोड़ की तुलना में यह वर्ष 2011-12 के दौरान आंशिक रूप से कम हुआ (₹ 1,618 करोड़)। तथापि, राज्य ऋण धारणीय स्थिति की ओर अग्रसर था। ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात, वर्ष 2011-12 के दौरान, एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 25 *प्रतिशत* के सापेक्ष 24.7 *प्रतिशत* था।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रणः वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 9,998.50 करोड़ की विशाल बचतें हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उप-शीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचतें राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 420.16 करोड़ उपबंधों से अधिक व्यय हुए जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-2011 के दौरान किया गया ₹ 8,120.63 करोड़ का अधिक व्यय को भी नियमित किया जाना शेष था। विगत पाँच वर्षों से, सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने वाले नौ विभागों में लगातार बचतें दर्ज की गई। 79 उप-शीर्षों में, ₹ 3,252.83 करोड़ का अभ्यर्पण वर्ष के अंतिम दो दिनों में किया गया जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों में उपयोग करने का कोई अवसर नहीं रहा। 16 शीर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में किया गया। व्यय का वेग बजट एवं व्यय पर उचित नियंत्रण को बाधित करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय (₹ 20,101 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 9,822 करोड़) का महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ समाशोधन नहीं किया।

अध्याय 3

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का अनुपालन लेखा परीक्षा : झारखण्ड में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से वर्ष 2000-2012 के दौरान विशाल (₹ 13,543 करोड़) का आहरण किया गया और विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नहीं जमा करने के कारण विपत्र दीर्घावधि तक बकाया (₹ 6,861 करोड़, जून 2012 तक) रहा। ए.सी. विपत्रों का आहरण ऐसे उद्देश्यों के लिए भी पाया गया जिसके लिए अग्रिम आहरण मान्य नहीं था। विभागों ने योजना कार्यान्वयन एवं अन्य योजना/पूँजीगत व्यय के लिए भी ए.सी.विपत्र का आहरण किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी.विपत्रों के जमा करने संबंधी गलत प्रमाण पत्र देकर बार-बार ए.सी.विपत्रों का आहरण किया। हमलोगों ने यह भी अवलोकन किया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना निधि का आहरण, यद्यपि इसका शीघ्र भुगतान आवश्यक नहीं था, ए.सी. विपत्र से बजटीय आवंटनों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया। साथ ही व्यय नहीं किए गए/अप्रयुक्त ए.सी. विपत्र से आहरित राशि सरकारी खातों में नहीं रखकर बैंक खातों में रखा गया। आगे, राज्य बजट में फ्लैगशीप कार्यक्रमों के निधियों का सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका आहरण ए.सी.विपत्रों से किया गया।

अध्याय 4

वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना : राज्य के संस्थाओं/निकायों द्वारा ₹ 6,836.04 करोड़ के सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया, जिससे राज्य सरकार इसके संचालन में दायित्व सुनिश्चितिकरण एवं कार्यदक्षता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने में बाधित हुई। सितम्बर 2012 तक 74 निकायों और प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) झारखण्ड को प्राप्त नहीं हुए। व्यक्तिगत जमा खाता, जिसमें सरकारी राशि जमा थी, वित्तीय वर्ष के अंत में बंद नहीं किया गया था।

अध्याय 1

अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त

1.1 झारखण्ड का परिचय

भारतीय संघ का 28 वाँ राज्य, झारखण्ड,15 नवम्बर 2000 को बिहार से अलग कर बनाया गया। यह राज्य कुल 79,714 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला है तथा राज्य की आबादी 3.30 करोड़ है। राज्य में विशाल वन क्षेत्र एवं खनिज भंडार है तथा इसकी दो तिहाई श्रम-शक्ति कृषि पर निर्भर है। ***परिशिष्ट 1.1 के पार्ट-ए*** में राज्य का संक्षिप्त सामाजिक व आर्थिक रूपरेखा दी गई है। सामाजिक विकास के पहलू पर देखा जाए तो झारखण्ड सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ी हुई है। झारखण्ड में सम्पूर्ण भारत के औसत स्तर से अपेक्षाकृत कम शिक्षा दर (67.63 *प्रतिशत*), अधिक मातृत्व मृत्यु दर (261 प्रति लाख), कम शिशु मृत्यु दर (41 प्रति हजार जीवित जन्म) तथा अपेक्षाकृत अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। झारखण्ड का जनघनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। पिछले दशक में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.46 *प्रतिशत*) की तुलना में धीमी गति से वृद्धि करते हुए 14.07 *प्रतिशत* रही ।

1.1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2011-12 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में पिछले पाँच वर्षों में समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखे के संरचना एवं रूपरेखा को ***परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी*** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को ***परिशिष्ट 1.1 पार्ट-सी*** दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए*** में दिये गये हैं। राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े ***परिशिष्ट 1.3*** में दिये गये हैं।

1.2 चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सांराश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2010-11) के साथ-साथ चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि ***परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए*** वर्ष 2011-12 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियाँ	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12		
खण्ड क: राजस्व					**गैर योजना**	**योजना**	**कुल**
18781.12	राजस्व प्राप्तियाँ	22419.45	17944.74	राजस्व व्यय	13345.30	7646.28	20991.58
5716.63	कर राजस्व	6953.89	6990.80	सामान्य सेवायें	7399.49	446.07	7845.56
2802.89	कर भिन्न राजस्व	3038.22	6707.30	सामाजिक सेवायें	3728.14	3558.89	7287.03
6154.35	संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	7169.93	4246.47	आर्थिक सेवायें	2217.67	3641.32	5858.99
4107.25	भारत सरकार से अनुदान	5257.41	0.17	सहायता अनुदान एवं अंशदान	--	--	--
खण्ड - ख: पूँजीगत							
	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	2664.30	पूंजीगत परिव्यय	47.88	3111.49	3159.37
24.12	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	23.42	307.56	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	31.21	185.89	217.10
1.39	अंतर्राज्यीय परिशोधन						
2446.51	लोक ऋण प्राप्तिया*	2671.22	1299.43	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	1639.01
-	आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	-	-	आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-
7721.42	लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813.40	7399.85	लोक लेखा संवितरण			9727.77
640.91	आरंभिक रोकड़ शेष	(-)0.41	(-)0.41	अंतर्राज्यीय परिशोधन			75.40
				रोकड़ अंतशेष			116.85
29615.47	**कुल**	**35927.08**	**29615.47**	**कुल**	**13424.40**	**10943.66**	**35927.08**

स्रोतः वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर।

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन नीचे दिये गये हैं-

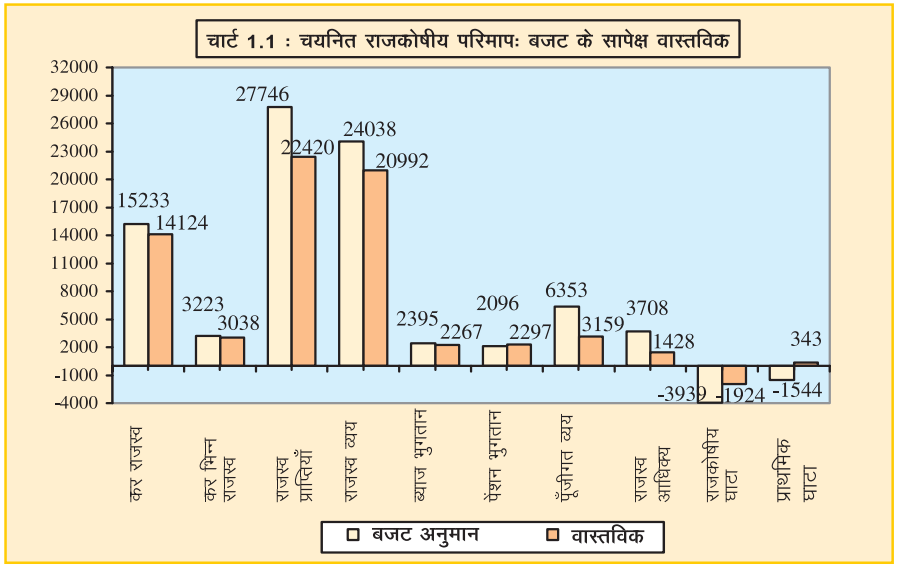
- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 3,639 करोड़ (19 *प्रतिशत*) बढ़ गयी। वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व में ₹ 1,237 करोड़ (22 *प्रतिशत*), गैर कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 235 करोड़ (8 *प्रतिशत*), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 1,016 करोड़ (17 *प्रतिशत*) और सहायता-अनुदानों में ₹ 1,151 करोड़ (28 *प्रतिशत*) की वृद्धि के फलस्वरूप थी। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 27,746 करोड़ के बजट अनुमान से कम रही।
- तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) द्वारा नियत किए गए कर-राजस्व (₹ 8,176 करोड़) एवं कर भिन्न राजस्व (₹ 3,594 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरूद्ध राज्य के वास्तविक कर एवं कर भिन्न प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 6,954 करोड़ (85 *प्रतिशत*) एवं ₹ 3,038 करोड़ (85 *प्रतिशत*) रही। इस प्रकार दोनों मोर्चे पर यह ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक प्रक्षेपण से कम थी।

- सामान्य सेवाओं (₹ 855 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 580 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1,613 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 3,047 करोड़ (17 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 24,038 करोड़ के बजट अनुमान से कम थी।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में ग्रामीण विकास, सिंचाई व जल आपूर्ति मद में अधिक खर्च होने के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 495 करोड़ (19 *प्रतिशत*) की बढ़ोत्तरी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम की वसूली लगभग समान रही जबकि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2011-12 के दौरान संवितरण ₹ 91 करोड़ (30 *प्रतिशत*) कम रही।
- पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 224 करोड़ (9 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 340 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3,092 करोड़ (40 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई तथा संवितरण में ₹ 2,328 करोड़ (31 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- इन लेन-देनों का निवल प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा 2011-12 के अन्त में रोकड़ शेष में ₹ 117.26 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.1 बजट आकलन के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष के लिये राजस्व एवं व्यय के अनुमान या प्रयोजना की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिये राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों के विचलन के कई कारण हो सकते है। यह बजट निर्माण के समय अधिक/कम अनुमान या अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं के कारण ऐसा हो सकता है।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंडों के संबंध में बजटीय एवं वास्तविक आंकड़ों को तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि पेंशन भुगतान को छोड़कर, वास्तविक प्राप्तियाँ व खर्चे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के निमित्त बजट अनुमान से कम थे। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 5,326 करोड़) मुख्यतया राज्य बजट में अनुमानित राशि के विरूद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्ति में कमी (₹ 4,032 करोड़) के कारण हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 3,046 करोड़) में कमी सामाजिक सेवाओं (₹ 2,237 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 787 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में कमी के कारण हुई।

राज्य के पूंजीगत व्यय में कमी राज्य के बजट अनुमान के विरूद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 1,156 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,014 करोड़) पर कम व्यय के कारण हुई, जो राज्य के लिए चिंता की विषय थी।

1.2.2 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार ने सरकार के राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया (***परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी.***)। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* तक सीमित करना था। यद्यपि, तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) ने राजकोषीय समेकन को सभी अनुदानों एवं ऋण राहत की सुविधा से जोड़ते हुए सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित संसुद्धि पथ अनुसंशित किया है।

तदनुसार, राज्य ने इसके एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्य कालीन राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2011 एवं 2012 में उपस्थापित संशोधित लक्ष्य (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन *प्रतिशत*

करना और (iii) 2011-12 में ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 28.5 *प्रतिशत* करना था। लक्ष्यों को एम.टी.एफ.पी.में पुनः संशोधित किया गया जो निम्न रूप में दिया गया है-

तालिका 1.2: राजकोषीय लक्ष्य बनाम एम.टी.एफ.पी. मे उपलब्धि

(प्रतिशत में)

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	वास्तविक 2010-11	लक्ष्य 2011-12	वास्तविक 2011-12	लक्ष्य 2012-13	लक्ष्य 2013-14
स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 0.61	(+) 2.69	(+)1.15	(+) 3.32	(-) 1.00
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (-) /आधिक्य (+)	(-)1.70	(-) 2.80	(-)1.54	(-) 2.15	(-) 2.50
स.रा.घ.उ. से प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (+)	(+)0.09	(-) 1.07	(+) 0.3	(-) 0.24	(-) 0.50
ऋण/स.रा.घ.उ.	23.35	25.00	24.70	25.00	25.00

- राज्य ने राजस्व घाटा को 2006-07 में बड़े राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो पुनः अंर्तवर्षीय परिवर्तन के साथ 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ तक बढ़ गया। यद्यपि, 2011-12 में एम.टी.एफ.पी. में राजस्व आधिक्य का स.रा.घ.उ. से लक्षित अनुपात (2.69 *प्रतिशत*) प्राप्त नहीं किया जा सका।
- एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा का *प्रतिशत* 2010-11 (1.90 *प्रतिशत*) तथा 2011-12 (1.54 *प्रतिशत*) के निर्धारित लक्ष्य के काफी अन्दर था। यह *प्रतिशत* एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित सीमा (2.80 *प्रतिशत*) के काफी अन्दर था।
- 2011-12 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 24.70 *प्रतिशत* था जो ते.वि.आ. (28.5 *प्रतिशत*) तथा एम.टी.एफ.पी. (25 *प्रतिशत*) के अनुमान के अन्दर था।

1.3 राज्य के संसाधन

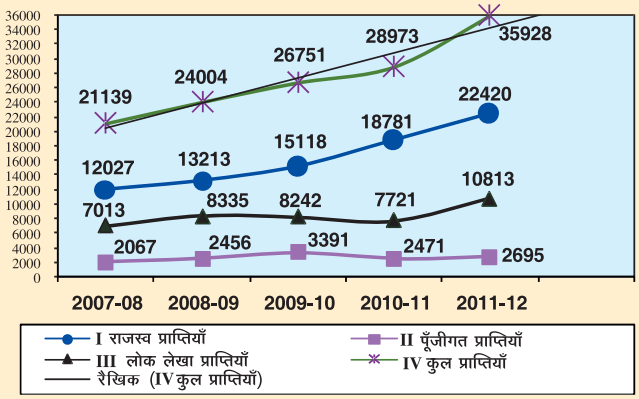
1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन के लिए प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं, राजस्व और पूँजीगत। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है।

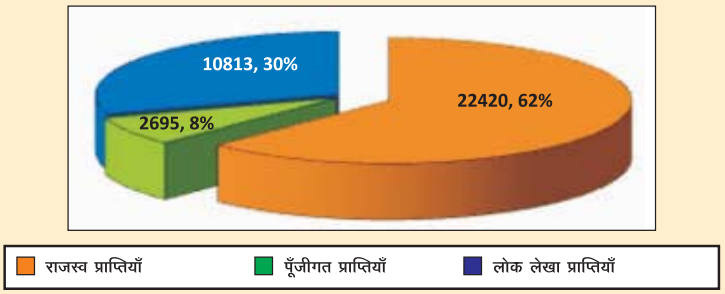
तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखे में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2,** 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृति (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.3: 2011-12 के दौरान राजस्व का संयोजन
(₹ करोड़ में)



- राज्य की कुल प्राप्तियाँ 2007-08 में ₹ 21,139 करोड़ से 2011-12 में ₹ 35,928 करोड़ तक बढ़ी। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर 2010-11 में आठ *प्रतिशत* से 2011-12 में 24 *प्रतिशत* था, जो मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,639 करोड़ (19 *प्रतिशत*) तथा लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3,092 करोड़ (40 *प्रतिशत*) की वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2007-12 में 55 *प्रतिशत* से 65 *प्रतिशत* तक दोलित रहा। कुल प्राप्तियों में तुलनात्मक अधिक वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों का *प्रतिशत* 2010-11 में 65 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 62 *प्रतिशत* हो गया।

- ऋण पूँजीगत प्राप्तियों (पूँजीगत प्राप्तियों घटाव कर्ज एवं अग्रिम की वसूली) 2010-11 में ₹ 2,447 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,671 करोड़ हो गया। इसकी वृद्धि दर 2010-11 में (-)27 *प्रतिशत* की तुलना में 2011-12 में नौ *प्रतिशत* थी।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ 2010-11 में ₹ 7,721 करोड़ (27 *प्रतिशत* कुल प्राप्तियों का) से प्रमुखता से बढ़कर 2011-12 में ₹ 10,813 करोड़ (30 *प्रतिशत* कुल प्राप्तियों का) हो गया।

1.3.2 राज्य की विशेष जरूरतों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान

झारखण्ड राज्य के लिए ते.वि.आ. द्वारा राज्य की विशेष जरूरतों के अधीन अनुशंसित अनुदान का आवंटन एवं विमोचन **तालिका 1.3** दिया गया है।

तालिका 1.3: 2011-12 के लिए राज्य की विशेष जरूरतों के अधीन अनुदान

(₹ करोड़ में)

विभाग/योजना	प्रावधान	विमुक्त
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास-10,000 आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	108.00	108.00
कल्याण-आदिवासी एवं व्यावसायिक सोसाइटियों के लिए छात्रावास	31.25	30.87
गृह-पुलिस प्रशिक्षण	18.25	15.86
गृह-आवास	56.25	56.25
कला,संस्कृति, खेल एवं युवा मामले/विरासत गैलेरी	25.00	22.00
श्रम एवं रोजगार-10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण	50.00	50.00
ग्रामीण विकास-प्रखंड स्तर पर भवनों का निर्माण	67.50	67.50
कुल	**356.25**	**350.48**

स्रोतः- वित्त विभाग

राज्य को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 356.25 करोड़ की राशि की अनुशंसा के विरूद्ध विभिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए ₹ 350.48 करोड़ प्राप्त हुए। कम राशि की विमुक्ति कल्याण (₹ 0.38 करोड़), पुलिस प्रशिक्षण (₹ 2.39 करोड़) तथा कला एवं संस्कृति (₹ तीन करोड़) के अंतर्गत हुआ।

2011-12 के विस्तृत विनियोग लेखे द्वारा पाया गया कि ते.वि.आ. द्वारा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग (₹ 108 करोड़) तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले (₹ 25 करोड़) की आवंटित राशि, जो राज्य बजट द्वारा प्रदान किये गये थे, प्रयोग नहीं किए जा सके और सम्पूर्ण राशि विभागों द्वारा प्रत्यर्पित कर दी गई।

1.3.3 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[1] को केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में निधि सीधे हस्तांतरित की गई । चूँकि यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है, वार्षिक वित्त लेखे इस निधि के प्रवाह को समाहित नहीं करता है और उस सीमा तक उनसे उत्पन्न राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चल/प्राचल न्यून प्राक्कलित है। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किये गये हैं।

[1] राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वैसे संगठन/संस्थान, गैर-सरकारी संगठन सहित, जो भारत सरकार से निधि प्राप्त करते हैं, राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में सम्मिलित है। जैसे एस.एस.ए. के लिए राज्य कार्यान्वयन संख्याएन.आर.एच.एम. के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना (केन्द्र: राज्य हिस्से को इंगित)	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	2010-11	2011-12
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	962.87	917.77
इंदिरा आवास योजना	झारखण्ड ग्रामीण विकास अभिकरण	561.65	215.48
स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन), समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	143.44	84.67
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	895.62	579.03
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार के लिए मानव संसाधन	झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन नियंत्रण संस्था	300.07	609.65
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	184.62	220.82
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	40.00	69.00
गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ	1122.81	1498.00
कुल		**4211.08**	**4194.42**

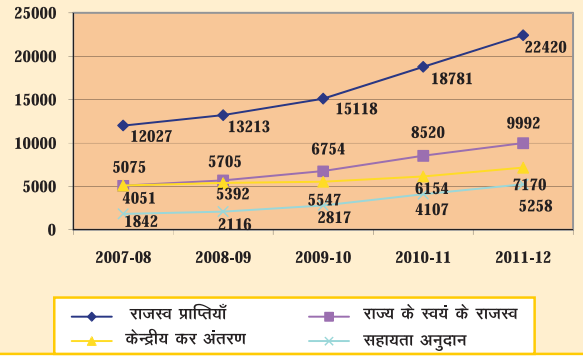
सूचनाएँ कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समाशोधित नहीं की गई।
(निधियों के सीधे हस्तांतरण की कुल राशि वर्ष 2011-12 एवं 2010-11 में झारखण्ड राज्य के क्षेत्र से बाहर से संगठनों को विमुक्त क्रमशः ₹ 146.05 करोड़ एवं ₹ 118.40 करोड़ सम्मिलित नहीं।)

संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधि के कारण इन निधियों के अनुचित उपयोग का जोखिम रहता है। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा कोई समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता इन सीधे हस्तांतरित निधि के खर्च का राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड द्वारा अद्यतन सूचना को विधिमान्य नहीं बनाया जाता तब तक इसके पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

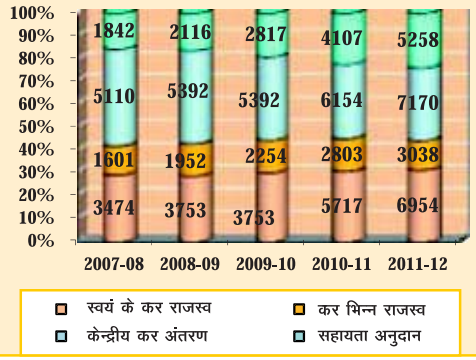
1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर और कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। वित्त लेखे की **विवरणी -11** सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। 2007-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को ***परिशिष्ट 1.3*** में दिखाया गया है एवं क्रमशः **चार्ट 1.4** और **चार्ट 1.5** में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.5: 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन (₹ करोड़ में)



- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2007-08 में ₹ 12,027 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 22,420 करोड़, 17.2 *प्रतिशत* की औसत विकास दर से बढ़ी। 2011-12 के दौरान प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के तुलना 19.4 *प्रतिशत* से बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2011-12 के दौरान ₹ 5,326 करोड़ से कम रही। औसतन, जहाँ 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का करीब 45 *प्रतिशत* राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ, वही इस अवधि के दौरान कुल राजस्व का 55 *प्रतिशत* सम्मिलित रूप से केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ।

- वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (₹ 22,420 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 6,954 करोड़ (31 *प्रतिशत*), कर भिन्न राजस्व ₹ 3,038 करोड़ (14 *प्रतिशत*), केन्द्रीय कर हस्तांतरण ₹ 7170 करोड़ (32 *प्रतिशत*) और सहायता अनुदान ₹ 5,258 करोड़ (23 *प्रतिशत*) थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इन शीर्षों में वृद्धि क्रमशः 21 *प्रतिशत*, आठ *प्रतिशत*, 17 *प्रतिशत* और 28 *प्रतिशत* रही।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ **तालिका 1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) ₹ करोड़ में	12027	13213	15118	18781	22420
आर.आर. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	20.1	9.9	14.4	24.2	19.4
आर.आर./ स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	14.3	15.1	15.6	17.0	18.1
राज्य के स्वयं कर/ स.रा.घ.उ.	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6
स.रा.घ.उ.की वृद्धि दर	25.42	4.58	10.41	14.27	12.09
उत्प्लावकता अनुपात[2]					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.79	2.15	1.38	1.69	1.60
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	0.35	1.74	1.91	1.89	1.79

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2008-09 में 9.9 *प्रतिशत* से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2010-11 में 24.2 *प्रतिशत* हो गई। तथापि, यह 2011-12 के दौरान घटकर 19.4 *प्रतिशत* तक पहुँच गई।

- स.रा.घ.उ.के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता 2007-12 के दौरान 0.79 तथा 2.15 के बीच रही। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (9.9 *प्रतिशत*) की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (4.6 *प्रतिशत*) निम्न स्तर पर रहने के कारण यह 2008-09 में उच्चतम स्तर पर था। जबकि 2007-08 में यह स.रा.घ.उ. के उच्चतम वृद्धि दर (24.2 *प्रतिशत*) के कारण निम्नतम स्तर (0.79 *प्रतिशत*) पर रहा। 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि में स.रा.घ.उ. की तुलना में तेजी से कमी हुई जिसके कारण राजस्व उत्पलावकता 2010-11 में 1.69 से गिर कर 2011-12 में 1.60 हो गई।

- स.रा.घ.उ. एवं स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर में व्यापक विचलन के कारण राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता 2007-12 के दौरान 0.35 और 1.91 के बीच रही। उत्प्लावकता 2009-10 में 1.91 से 2010-11 में 1.89 की उत्तरोत्तर कमी हुई। पुनः 2011-12 में उत्प्लावकता 1.79 तक घटी, जबकि राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि में स.रा.घ.उ. की अपेक्षा उच्चतर दर से कमी हुई।

- 2007-08 से 2011-12 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 4.6 *प्रतिशत* से 25.4 *प्रतिशत* तक वृहत् अन्तर दर्ज किया गया जबकि वृद्धि दर 2010-11 में 14.3 *प्रतिशत* तक बढ़ी जो 2011-12 में, ते.वि.आ. के मानक 14.14 *प्रतिशत* के विरूद्ध, घटकर 12.1 *प्रतिशत* हो गई जिसका मुख्य कारण उत्पादन एवं उद्योग प्रक्षेत्र के वृद्धि में कमी थी।

[2] आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे - राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 *प्रतिशत* तक बढ़ेगा।

1.4.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

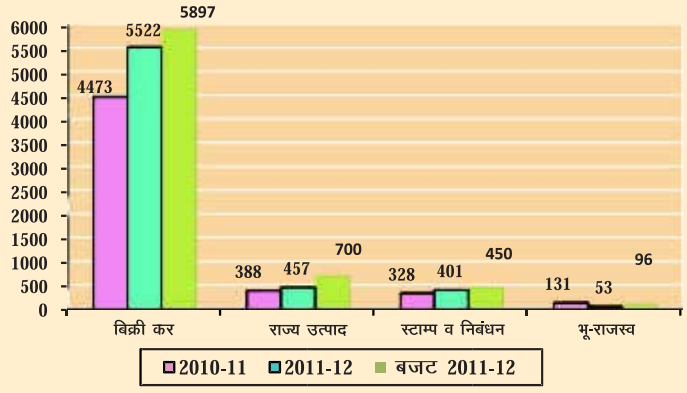
चूँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कर प्राप्ति के संग्रहण और योजनागत कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता इत्यादि के द्वारा केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन जिसमें राजस्व के रूप में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू-राजस्व आदि तथा कर भिन्न राजस्व के रूप में स्वयं के संसाधन के वृद्धि के द्वारा किया जाना चाहिए ।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2007-08 में ₹ 3,474 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 6,954 करोड़ हो गया । 2007-08 एवं 2008-09 में आठ *प्रतिशत* से 2010-11 में 27 *प्रतिशत* तक बढ़ा जो 2011-12 में आंशिक रूप से घटकर 21 *प्रतिशत* हो गया। 2011-12 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर की भागीदारी 79 *प्रतिशत* थी। इसके बाद राज्य उत्पाद (सात *प्रतिशत*), स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन (छः *प्रतिशत*) की भागीदारी रही।

पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कर राजस्व के मुख्य घटक को **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.6: कर राजस्व में वृद्धि के मुख्य घटक (₹ करोड़ में)



2011-12 के दौरान, ते.वि.आ. के सामान्य अनुमान ₹ 8,176 करोड़ के विरूद्ध राज्य का स्वयं का कर ₹ 6,954 करोड़ रहा। ते.वि.आ. तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का कारण बिक्री कर एवं राज्य उत्पाद के अनुमान से कम संग्रहण होना था। इन शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित संग्रहण क्रमशः ₹ 5,897 करोड़ तथा ₹ 700 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5,522 करोड़ तथा ₹ 457 करोड़ का वास्तविक संग्रहण हुआ। 2011-12 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.6 *प्रतिशत*) था। जो एम.टी.एफ.पी. के 5.4 *प्रतिशत* के लक्ष्य से अधिक था जबकि यह ते.वि.आ. के 6.38 *प्रतिशत* के अनुमान से काफी कम था।

कर भिन्न राजस्व

वर्ष 2011-12 के दौरान ते.वि.आ. के मानक ₹ 3594 करोड़ के विरूद्ध कुल कर भिन्न राजस्व का संग्रहण ₹ 3038 करोड़ था।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कर भिन्न राजस्व राजस्व प्राप्तियों का 13 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* था। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों में इसका *प्रतिशत* 2010-11 में 15 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 14 *प्रतिशत* हो गया। कर भिन्न राजस्व का वृद्धि दर 2010-11 में 24 *प्रतिशत* से मुख्य रूप से घटकर 2011-12 में आठ *प्रतिशत* हो गया। जो मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं अन्य सामाजिक सेवाओं, पर्यटन एवं उद्योगों में कम संग्रहण के कारण हुआ, यद्यपि अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों में 2011-12 में वृद्धि हुई।

1.4.1.1 कर के संग्रह की लागत

2011-12 के दौरान मुख्य करों तथा व्यय से होने वाले कर संग्रह के कुल संग्रह तथा उनके संगत अखिल भारतीय औसत **तालिका 1.6** में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.6: कर के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे शीर्ष	2011-12 के दौरान सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय की *प्रतिशतता*	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
1	बिक्री,व्यापार आदि पर कर	5522	50.20	0.91	0.75
2	राज्य उत्पाद	457	15.95	3.49	3.05
3	मोटरयान कर	392	4.60	1.17	3.71
4	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	401	11.34	2.83	1.60

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

2011-12 के दौरान बिक्री कर, राज्य के उत्पाद एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक था। राज्य सरकार को उक्त विभागों के कर संग्रह की दक्षता को बेहतर बनाना चाहिए तथापि, मोटर यान कर के संग्रह की लागत भी अखिल भारतीय औसत से काफी कम था।

1.4.2 केंद्रीय कर हस्तांतरण

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 7,170 करोड़) में ₹ 1,016 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 *प्रतिशत* थी। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 617 करोड़) निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 162 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 167 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 242 करोड़) के अंतर्गत हुई थी।

1.4.3 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

भारत सरकार द्वारा गैर-योजनागत, राज्य योजना, केन्द्रीय पोषित प्रायोजित तथा केंद्र योजना स्कीमों पर विमुक्ति सहायता अनुदानों की प्रवृत्ति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:-

तालिका 1.7: भारत सरकार द्वारा विमोचित अनुदान-विषयवार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-योजना	राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजना स्कीम	कुल	*प्रतिशतता वृद्धि*
2007-08	556.49	752.18	533.10	1841.77	21
2008-09	591.91	1054.18	469.79	2115.88	15
2009-10	1145.33	982.97	688.33	2816.63	33
2010-11	1281.40	1826.99	998.86	4107.25	46
2011-12	1550.77	2404.61	1302.03	5257.41	28

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- 2011-12 के दौरान, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान 2010-11 के ₹ 4,107.25 करोड़ के अनुदान से 28 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,257.41 करोड़ थी।

- चालू वर्ष में गैर-योजना अनुदान, राज्य योजना अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीम हेतु अनुदानों में क्रमशः

  ₹ 269.36 करोड़ (21 *प्रतिशत*), ₹ 577.62 करोड़ (32 *प्रतिशत*) और ₹ 303.17 करोड़ (30 *प्रतिशत*) से वृद्धि हुई ।

- गैर-योजना अनुदानों में वृद्धि का कारण मूलतः ते.वि.आ.(₹ 611.51 करोड़) के अनुशंसा पर अनुदानों में वृद्धि तथा राज्य को केन्द्रीय बिक्री कर (₹ 243 करोड़) के कम करने के कारण हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति थी।

- राज्य योजना अनुदान में वृद्धि मुख्यतया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (₹ 184 करोड़) के अंतर्गत हुआ। केन्द्रीय योजना स्कीम के अधीन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए अनुदानों में ₹ 199 करोड़ तक की वृद्धि हुई ।

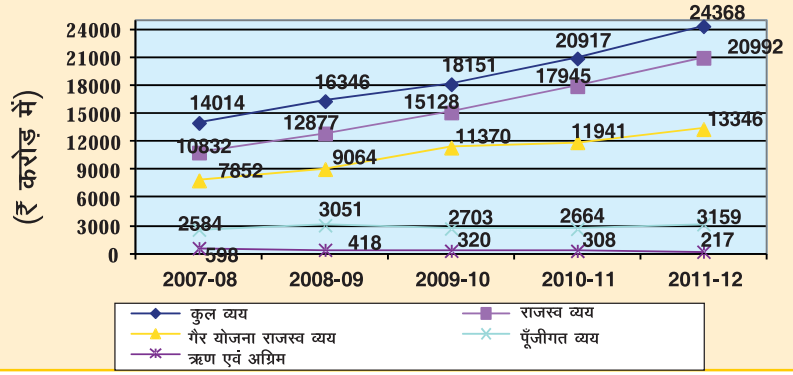
1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन पर मुख्य व्यय करने का उत्तरदायित्व है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बहाने में बजटीय बाध्यता थी। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय शुद्धि और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया उधार द्वारा सम्पोषित लोक व्यय की बढ़ी हुई प्रकृति को बिना नकारते हुए विकास एवं सामाजिक व्ययों को ध्यान में रखा जाय ।

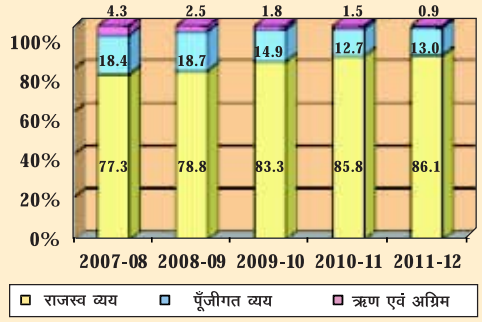
1.5.1 कुल व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 2007-08 से 2011-12 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। इसके संघटक "आर्थिक वर्गीकरण" और "क्रियाकलापों द्वारा व्यय" दोनों के संदर्भ में क्रमशः **चार्ट 1.8 और 1.9** में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय : प्रवृति एवं संघटन



चार्ट 1.8: कुल व्यय : घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृति (*प्रतिशत* में हिस्सेदारी)



- पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल व्यय 15 *प्रतिशत* के औसत वृद्धि दर से बढा। 2011-12 के दौरान वृद्धि दर 16 *प्रतिशत* थी।
- कुल व्यय में से राजस्व व्यय 86 *प्रतिशत* था जबकि पूँजीगत व्यय 13 *प्रतिशत* था। संवितरित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का केवल एक *प्रतिशत* था।
- वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय की प्रवृत्ति दर्शाता है कि गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय 2010-11 में क्रमशः 58 और 48 *प्रतिशत* की अपेक्षा 2011-12 में 55 और 45 *प्रतिशत* थी। कुल व्यय में ₹ 3,451 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से योजना व्यय में (₹ 2,147 करोड़) वृद्धि था।

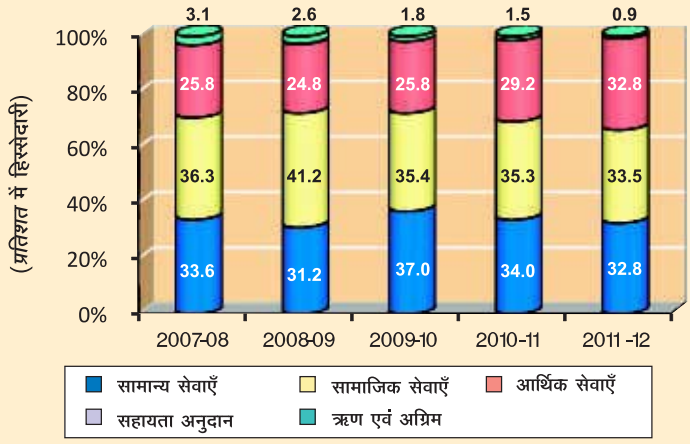
1.5.2 कार्य कलापों के संदर्भ में कुल व्यय

कार्यकलापों के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), समाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदानों एवं ऋण व अग्रिम पर समग्र व्यय है।

कार्यकलापों द्वारा व्यय (**चार्ट 1.9**) का विश्लेषण दर्शाता है कि गैर-विकासात्मक रूप में समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं पर व्यय, 2011-12 के दौरान 32.8 *प्रतिशत* रही जो 2008-09 (31.2 *प्रतिशत*) को छोड़कर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम थी। दूसरी ओर 2009-10 में 61.1 *प्रतिशत* तथा 2010-11 में 64.5 *प्रतिशत* के विरूद्ध 2011-12 के

दौरान विकासात्मक व्यय अर्थात सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय सम्मिलित रूप से 66.2 *प्रतिशत* रही।

चार्ट 1.9: कुल व्यय: कार्यकलापों की प्रवृति



1.5.3 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय 18.7 *प्रतिशत* के औसत वृद्धि दर से 2007-08 में ₹ 10,832 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 20,992 करोड़ (94 *प्रतिशत*) हो गई। 2011-12 में इसमे पिछले वर्ष की तुलना में 17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

- 2011-12 के दौरान, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर 2010-11 में क्रमशः 20 *प्रतिशत* तथा 46 *प्रतिशत* की तुलना में घटकर क्रमशः नौ *प्रतिशत* तथा 38 *प्रतिशत* हो गई जो विकासात्मक/उत्पादक सेवाओं पर कम व्यय का संकेतक था।

- स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व की उत्पलावकता एवं राजस्व प्राप्तियाँ 2010-11 के क्रमशः 1.30 तथा 0.77 के सापेक्ष बढ़कर 2011-12 में क्रमशः 1.40 तथा 0.88 हो गई। 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 12 *प्रतिशत* के विरूद्ध राजस्व व्यय की वृद्धि दर 17 *प्रतिशत* थी।

1.5.3.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) 2010-11 के कुल राजस्व व्यय के 33 *प्रतिशत* से बढ़कर 2011-12 में 36 *प्रतिशत* हो गया, जबकि पी.आर.ई. की वृद्धि दर में 2007-12 के दौरान (-)1.4 *प्रतिशत* और 61 *प्रतिशत* के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2011-12 के दौरान, अ.जा. व अ.ज.जा. कल्याण (₹ 174 करोड़) तथा परिवहन (₹ 507 करोड़) में मुख्य रूप से बढ़ोत्तरी के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष पी.आर.आई. ₹ 1,642 करोड़ (27 *प्रतिशत*) की वृद्धि के साथ ₹ 7,646 करोड़ हो गई।

1.5.3.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

2011-12 के दौरान एम.टी.एफ.पी. के ₹ 13,724 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध एन.पी.आर.ई. ₹ 13,346 करोड़ थी। 2009-10 के 25.4 *प्रतिशत* की तुलना में एन.पी.आर.ई. की वृद्धि दर में 2010-11 में 5 *प्रतिशत* तक का भारी ह्रास हुआ। तथापि, 2011-12 में इसमें 12 *प्रतिशत* की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 2007-12 के दौरान कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. की *प्रतिशतता* 55 से 63 के बीच दोलित रही। 2011-12 के दौरान, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. 55 *प्रतिशत* थी तथा राजस्व व्यय का यह 64 *प्रतिशत* था।

1.5.4 पूँजीगत व्यय

2007-12 के दौरान, पूँजीगत व्यय (सी.ई.) 2007-08 में ₹ 2,584 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 3,159.37 करोड़ हो गई।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 126 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 256 करोड़) पर हुए अधिक व्यय के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 495.07 करोड़ (19 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 6,353 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था। 2007-12 के दौरान कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 13 से 19 *प्रतिशत* थी।

- 2010-11 के अवधि एवं 2011-12 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय की *प्रतिशतता* (13 *प्रतिशत*) एक समान रही। पूंजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का 2.54 *प्रतिशत* थी तथा यह *प्रतिशतता* 2011-12 के लिए एम.टी.एफ.पी. द्वारा अनुमानित प्रतिशतता (3.15 *प्रतिशत*) की तुलना में काफी कम था।

- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम की हिस्सेदारी एक *प्रतिशत* (2007-08) से 4 *प्रतिशत* (2011-12) तक लंबित था। 2011-12 के दौरान ऊर्जा के लिए आवंटित ऋण में (₹ 110 करोड़) की कमी के कारण, यह 2010-11 में ₹ 308 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गई। तथापि, चालू वर्ष में ऋण एवं अग्रिम ₹ 2,731.22 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में कम थी।

1.5.5 वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार का व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन और सब्सिडी से संघटित होता है जो प्रतिबद्ध या अनिवार्य प्रकृति के होते हैं, यद्यपि सरकार ने इन सभी व्यय को प्रतिबद्ध या अनिवार्य नहीं बताया।

तालिका 1.8 और **चार्ट 1.10** 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति दर्शाता है।

तालिका 1.8: वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान के अवयव

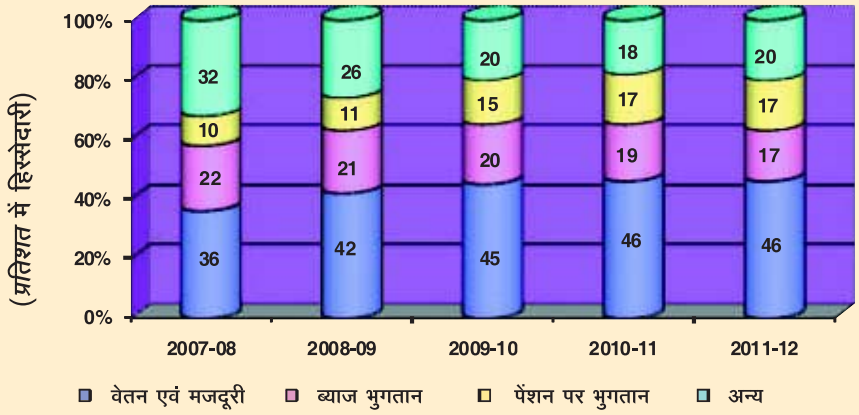
(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बी ई #	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	2985 (25)	3948 (30)	5342 (35)	5642(30)	7434	6352(28)
गैर-योजना शीर्ष	2802 (23)	3801 (29)	5154 (34)	5434(29)	7053	6150(27)
योजना शीर्ष	183 (2)	147 (1)	188 (1)	208(1)	381	202(1)
ब्याज भुगतान	1758 (15)	1887 (14)	2307(15)	2228(12)	2395	2267(10)
पेंशन पर व्यय	818 (7)	988 (7)	1681(11)	2081(11)	2096	2297(10)
सब्सिडी	77 (1)	37 (0.3)	41(0.3)	80	¥	286(2)
कुल	**5638 (47)**	**6860 (52)**	**9371 (62)**	**10031 (53)**	**11925**	**11202(50)**

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।
** इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।*
बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़ें हैं।
¥ बजट उपलब्ध नहीं ।

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

चार्ट 1.10: 2007-12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी



2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6,352 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,267 करोड़) और पेंशन (₹ 2,297 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय के 52 *प्रतिशत* लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 49 *प्रतिशत* था। 2011-12 के दौरान वेतन पेंशन और ब्याज भुगतान पर कुल व्यय एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 75 *प्रतिशत* के लक्ष्य के विरूद्ध एन.पी.आर.ई का 80 *प्रतिशत* थी।

वेतन एवं मजदूरी

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 28 से 35 *प्रतिशत* और राजस्व प्राप्तियों का 25 से 35 *प्रतिशत* था। राजस्व

व्यय और राजस्व प्राप्तियों में वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता 2010-11 में क्रमशः 31 *प्रतिशत* तथा 30 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 30 *प्रतिशत* तथा 28 *प्रतिशत* हो गई।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2011-12 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6,150 करोड़) ₹ 716 करोड़ (13 *प्रतिशत* से) बढ़ा। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक प्रक्षेपण (₹ 4,967) से ₹ 1,183 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- 2007-08 में पेंशन पर व्यय 36 *प्रतिशत* के औसत वृद्धि दर से ₹ 818 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,297 करोड़ हो गया। 2011-12 के दौरान वृद्धि पिछले वर्ष से केवल 10 *प्रतिशत* थी, जो ते.वि.आ. के मानक के बराबर थी। तथापि, 2011-12 के लिए पेंशन अदायगी की राशि उक्त वर्ष के लिए ते.वि.आ. के ₹ 1,291 करोड़ के मानक प्रक्षेपण से अधिक थी। यह 2011-12 के बजट अनुमान से भी ₹ 201 करोड़ (10 *प्रतिशत*) अधिक था।

- भविष्य में पेंशन तथा पेंशनरी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने एक जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। राज्य ने 20 मार्च 2009 को नई पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ एक करार किया तथा 2011-12 के दौरान मार्च 2010 से नवम्बर 2010 तक की अवधि का ₹ 148.20 करोड़, कर्मचारी अंशदान एवं सरकारी अंशदान के निमित्त (प्रत्येक ₹ 74.10 करोड़) और ₹ 0.74 करोड़ लीगेसी राशि पर ब्याज के निमित्त केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी.आ.ए.) को हस्तांरित किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ.के ₹ 2,687 करोड़ के मानक प्रक्षेपन के विरूद्ध 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,267 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान का वृद्धि दर दो *प्रतिशत* था। राजस्व प्राप्ति के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान 2009-10 के 15 *प्रतिशत* और 2010-11 के 12 *प्रतिशत* के विरूद्ध 2011-12 में 10 *प्रतिशत* ही था।
- 2010-11 तथा 2011-12 दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक **तालिका 1.9** में दिये गये हैं-

तालिका 1.9: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

के लिये ब्याज भुगतान	**2010-11**	**2011-12**
आंतरिक ऋण	1835.53	1941.20
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	215.15	165.81
राज्य भविष्य निधि	170.78	157.76
कुल	**2221.46**	**2264.77**

सब्सिडी

- 2011-12 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 286 करोड[3] के सब्सिडी का भुगतान शीर्ष 2401-फल उत्पादन (₹ 176.81 करोड़), 2425-कोपरेटिव (₹ 28.30 करोड़) और 2852-उद्योग (₹ 54.28 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी के निमित्त उप-शीर्ष के अधीन ही दर्ज किए गए थे। यह राशि 2010-11 के दौरान खर्च हुए राशि (₹ 80 करोड़) से काफी अधिक थी।
- 2011-12 के वित्त लेखे के *परिशिष्ट*-III के अनुसार खाद्य, ऊर्जा व सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी। झारखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (ई.एस.आर.) में 2011-12 के लिए ₹ 760 करोड़ के खाद्य सब्सिडी का अनुमान किया गया था। वित्त विभाग से लेखों में संबंधित खाद्य सब्सिडी पर वास्तविक व्यय तथा व्यय शीर्ष बताने का आग्रह किया गया था (अक्टूबर 2012)। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर, 2012)।

1.5.6 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2011-12 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.10** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.10: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पंचायती राज संस्थाएँ	-	-	875.69	581.06
शहरी स्थानीय निकाय	735.64	485.14	246.15	25.34
सार्वजनिक उपक्रम	200.70	602.64	491.55	777.00
स्वायत निकाय	923.83	678.31	607.55	677.85
गैर-सरकारी संस्थाऐं	7.60	17.87	192.43	209.68
अन्य	498.08	548.98	708.34	2259.30[4]
कुल	**2365.85**	**2332.94**	**3121.71**	**4530.23**

स्रोतः वित्त लेखे की विवरणी 8

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 2,365.85 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4,530.23 करोड़ तक स्थिरता से बढ़ा। उपरोक्त सहायता की वृद्धि दर 2009-10 में (-) एक *प्रतिशत* से बढ़कर 2010-11 में 34 *प्रतिशत* हो गई जो आगे 2011-12 में 45 *प्रतिशत* तक जा पहुँची।

[3] वित्त लेखे के परिशिष्ट-III

[4] राशि में सम्मिलि है (1) निजी स्कूलों के लिए मानव संसाधन विकास विभाग (₹ 255.81 करोड़), समेकित एवं असमेकित कार्य योजना के लिए जिला प्रशासन (₹ 581.15 करोड़) वृहत राँची विकास अभिकरण (₹ 149.46 करोड़), जनजाति विकास हेतु जनजाति कल्याण समिति (₹ 147.46 करोड़) और रेलवे परियोजनाएँ (₹ 486.70 करोड़)

- 2011-12 में वित्तीय सहायता में ₹ 1,551 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण अन्य संस्थाओं (नीचे दिये गये पाद टिप्पणी 4) को भुगतित नया वित्तीय सहायता (₹ 1,621 करोड़) था जिसका कुछ भाग पंचायती राज संस्थानों (295 करोड़) और शहरी स्थानीय निकायों (₹ 221 करोड़) को कम सहायता द्वारा प्रतितुलित था। इन संस्थानों को दी गई कुल सहायता राशि पिछले वर्ष के कुल राजस्व व्यय के 17 *प्रतिशत* के विरूद्ध 2011-12 में 22 *प्रतिशत* रही।

1.5.7 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली स्थानीय शहरी निकाय (यू. एल. बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदुनसार 18 कार्यों जैसे कि नगर-योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामें किये जाने थे। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने ***परिशिष्ट 1.5*** में इंगित सभी 18 कार्यों को समाविष्ट करते हुए फरवरी, 2012 में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 को अधिनियमित किया। अभी राज्य में 39 यू एल बी (नगर निगम-3, नगरपरिषद्-14, नगर पंचायत-19, नगरपालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.11 से प्रदर्शित होता है कि झारखण्ड सरकार ने 2008-12 के दौरान स्थानीय शहरी निकायों को कुल ₹ 1,492.72 करोड़ के अनुदानों का भुगतान किया। तथापि, 2008-12 के दौरान इसकी प्रवृति अनुदानों के निकास में कमी दर्शाती है। 2010-11 में ₹ 241.54 करोड़ के विरूद्ध 2011-12 के दौरान स्थानीय निकायों की सहायता मद में महत्वपूर्ण कमी पायी गई, जिसका मुख्य कारण मल व्यवस्था, जल निकास, जल आपूर्ति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निर्माण, नागरिक सुविधायें, इमारतों का निर्माण, भू-अधिग्रहण आदि सहायक मदों का अप्राप्त होना था। स्थानीय शहरी निकायों को निर्गत निधियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.11: स्थानीय निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्रा.)	13213	15118	18781	22420
2	राज्य की राजस्व व्यय (रा.व्यय)	12877	15128	17945	20992
3	स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	736	485	246	25
4	राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में वित्तीय सहायता	5.58	3.21	1.31	0.11
5	राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में वित्तीय सहायता	5.72	3.21	1.37	0.12
6	स्वयं के संग्रह[5]	-	-	3.23	18.84

[5] अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित किये गये निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों के लेखा परीक्षा के दौरान उद्भेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किये गये (2010-11: नगर पंचायतें-बासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगर पालिका परिषद् लोहरदगा तथा 2011-12 नगर पंचायतें- विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल नगर पालिका, जुगसलाई और राँची नगर पालिक निगम)।

जनवरी 2009 में अस्तित्व में आये दूसरे राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर, 2012 तक स्थानीय शहरी निकायों की निधियों को सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर, 2012)। उनका जबाव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर, 2012)।

झारखण्ड में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों के लेखापरीक्षा का कार्यभार भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी, पर्यवेक्षक-स्थानीय लेखे, को सौंपा गया है। ते.वि.आ. के निर्देशों के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने (मार्च, 2012 में) झारखण्ड स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित किया जिसके तहत् राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है और जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिया जाएगा। तथापि, सितम्बर, 2012 तक भी डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं होने के कारण स्थानीय शहरी निकायों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु भी नियम बनायें गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लधु शीर्षों 196-जिला परिषद् को अनुदान, 197-प्रखंड पंचायत को अनुदान और 198-ग्राम पंचायत को अनुदान के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमोचित निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4706 पंचायती राज संस्थायें[∂] हैं। **तालिका 1.12** के अनुसार, 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। 2010-12 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 1,456.75 करोड़ का भुगतान किया गया। पंचायती राज संस्थानों को दिये गए सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है :

[∂] 24 जिला परिषदों, 259 पंचायत समितियाँ और 4423 ग्राम पंचायतें

तालिका 1.12: पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420
2	राज्य की राजस्व व्यय (रा.व्यय)	12877	15128	17945	20992
3	पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	-	876	581
4	आर.आर.से वित्तीय सहायता की *प्रतिशतता*	-	-	4.66	2.59
5	आर.ई. से वित्तीय सहायता की *प्रतिशतता*	-	-	4.88	2.77
6	स्वयं संग्रह	-	-	**	**

** पी.आर.आई को चुनाव दिसम्बर 2010 में हुई थी।*

*** राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।*

जनवरी, 2009 में अस्तित्व में आये दूसरे राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर, 2012 तक पंचायती राज संस्थानों को निधियाँ सौंपने संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों (अनुदानों/कार्यक्रम निधियों के अलावे) के राजस्व स्रोतों की पहचान नहीं की है, क्योंकि पंचायती राज संस्थानों द्वारा करों का दर, पथ करों तथा शुल्कों आदि को निर्धारित व अधिसूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2012)।

ई.एफ.सी. की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने "झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012" अधिसूचित (मार्च 2011) किया तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखाकरन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (सितम्बर, 2012)।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं का विद्यमान होना व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय के उत्कर्ष में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू पर्याप्तता (अर्थात सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (लोक सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

1.6.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न होगी यदि यह अपने क्रम के सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से कम है।

तालिका 1.13 2008-09 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.13: 2008-09 और 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	एई/स.रा.घ.उ.	डी ई#/ए.इ	एस.एस.इ./ए. ई.	सी ई/ए. ई.	शिक्षा/ए ई	स्वास्थ्य/ए.ई.
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2008-09	18.62	68.54	41.67	18.67	19.40	4.79
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2011-12	19.63	67.09	33.51	12.96	16.65	4.06

ए ई: समुच्चयित व्यय, डी ई: विकास पर व्यय, एस एस ई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी ई: पूँजीगत व्यय

* स.रा.घ.उ. के अनुपात में

\# विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोतः स.रा.घ.उ. के लिए सूचनाएँ राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त की गई थी

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2008-09 एवं 2011-12 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग उपयोग किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के एक भाग के रूप में विकास व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में 2008-09 एवं 2011-12 में थोड़ा अधिक रहा क्योंकि झारखण्ड द्वारा इस मद में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में अधिक खर्च किया गया।

राज्य की पूंजीगत व्यय से सकल व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2008-09 में कुछ अधिक था, लेकिन वर्ष 2011-12 में यह थोड़ा कम हो गया, जैसा कि राज्य द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इस मद में कम खर्च किया गया। भौतिक पूंजीगत निर्माण में कमी की प्राथमिकता के कारण राज्य के संभावित विकास में कमी होगी।

वर्ष 2011-12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम प्राथमिकता दी गयी।

1.6.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय के लिए बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाये और कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स[6] के प्रावधान पर जोर दें। विकास व्यय[7] हेतु आबंटन के अलावा कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे

[6] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसेः-कानून और आदेश का प्रवर्त्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स वे सामग्री हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को मुफ्त या कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति या समाज के पास ये सामग्री आवश्यकता, योग्यता और सरकार को भुगतान करने की इच्छा के आधार पर होनी चाहिए और उनके उपयोग को बढ़ाने की इच्छुक हों, इन सामग्रियों के उदाहरण है, पोषण हेतु गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न का प्रावधान, जीवन स्तर सुधारने और मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, सभी को आधारभूत शिक्षा का प्रावधान, पेयजल और स्वच्छता इत्यादि।

[7] व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे की अपेक्षा सभी व्यय, आबंटन और ऋण एवं अग्रिम को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवायें और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किये गये हैं। व्यापक रूप में, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय सम्मिलित है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में है।

समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.14 पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय के साथ-साथ चालू वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के समुच्चयित व्यय के तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.14: विकास का व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास पर व्यय (अ से स)						
अ. विकास पर राजस्व व्यय	6224 (44)	7918 (48)	8523(47)	10954(52)	16171	13146(54)
ब. विकास पर पूंजीगत व्यय	2476 (18)	2875 (18)	2591(14)	2544(12)	6173	3003(12)
स. विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	586 (4)	411 (3)	308(2)	296(1)	1316	199(1)
कुल	**9286**	**11204**	**11422**	**13794**	**23660**	**16348**

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्यय + पू.व्यय + ऋण एवं अग्रिम) से *प्रतिशत* दर्शाते हैं।

* *बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।*

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक क्षेत्रों पर ऋणों एवं अग्रिम के साथ राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय सम्मिलित है। कुल विकास व्यय 2007-12 के दौरान 15 *प्रतिशत* औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2011-12 के दौरान 18.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।
- 2007-12 के दौरान, कुल व्यय का मुख्य हिस्सा विकासात्मक राजस्व व्यय का था और यह 44 *प्रतिशत* (2007-08) तथा 54 *प्रतिशत* (2011-12) के बीच था।
- कुल व्यय में विकासात्मक पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) का हिस्सा 2007-08 में 22 *प्रतिशत* से 2010-11 एवं 2011-12 में 13 *प्रतिशत* तक क्रमिक रूप से घटा। पुनः जैसा **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है, विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम बजट अनुमान 2011-12 से काफी कम थे।
- समाज कल्याण सेवाओं (₹ 8,165 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 8,183 करोड़) पर व्यय कुल विकासात्मक व्यय का 50 *प्रतिशत* था। 2007-12 के दौरान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय 98 *प्रतिशत* से बढ़ा जबकि समाज कल्याण सेवाओं के संदर्भ में वृद्धि 58 *प्रतिशत* थी।

चयनित समाज कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय

तालिका 1.15: चयनित समाज कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं पर हुए पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.15: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/ आर्थिक ढाँचा	2010-11			2011-12		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी.इ. का अनुपात	आर.ई. में, हिस्सा	
		एस.और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.08	52.36	00	0.45	54.43	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17.50	60.24	0.05	16.57	54.96	0.10
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	39.60	25.34	4.88	48.12	25.80	2.43
कुल (एस.एस.)	**8.46**	**51.00**	**0.45**	**10.75**	**40.91**	**0.29**
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	2.71	33.62	0.04	7.10	30.99	0.38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	50.38	96.97	00	58.59	98.23	0.00
विद्युत और ऊर्जा	00	00	1.12	16.10	0.00	0.00
परिवहन	82.79	38.61	43.56	49.08	10.72	11.41
कुल (ई.एस.)	**37.53**	**47.40**	**5.16**	**28.40**	**17.05**	**2.92**
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	**19.84**	**50.23**	**1.75**	**19.59**	**30.28**	**3.21**

टी.ई. : उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई. : पूँजीगत व्यय; आर.ई. : राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू : वेतन एवं मजदूरी;
ओ. और एम. : संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05-रखरखाव एवं मरम्मति के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता 2010-11 में 19.84 *प्रतिशत* से 2011-12 में 19.59 *प्रतिशत* तक घटी।
- समाज कल्याण सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक 2010-11 में क्रमशः 51 *प्रतिशत* एवं 47.40 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 40.91 *प्रतिशत* एवं 17.05 *प्रतिशत* हो गई।
- 2011-12 के दौरान, राज्य सरकार ने वृहत शीर्ष- "05 सार्वजनिक सम्पति के अनुरक्षण और मरम्मतें" के अधीन केवल ₹ 298.06 करोड़ खर्च किया।
- समाज कल्याण सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी जल आपूर्ति, मल-निकास, आवास और शहरी विकास पर हुए कम व्यय के कारण 2010-11 में 0.45 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 0.29 *प्रतिशत* हो गई।
- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी ऊर्जा एवं यातायात पर हुए राजस्व व्यय में कमी के कारण 2010-11 में 5.16 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 2.92 *प्रतिशत* तक हो गई।

1.7 सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. के परावर्ती ढाँचे में, राज्य न सिर्फ अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) नीचे स्तर पर रखने के लिए आशान्वित है बल्कि अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित) की जरूरत को पूरा करने के प्रति भी आशान्वित है। इसके अलावे, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की संक्रांति में, राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की

आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड निवेश के व्यापक वित्तीय विश्लेषण और पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अन्य पूँजीगत व्यय को प्रस्तुत करता है।

1.7.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य के सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम वित्त लेखे के *परिशिष्ट*-IX (i) में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्त लेखे-2011-12 के *परिशिष्ट* के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.7.2 अपूर्ण परियोजनायें

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि के रूकने से व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मार्च, 2012 तक 182 प्रमुख कार्य, प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक के अपूर्ण थे। इन परियोजनाओं में कुल ₹ 572.67 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी। 31 मार्च, 2012 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी **तालिका 1.16** में दी गई है।

तालिका 1.16: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं* की सं.	आरंभिक बजट लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	लागत वृद्धि	31.3.2012 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	104	451.29	103.84	-	149.53
पेयजल एवं स्वच्छता	7	54.65	6.95	-	40.02
जल संसाधन	13	267.25	6.79	-	160.42
भवन निर्माण	58	339.81	79.84	-	222.70
कुल	**182**	**1113.00**	**197.42**	**--**	**572.67**

* *एक करोड़ रूपये से अधिक की योजनाएँ*

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

- अपूर्ण कार्यों/परियोजनाओं की संख्या मार्च, 2011 के 167 की तुलना में 2011-12 के दौरान 182 थी। यह वृद्धि सड़क निर्माण विभाग (41 परियोजनायें) और भवन निर्माण विभाग (52 परियोजनायें) के अधीन हुई जो जल संसाधन विभाग (76 परियोजनाओं) के अधीन कमी द्वारा प्रतितुलित थी।
- **तालिका 1.16** में दिये गए अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने की लक्षित तिथि अक्टूबर 2005 से नवम्बर 2012 के बीच थी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। ₹ 1,113 करोड़ के अनुमानित राशि (मूल) के विचार से 2011-12 के दौरान व्यय हुई राशि (₹ 197.42 करोड़) काफी कम थी।

1.7.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में नये राज्य बनने के बाद से 31 मार्च, 2012 तक सरकार द्वारा नौ सरकारी कम्पनियों[8] (₹ 29.05 करोड़) और 20 सहकारी संस्थाओं, निगमों, बैंक एवं

[8] सरकारी कम्पनियों के संबंध में किये गये निवशों, संग्रहित लाभ/हानि इत्यादि का विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (लोक उपक्रम) वर्ष 2011-12 में दर्शाया गया है।

समितियों (₹ 153.52 करोड़) में कुल ₹ 182.57 करोड़ निवेश किये गये थे (**तालिका 1.17**) 2010-11 में ₹ 40 लाख (0.3 *प्रतिशत*) और 2011-12 में ₹ 1.17 करोड़ (0.64 *प्रतिशत*) लाभांश प्राप्त हुआ। तथापि सरकार ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 7.42 *प्रतिशत* से 8.03 *प्रतिशत* तक के औसत दर से ब्याज भुगतान किया, इसके निवेशों पर प्राप्त लाभांश नगण्य था।

तालिका 1.17: निवेशों पर लाभांश

(₹ करोड़ में)

निवेश/लाभ/उधार की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	98.96	112.47	128.73	135.18	182.57
लाभांश (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य	शून्य	0.40	1.17
लाभांश (*प्रतिशत* में)	शून्य	शून्य	शून्य	0.30	0.64
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर	7.97	7.42	8.03	7.98	7.64
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (*प्रतिशत*)	7.97	7.42	8.03	7.68	7.00

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे – विवरणी 14

2011-12 के दौरान 47.39 (26 *प्रतिशत*) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (₹ 14.70 करोड़), सरकारी कम्पनियाँ (₹ 6.25 करोड़) और समेकित सहकारी विकास परियोजना (₹ 26.44 करोड़) में किया गया । तथापि, 2007-08 के अंत में निवेश पर लाभांश (0.64 *प्रतिशत*) ते.वि.आ. के 5 *प्रतिशत* के मानक प्रक्षेपण से काफी कम था।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थानों के साथ ही सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में निवेश बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं की गई।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ सरकार ऐसे कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान कर दी गई है। **तालिका 1.18** 31 मार्च 2011 तक बकाये ऋण एवं अग्रिम और पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्राप्ति को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.18 राज्य सरकार द्वारा अग्रिम की गई ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

अग्रिम/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागतों की प्रमात्रा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋणों का आरंभिक शेष *(₹ करोड़ में)*	5462	6016	6415	6713	6997
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि *(₹ करोड़ में)*	598	418	320	308	217
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि *(₹ करोड़ में)*	44	19	22	24	24
बकाया ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान का *प्रतिशत*	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3
अंतशेष	**6016**	**6415**	**6713**	**6997**	**7190**
निवल योग *(₹ करोड़ में)*	553	399	298	284	193
ब्याज प्राप्तियाँ *(₹ करोड़ में)*	87	110	153	99	44
बकाये ऋणों एवं अग्रिमों के *प्रतिशत* में ब्याज प्राप्तियाँ	1.52	1.77	2.33	1.44	0.62
राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व के *प्रतिशत* में ब्याज भुगतान	8.57	8.26	9.00	7.98	7.64
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति का अंतर (*प्रतिशत*)	(-)7.05	(-) 6.5	(-)6.67	(-)6.54	(-)7.02

स्रोतःझारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम की गई ऋणों की प्रमात्रा 2007-08 में ₹ 598 *करोड़* से घट कर 2010-11 में ₹ 308 करोड़ एवं 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गई। 2011-12 के दौरान यह कमी मुख्यतः शक्ति परियोजनाओं (₹ 110.48 करोड़) में दी गई ऋण एवं अग्रिम में कमी के कारण थी।
- शेष ऋण एवं अग्रिम, 2011-12 के दौरान, पिछले वर्ष के सापेक्ष 3 *प्रतिशत* बढ़ा। मार्च 2012 के अन्त तक मुख्य बकाया राशियाँ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 6,584 करोड़) और नगर स्थानीय निकाय (₹ 526 करोड़) के विरूद्ध थी।

- 2011-12 के दौरान ₹ 44 करोड़ के कुल ब्याज प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा ब्याज आय (₹ 42.04 करोड़) के रूप में था जो सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध नकद शेष (₹ 2.12 करोड़) व अन्य प्राप्तियों के रूप में एकत्रित था।
- ₹ 1,035.74 करोड़ के ऋण व अग्रिम (मूल ₹ 310.24 करोड़) एवं ब्याज (₹ 725.50 करोड़) की वसूली 31 मार्च 2012 तक शेष थी।

1.7.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष और राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों का विवरण **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

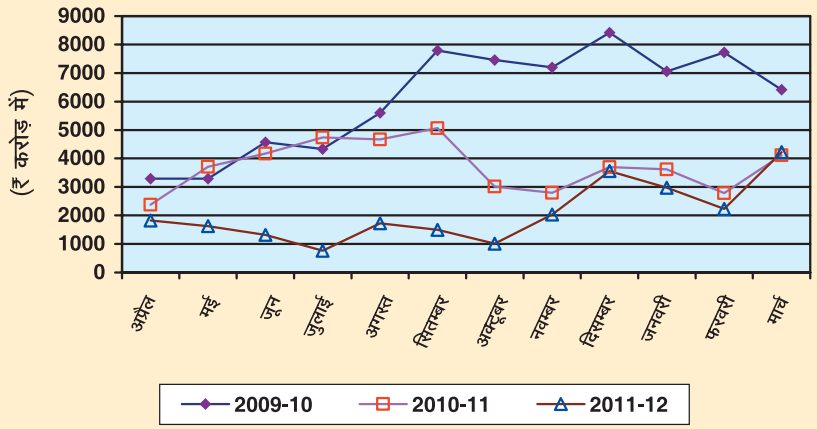
विवरण	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि/ कमी
रोकड़ शेष	(-)0.41	116.85	117.26 (वृद्धि)
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	879.19	4.41	874.78(कमी)
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	874.78	शून्य	874.78(कमी)
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41	शून्य
प्राप्त ब्याज	85.70	42.02	43.68(कमी)

स्रोतःझारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 0.41 करोड़ के विरूद्ध 31 मार्च 2012 को राज्य का रोकड़ शेष ₹ 116.85 करोड़ था।

मार्च, 2011 के अन्त तक ₹ 879.19 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के विरूद्ध मार्च 2012 के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष निवेश ₹ 4.41 करोड़ था। महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2012 तक का लेखा-जोखा करने पर ₹ 93.85 करोड़ का रोकड़ शेष (डेबिट) आर.बी.आई. के पास उपलब्ध था। तथापि, आर.बी.आई. द्वारा सूचित रोकड़ शेष 31 मार्च 2012 को ₹ 120.58 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2012 को ₹ 214.43 करोड़ का अन्तर समायोजन के प्रक्रियाधीन था। 30 सितम्बर 2012 तक, असमायोजित शेष ₹ 1.61 करोड़ था।

चार्ट 1.11: मासिक नगद शेष की प्रवृति



झारखण्ड सरकार को हर वक्त ₹ 0.45 करोड़ का न्यनतम शेष आर.बी.आई. में संचित रखना है। यदि किसी भी दिन शेष उक्त सीमा से कम होती है तो यह कमी विशेष या साधारण अर्थोपाय अग्रिम या आर.बी.आई. से ओवरड्राफ्ट द्वारा प्रतिपूरित की जाती है। जैसा **चार्ट 1.11** में दर्शाया गया है कि दैनिक रोकड़ शेष ठीक से संभाला गया और केवल सामान्य बैंकिंग लेन-देनों के लिए आवश्यक शेष ही रखे गये। 2011-12 के दौरान, राज्य को आर.बी.आई. में न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए 5 दिन विशेष अर्थोपाय अग्रिम व एक दिन सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.8.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

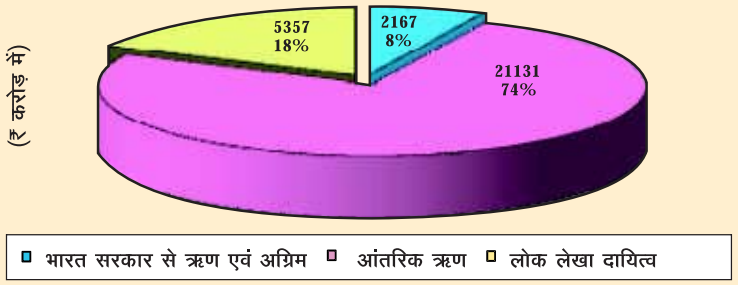
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियाँ अर्थात भूमि और भवनों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते है। ***परिशिष्ट 1.4* - पार्ट-बी** मार्च 2012 को उसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2011 की तदनुरूपी स्थिति के साथ तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में मुख्यतः भारत सरकार से लिये गये आंतरिक उधार, ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे एवं जमा निधि से प्राप्तियॉ होती है, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष होते हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 कुल दायित्वों को संचित निधि और लोक लेखे के अतर्गत दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सरकारी कर्मचारी के लोक निधि शेष, जमा निधि, जमायें इत्यादि सम्मिलित हैं।

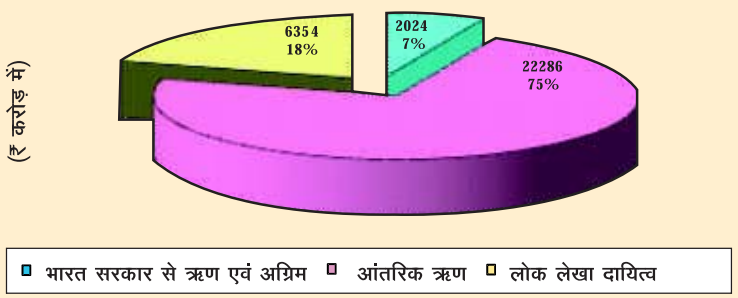
राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्य की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत की गई है। तथापि, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान राजकोषीय दायित्व का संघटन **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13** में प्रस्तुत किये गये है।

चार्ट 1.12: 01.04.2011 को बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन
(₹ 28655 करोड़)



चार्ट 1.13: 31.03.2012 को बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन
(₹ 30664 करोड़)



तालिका 1.20: राजकोषीय दायित्व की प्रवृतिः आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	15859	17568	19880	21131	22286
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2540	2404	2272	2167	2024
लोक लेखे दायित्व	3216	4112	5013	5357	6354
कुल	**21615**	**24084**	**27165**	**28655**	**30664**
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	25.7	27.4	28.0	25.9	24.7

- राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय दायित्व 42 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ 2007-08 में ₹ 21,615 करोड़ से 2011-12 में ₹ 30,664 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर 2010-11 में छः *प्रतिशत* के विरूद्ध 2011-12 में सात *प्रतिशत* थी।

- राज्य का राजकोषीय दायित्व ₹ 443.09 करोड रिजर्व फंड (₹ 439.12 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा ₹ 3.47 करोड़ सरकारी व्यावसायिक निकायों/विभागों के सामान्य रिजर्व फंड) के रूप में था।

- बढ़ते दायित्व राज्य सरकार के वित्त की अविच्छिन्नता का मुद्दा उठाता है। इसका वृद्धि दर 2009-10 में 13 *प्रतिशत* से 2010-11 में छः *प्रतिशत* तक घटी और 2011-12 में आंशिक रूप से बढ़कर सात *प्रतिशत* हो गई। तथापि, स.रा.घ.उ.

से राजकोषीय दायित्व का अनुपात 2009-10 में 28 *प्रतिशत* से 2011-12 में 24.7 *प्रतिशत* तक घटा जो उस वर्ष के लिए ते.वि.आ. के अनुशंसित 28.5 *प्रतिशत* से कम था। 2010-11 में राजस्व प्राप्तियाँ तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की तुलना में ये दायित्व क्रमशः 1.53 गुणा ओर 3.36 गुणा से घटकर 2011-12 में 1.37 गुणा और 3.07 गुणा हो गया। अतः राज्य के ऋण धारणीयता की क्षमता में चालू वर्ष में सुधार हुआ।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के बाहर बैंक ऋण सहित सभी ऋणों एन.एस.एस.एफ. के नामे ऋण प्रतिपूर्ति के लिए एक मर्जित निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। यद्यपि, सितम्बर 2012 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई थी।

- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं किया गया है (सितम्बर, 2012) ।

1.8.2 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार लेने वाले के द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के संधीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकते हैं। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया था और राज्य की संचित निधि की जमानत पर प्रत्याभूति की कोई सीमा निर्धारित की गई थी।

वित्त लेखे की विवरणी 9 में कोई आँकड़ा नहीं दिया गया था क्योंकि 2011-12 के दौरान और इसके पूर्व भी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराये गये थे। यद्यपि, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई।

1.8.3 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता[9] को निर्धारित करने वाली विभिन्न संकेतकों को विश्लेषित करना अनिवार्य है। ऋण स्थिरीकरण[10],

[9] समय की एक अवधि में एक नियत ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नकद परिसम्पततियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

[10] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर - ब्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण * दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात संभवतः गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों[11] की पर्याप्तता, उधार निधि[12] की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार के प्रत्याभूति का परिपक्वता रूपरेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

तालिका 1.21 2007-08 से प्रारंभ पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.21: ऋण धारणीयता : संकेतक और झुकाव

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	3087	(-)2022	(-)364	1825	1618
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-)1033	(-)1171	103	899	188
उधार निधि की निवल उपलब्धता	439	583	773	(-)737	(-)238
ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात	25.7	27.4	28.0	25.9	24.7
ब्याज भुगतान का बोझ (आई.पी./ आर.आर. अनुपात)	15	14	15	12	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	5	775(4)	1183(5)	1868(8)	1449(6)
1 - 3	1850(10)	2508(13)	2885(13)	2977(13)	3080(13)
3 - 5	2689(15)	2829(14)	3263(15)	2872(12)	2623(11)
5 - 7	2771(15)	2635(13)	2569(12)	3284(14)	4302(17)
7 और आगे	11084(60)	11225(56)	12252(55)	12298(53)	12856(53)
कुल	**18399**	**19972**	**22152**	**23299**	**24310**

कुल का प्रतिशत कोष्ठक में दिखाये गये हैं।

- जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में 2007-12 के दौरान (-)₹ 2,022 करोड़ और ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक विचलन दर्ज किया गया। 2009-12 के दौरान की प्रवृत्ति ने स.रा.घ.उ.-ऋण अनुपात में गिरावट इंगित किया और राज्य को ऋण-धारणीय स्थिति में पहुँचाया। तथापि, 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर में गिरावट के कारण प्राथमिक आधिक्य के प्रभाव के साथ प्रमात्रा विस्तार में थोड़ी कमी आई (₹ 1,618 करोड़) जो चिंता का विषय है।
- 2011-12 दौरान 24.7 *प्रतिशत* के साथ ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/एम.टी.एफ.पी. के लक्षित 25 *प्रतिशत* के बराबर था।

[11] बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

[12] कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगित ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

यह ते.वि.आ. के 28.5 *प्रतिशत* के मानक स्तर से भी कम था। 2010-11 (25.9 *प्रतिशत*) की तुलना में 2011-12 में इसके अनुपात में कमी आई।

- जहाँ तक संसाधन अन्तराल का संबंध है, 2007-08 में (-) ₹ 1,033 करोड़ के संसाधन अन्तराल के विरूद्ध 2010-11 के दौरान संसाधन अन्तराल ₹ 899 करोड़ तक बढ़ा, जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का उदघाटक है। तथापि, 2011-12 में यह ₹ 188 करोड़ तक तीक्ष्णता से घटा।

- कर्ज ली गई निधियों की कुल उपलब्धता 2007-08 में ₹ 439 करोड़ से 2009-10 ₹ 773 करोड़ तक बढ़ी जो 2010-11 में (-) ₹ 737 करोड़ तक घटी। तथापि, 2011-12 में यह ₹ 238 करोड़ रही।

- ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जैसा कि 2007-08 में 15 *प्रतिशत* से 2011-12 में 10 *प्रतिशत* तक कम हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में भी इसमें सुधार दर्ज किया गया, जैसा कि इसका अनुपात 12 *प्रतिशत* से घटकर 10 *प्रतिशत* हो गया।

- राज्य-ऋण की परिपक्वता अवधि से परिलक्षित होता है कि ऋण उत्तरदायित्व, तीन से पाँचवें वर्ष-खंड के अलावे, प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ती जा रही थी, जो कि भविष्य में बढ़ते ऋण उत्तरदायित्व का सूचक है। पुनः उधार इस प्रकार ली जानी चाहिए कि वर्ष विशेष में कोई ऋण समूहीकरण न हो सके क्योंकि इससे बजट पर अनचाहा दबाब बढ़ेगा।

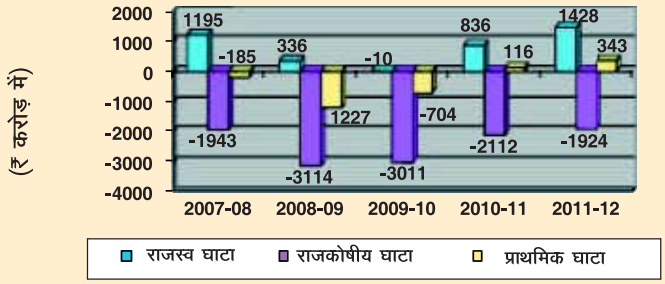
1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे-किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करती है। सरकारी लेखे में घाटे प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बताती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों को उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा घाटों के वित्तीय पोषण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आकलन के लिए प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके को बताती है।

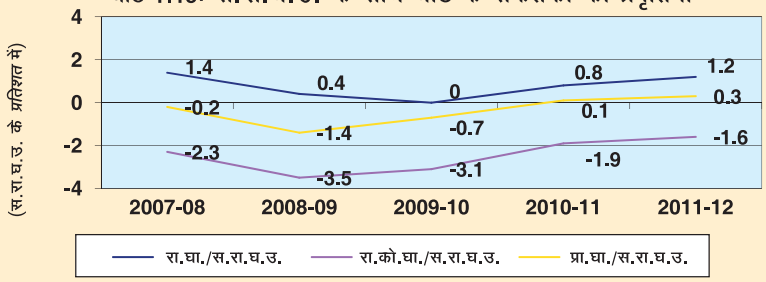
1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.14 एवं **1.15** 2007-12 के अवधि में घाटे के संकेतक की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते है।

चार्ट 1.14: घाटे के संकेतकों की प्रवृतियाँ



चार्ट 1.15: स.रा.घ.उ. के साथ घाटे के संकेतकों की प्रवृतियाँ



- 2007-12 के दौरान, सिवाय 2009-10 में ₹ 10 करोड़ का राजस्व घाटा, राज्य का राजस्व आधिक्य था। राजस्व आधिक्य की राशि 2007-08 में ₹ 1,195 करोड़ से 2009-10 में ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हो गई जों पुनः 2010-11 में ₹ 836 करोड़ और 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ के आधिक्य में परिवर्तित हो गई। राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और ते.वि.आ. द्वारा लक्षित "शून्य" राजस्व घाटा के लक्ष्य को 2008-09 के अन्त में प्राप्त कर लिया। तथापि, राज्य 2011-12 के लिए एम.टी.एफ.पी. के ₹ 5,379.11 करोड़ के राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

- राज्य का राजकोषीय घाटा 2007-08 में ₹ 1,943 करोड़ से 2008-09 में ₹ 3,114 करोड़ तक बढ़ा जो पुनः 2010-11 में ₹ 2,112 करोड़ और 2011-12 में ₹ 1,924 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3,390.49 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था जिसका मुख्य कारण बजट अनुमान के विरूद्ध राजस्व आधिक्य के साथ ही पूंजीगत व्यय और ऋण व अग्रिम में बढ़ोत्तरी था।

- स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता में सुधार दर्ज किया गया। यह मार्च 2010 के अन्त में 3.1 *प्रतिशत* से मार्च 2011 के अन्त में 1.9 *प्रतिशत* तक घटी जो पुनः मार्च 2012 के अन्त में भी 1.54 *प्रतिशत* तक कम हो गया। स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता 2010-11 के लिए 2.38 *प्रतिशत* तथा 2011-12 के लिए 2.80 *प्रतिशत* के अनुमानित सीमा के अन्दर थी। यह 2010-11 और 2011-12 के लिए ते.वि.आ. के तीन *प्रतिशत* के अनुशंसित सीमा के भी अन्दर था।

- 2007-12 के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा में व्यापक उतार-चढ़ाव रहा। प्राथमिक घाटा 2007-08 में ₹ 185 करोड़ से 2008-09 में ₹ 1,227 करोड़ तक घटा जो 2010-11 मे ₹ 116 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया। पुनः 2011-12 में बजट में अनुमानित ₹ 935 करोड़ के प्राथमिक घाटा के विरूद्ध यह ₹ 343 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य तक बढ़ा।

1.9.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण

वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्तीय घाटा के वित्त पोषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन हुआ जैसा कि **तालिका 1.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण प्रणाली

(₹ करोड़ में)

	विवरणी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11		
वित्तीय घाटे का बिखराव								
1	राजस्व घाटा	1195	336	(-)10	836	1428		
2	निवल पूंजीगत व्यय	2584	3051	2703	2664	3159		
3	निवल कर्ज एवं पेशगियाँ	554	399	298	284	193		
वित्तीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली *						**प्राप्ति**	**भुगतान**	**निवल**
1	बाजार से उधार	921	1238	1674	198	1253	469	784
2	भारत सरकार से कर्ज	(-)161	(-)136	(-)133	(-)104	33	155	(-)122
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	125	54	670	957	281	354	(-)73
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	602	1348	180	309	1104	661	443
5	लघु बचत, पी.एफ. आदि	162	200	272	105	613	544	69
6	जमा एवं अग्रिम	625	799	273	464	5236	4206	1030
7	उचन्त एवं विविध	(-)447	709	(-)258	473	23916	22974	942
8	प्रेषण	(-)146	(-)11	(-)39	6	4520	4503	17
9	अन्य	262	(-)1087	372	(-)296	-	5014	(-)5014
10	समग्र आधिक्य/घाटे	(-)1943	(-)3114	(-)3011	(-)2112	36956	38880	(-)1924
* ये सभी अंक वर्ष 2011-12 के दौरान सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।								

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

2011-12 के दौरान ₹ 1,924 करोड़ के राजकोषीय घाटे मुख्यतः वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 443 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 1,030 करोड़), उचंत एवं विविध (₹ 942 करोड़) से पूरा किया गया जो बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण मद में कम लेनदारी द्वारा प्रतितुलित किया गया।

घाटा एवं अधिक्य के गुण

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) की भरपाई करना चाहिए, जबकि राजस्व घाटे की भरपाई उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, तो राजस्व आधिक्य को पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा

सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय[13] का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का द्विविभाजन इंगित करता है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है।

तालिका 1.23: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य-अवयवों का विखंडन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	12071	9074	2584	598	12256	(+)2997	(-)185
2008-09	13232	10990	3051	418	14459	(+)2242	(-)1227
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय और प्राथमिक व्यय में संगत वृद्धि के विरूद्ध ₹ 12,071 करोड़ से ₹ 22,444 करोड़ तक बढ़ी। 2007-12 के दौरान पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव हुआ।
- 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रर्याप्त प्राथमिक आधिक्य प्राप्तियों के बावजूद, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2007-09 के दौरान 19 *प्रतिशत* और 2009-10 में, जब प्राथमिक घाटा था, 15 *प्रतिशत* की तुलना में 13 *प्रतिशत* था ।
- गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा प्राथमिक व्यय के भरपाई के कारण 2010-12 के दौरान प्राथमिक आधिक्य हुआ जो भविष्य में भी बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि राज्य के उत्पादक क्षमता को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सके।

1.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय अनुशासनः राज्य सरकार ने 2011-12 में राजकोषीय स्थिति सुधारने में सफल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 22,420 करोड़) 19.4 *प्रतिशत* बढ़ी है जबकि राजस्व व्यय (₹ 20,992 करोड़) 17 *प्रतिशत* से बढ़ा है। फलस्वरूप 2011-12 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 1,428 करोड़ से बढ़ा है। तथापि, राजस्व आधिक्य मध्यकालीन राजकोषीय नीति के लक्ष्य ₹ 5,379 करोड़ की तुलना में कम था। राजकोषीय घाटा (₹ 1,924 करोड़) भी वर्ष 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. का *प्रतिशत* 1.54 *प्रतिशत* रहा जो ते.वि.आ. के अनुशंसा के अन्दर (तीन *प्रतिशत*) था।

[13] ब्याज भुगतान के अलावे, राजस्व, पूँजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय

यद्यपि, वर्ष 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. में वृद्धि ते.वि.आ. मानदण्ड 14.14 *प्रतिशत* के सापेक्ष 12.1 *प्रतिशत* रहा।

2011-12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आकलन से ₹ 5,326 करोड़ से कम रहा। राज्य का अपना कर एवं कर भिन्न राजस्व का समावेशन 45 *प्रतिशत* था, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान का समावेशन 55 *प्रतिशत* रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 86 *प्रतिशत* था। इसकी वृद्धि स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर से काफी अधिक थी। योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) और गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 36 *प्रतिशत* एवं 64 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में यो.रा.व्य. 27 *प्रतिशत* से और गै.यो.रा.व्य. 12 *प्रतिशत* से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता कुल राजस्व व्यय का 22 *प्रतिशत* था।

सरकार को स्वयं के राजकोषीय लक्ष्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना चाहिये।

पूंजीगत व्ययः वर्ष 2011-12 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 3,159 करोड़) वर्ष 2011-12 के सापेक्ष ₹ 495 करोड़ बढ़ा। तथापि, इसका *प्रतिशत* वर्ष 2009-10 के दौरान 15 *प्रतिशत* की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व एवं प्राथमिक आधिक्य के बावजूद, 13 *प्रतिशत* पर स्थिर रहा। पूंजीगत व्यय से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत* एम.टी.एफ.पी के 3.15 *प्रतिशत* के सापेक्ष 2.54 *प्रतिशत* रहा।

सकल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी सामान्य श्रेणी राज्यों के समतुल्य औसत से काफी कम था। अतः सरकार को पूंजीगत व्यय को ज्यादा प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करना चाहिए।

विकास व्यय पर जोरः कुल विकास व्यय पिछले पाँच वर्षों के दौरान 15 *प्रतिशत* के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 54 *प्रतिशत* थी, जबकि विकासात्मक पूंजीगत व्यय केवल 13 *प्रतिशत* थी।

अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम साक्षरता दर एवं अधिक बी.पी.एल. आबादी को देखते हुए, सरकार को इसके विकासात्मक व्यय के पुनर्निर्धारण पर विचार करना चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षाः सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों (31 मार्च 2012 तक ₹ 182.57 करोड़) पर प्रतिफल विगत पाँच वर्षों में एक *प्रतिशत* से भी कम थी, जबकि 2007-12 के दौरान सरकारी उधारों पर व्यय अपेक्षाकृत काफी अधिक थी (औसत ब्याज दर 7.42 *प्रतिशत* से 8.03 *प्रतिशत*)।

सरकार को निवेशित धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए और उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ वाले परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि हस्तांतरणः राज्य बजट के बाहर, भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 4,194.42 करोड़ का हस्तांतरण सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। चूंकि वार्षिक वित्त लेखे ऐसे निधियों के प्रवाह को अधिग्रहण नहीं करता है अतएव राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय इस सीमा तक कम हो जाता है। इसके अलावा, अभिकरणों को निधियों का सीधा अंतरण, जबतक इसमें समरूप लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं होता है, उन अभिकरणों द्वारा निधियों का अनुचित अनुप्रयोग के खतरों को भी बढ़ाती है।

इन सीधे हस्तांतरण के सही लेखाकरन को सुनिश्चित करने और इनके अंतिम उपयोग के निगरानी के लिए एक पद्धति/युक्ति स्थापित की जानी चाहिए।

राजकोषीय उत्तरदायित्वः राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 30,664 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष सात *प्रतिशत* बढ़ा। राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. के 28 *प्रतिशत* से धीरे-धीरे घटकर 24.7 *प्रतिशत* (ते.वि.आ. के वर्ष 28.5 *प्रतिशत* की अनुशंसा के विरूद्ध) हो गया।

राज्य को स.रा.घ.उ. से राजकोषीय उत्तरदायित्व के अनुपात को बरकरार रखना चाहिए।

ऋण धारणीयताः वर्ष 2007-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा/आधिक्य के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में (-) ₹ 2,022 करोड़ से ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वर्ष 2010-11 में ₹ 1,825 करोड़ की तुलना में यह वर्ष 2011-12 के दौरान आंशिक रूप से गिरा (₹ 1,618 करोड़ तक)। तथापि, राज्य ऋण धारणीय स्थिति की ओर अग्रसर था। ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात, वर्ष 2011-12 के दौरान, एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 25 *प्रतिशत* के सापेक्ष 24.7 *प्रतिशत* था।

सरकार को वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु वर्तमान प्राथमिक आधिक्य और गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को बरकरार रखना चाहिए।

अध्याय 2

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों की तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान. समर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के दोनों भारित और दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अतः विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जब कभी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

राज्य का बजट प्राक्कलन वित्त विभाग द्वारा एकरूपता से निर्धारित प्रपत्रों में मुद्रित कर तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार प्राक्कलन की जाँच वित्त विभाग द्वारा की जाती है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण के उपस्थापन हेतु संकलित की जाती है। व्यय के नियंत्रण हेतु नियम बिहार वित्तीय नियमावली (जिसे झारखण्ड द्वारा अपनाया गया) में समाहित हैं। राज्य के बजट मैनुअल के नियम 112 के अनुसार समस्त अनुमानित बचतों को सरकार को तुरन्त अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के अधिकाई व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित अधिकाई हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित अधिकाई को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए। वर्ष 2011–12 के दौरान अनेक अनुदानों में बड़ी बचतों एवं आधिक्यों को देखा गया जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे के कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2011–12 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2011–12 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति–

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	दत्तमत	कुल	वास्तविक व्यय*	बचत (-) आधिय (+)
दत्तमत	(I) राजस्व	21594.22	2384.14	23978.36	18946.42	(-)5031.94
	(II) पूँजीगत	6352.73	327.14	6679.87	3249.84	(-)3430.03
	(III) ऋण एवं अग्रिम	1328.02	79.61	1407.63	217.10	(-)1190.53
कुल दत्तमत		**29274.97**	**2790.89**	**32065.86**	**22413.36**	**(-)9652.50**
भारित	(Iv) राजस्व	2443.55	16.21	2459.76	2314.36	(-)145.40
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Vi) लोक ऋण पुनर्भुगतान *	1403.18	16.28	1419.46	1639.02	(+)219.56
कुल भारित		**3846.73**	**32.49**	**3879.22**	**3953.38**	**(+)74.16**
सकल योग		**33121.70**	**2823.38**	**35945.08**	**26366.74**	**(-)9578.34**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2011–12

• व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 269.20 करोड़ तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 15.07 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट– वर्ष 2011–12 के दौरान आकस्मिक विपत्रों पर निकासित ₹ 1,470 करोड़ जिनके विरुद्ध विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ये व्यय अधिवर्णित हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹ 9,578.34 करोड़ का बचत ₹ 9,998.50 करोड़ (राजस्व संभाग के अन्तर्गत 55 अनुदानों एवं तीन विनियोगों के मामलों में कुल ₹ 5,377.92 करोड़ एवं पूंजीगत संभाग के 27 अनुदानों के मामले में ₹ 4,620.58 करोड़) का बचत एवं राजस्व संभाग के दो अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 420.16 करोड़ आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था। ₹ 2,823.38 करोड़ का अनुपूरक उपबंध प्राप्त किया गया जबकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से भी कम (29 *प्रतिशत*) था।

महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को मासिक सिविल लेखा का विवरण के अन्तर्गत शीर्षवार मासिक व्यय की स्थिति उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, सरकारी विभागों द्वारा बड़े–बड़े बचतों एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय को दूर करने हेतु कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे से लिए गए कुल 1168 उप–शीर्षों में से 865 उप–शीर्षों में अंतरों (बचत/आधिक्य) के लिए विभागों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 वित्तीय आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 38 मामलों (31 अनुदानों) में कुल बचत ₹ 8,766.05 करोड़ में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक की बचतें हुईं जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में

दर्शाया गया है। कुल ₹ 9,998.50 करोड़ की बचत में, ₹ 8,618.71 (86 *प्रतिशत*)[1] 20 अनुदानों के 22 मामलों से संबंधित है जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें
राजस्व दत्तमत						
1	1– कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	625.61	26.32	651.93	423.11	228.82
2	10– ऊर्जा विभाग	1074.18	2.81	1076.99	876.89	200.10
3	18–खाद्य, सार्वजनिक वितरण एव उपभोक्ता मामले विभाग	785.42	339.70	1125.12	957.11	168.01
4	20– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1086.02	8.21	1094.23	816.30	277.93
5	22– गृह विभाग	2206.56	297.67	2504.23	2248.06	256.17
6	23– उद्योग विभाग	226.90	126.23	353.13	195.72	157.41
7	26– श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	821.05	30.65	851.70	658.63	193.07
8	35– योजना एवं विकास विभाग	230.61	268.71	499.32	207.54	291.78
9	39– आपदा प्रबंधन विभाग	362.61	125.00	487.61	220.73	266.88
10	42– ग्रामीण विकास विभाग	836.37	0.22	836.59	619.59	217.00
11	47– परिवहन विभाग	513.65	310.09	823.74	492.00	331.74
12	51– कल्याण विभाग	750.98	184.21	935.19	626.05	309.14
13	56– पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	1272.30	140.10	1412.40	1102.16	310.24
14	58– माध्यमिक शिक्षा	629.16	46.09	675.25	475.50	199.75
15	59– प्राथमिक एवं जन शिक्षा	3841.88	0.03	3841.91	3039.10	802.81
16	60– समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	805.57	19.62	825.19	594.72	230.47
पूँजी –दत्तमत						
17	10– ऊर्जा विभाग	1295.00	0.00	1295.00	164.95	1130.05
18	20– स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	341.25	0.00	341.25	163.53	177.72
19	41– पथ निर्माण विभाग	1691.60	5.00	1696.60	796.66	899.94
20	48– नगर विकास विभाग	1003.56	0.00	1003.56	187.50	816.06
21	49– जल संसाधन विभाग	911.30	0.00	911.30	196.61	714.69
22	50– लघु सिंचाई विभाग	656.70	0.00	656.70	217.77	438.93
कुल		**21968.28**	**1930.66**	**23898.94**	**15280.23**	**8618.71**

स्रोत : झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, उपरोक्त अनुदानों में 114 उपशीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 6,968.32 करोड़ (कुल बचत का 70 *प्रतिशत*) का बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) हुआ। वर्ष 2011–12 में विनियोग लेखे में प्रदर्शित बचत के साथ बचत के कारणों का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

अधिकांश मामलों में बचत का कारण नहीं दिया गया है। बड़ी बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

[1] ₹ 100 एवं उससे अधिक बचत

2.4.2 सतत बचतें

10 मामलों में (नौ विभाग) विगत पाँच वर्षों के दौरान (**तालिका 2.3**) प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 *प्रतिशत* या उससे अधिक की सतत बचतें थीं।

तालिका 2.3: वर्ष 2007–12 के दौरान सतत् बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचतों की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	राजस्व–दत्तमत					
I	1– कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	165.37(44)	499.65(70)	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)
II	2– पशु पालन विभाग	70.40(39)	58.61(29)	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)
III	10– ऊर्जा विभाग	576.18(82)	234.46(53)	397.74(45)	346.05(39)	200.10(19)
IV	20– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	301.92(44)	184.31(23)	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)
V	23– उद्योग विभाग	62.70(37)	83.42(42)	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)
Vi	43– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	50.00(34)	76.74(50)	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)
7	49– जल संसाधन विभाग	16.76(11)	17.52(09)	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)
8	51– कल्याण विभाग	112.62(15)	219.46(23)	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)
	पूँजी दत्तमत					
9	41– पथ निर्माण विभाग	241.24(44)	88.05(14)	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)
10	49– जल संसाधन विभाग	148.08(20)	254.29(48)	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)

स्रोतः झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

(कोष्ठक के अंक कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशत बचत प्रदर्शित करती है)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विशाल बचतें वर्षों से जारी रहीं जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती हैं।

2.4.3 वर्ष 2011–12 के दौरान नियमन योग्य आधिक्य प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा नियमित करवाना आवश्यक है।

तालिका 2.4 में वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के विरुद्ध एक विनियोग एवं दो अनुदानों में कुल ₹ 420.16 करोड़ के आधिक्य का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.4: वर्ष 2011–12 के दौरान नियमन योग्य आधिक्य प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	14– ऋण की अदायगी	1419.46	1639.02	219.56
दत्तमत अनुदान				
2	15– पेंशन	2096.09	2296.69	200.60
3	25– सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	14.70	14.70	*
	कुल	**3515.55**	**3935.71**	**420.16**

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे

**आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160*

उपरोक्त अनुदानों/विनियोग में कुल ₹ 420.16 करोड़ का आधिक्य अनुदानों/विनियोग के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत या तो बिना बजट के या बजट से आधिक्य के कारण।

2.4.4 विगत वर्षों से संबंधित नियमन हेतु प्रावधानों से अधिक व्यय

वर्ष 2001–02 से 2010–11 के लिए ₹ 8,120.63 करोड़ का प्रावधान से अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार नियमित किया जाना अभी भी शेष है जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। नियमन हेतु लंबित वर्षवार आधिक्य व्यय की राशि का सारांश **तालिका 2.5** में दिया गया है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों का नियमित नहीं होना विनियोगों पर वित्त–विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित नियमन योग्य आधिक्य

(₹ करोड़ में)

	संख्या		प्रावधान से अधिक की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	3, 25, 32	-	0.04
2002-03	10, 32	13,14	1241.49
2003-04	10, 39,46	13,14	937.25
2004-05	23,39,40	13,14	576.07
2005-06	10, 29	13	3121.47
2006-07	38	13,14	1245.87
2007-08	15	14	334.44
2008-09	12	14	228.89
2009-10	-	14	116.71
2010-11	-	13,15,32	318.40
		कुल	**8120.63**

स्रोतः झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.4.5 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 45 मामलों में कुल ₹ 1,574.56 करोड़ का प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल आबंटन समाप्त नहीं हुए और इन उपशीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचतें हुईं।

2.4.6 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित है से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोग होता है। वर्ष 2011–12 के दौरान 25 उपशीर्षों जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। नौ योजनाओं/उपशीर्षों में से ₹ 13.16 करोड़ को दूसरे उपशीर्षों योजनाओं में पुनिर्विनियोजित किया गया जिसके फलस्वरूप उन योजनाओं पर ₹ 4.51 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। साथ ही 11 योजनाओं/उपशीर्षों में ₹ 15.51 करोड़ का अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की बचत हुई। यह भी देखा गया कि ₹ 17.01 करोड़ पाँच योजनाओं/उपशीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया, जो उन योजनाओं पर ₹ 1.47 करोड़ का अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त साबित हुआ।

2.4.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

छः मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उनसे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो उन विभागों पर अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को विनिर्दिष्ट करती है। ₹ 1,309.92 करोड़ के बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 1,323.77 करोड़ था जिसके फलस्वरूप ₹ 13.85 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.4.8 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी बचत प्रत्याशित हो, अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है।

33 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचतों (प्रत्येक अनुदानों/विनियोजनों में एक करोड़ और इससे अधिक बचत) में कुल ₹ 6,990.33 करोड़ में से ₹ 1,955.57 करोड़ (कुल बचत का 28 *प्रतिशत*) का अभ्यर्पण नहीं किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। इसके अलावा 79 मामलों में जिसमें अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था, ₹ 3,252.83 करोड़ (***परिशिष्ट 2.8***) का अभ्यर्पण मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवस में किया गया जिससे इन निधियों का अन्य विकासपरक उद्देश्यों में उपयोग करने का कोई अवसर नहीं रहा। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करती है।

2.4.9 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के वेग से बचना चाहिए। बजटीय नियंत्रण की प्रमुख आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यय की समरूप प्रवाह आवश्यक है। इसके बावजूद ***परिशिष्ट 2.9*** में सूचीबद्ध 26 शीर्षों में वर्ष 2011–12 के अंतिम तिमाही में व्यय (प्रत्येक मामलों में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक था। **तालिका 2.6** में भी वैसे 16

प्रमुख शीर्षों जिसमें बजट नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया गया, दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.6: वर्ष 2011–12 के अंत में व्ययों के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही में खर्च		मार्च 2012 में व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	2053	331.57	237.77	72	190.32	57
2	2225	623.99	397.79	64	336.03	54
3	2230	127.44	88.97	70	78.26	61
4	2401	303.70	211.34	70	165.14	54
5	2404	60.82	50.32	83	35.12	58
6	2425	138.48	104.06	75	96.16	69
7	2515	1389.17	889.36	64	778.33	56
8	2810	35.00	35.00	100	35.00	100
9	2852	86.34	57.80	67	54.64	63
10	3053	66.67	66.47	100	66.43	100
11	3075	450.25	450.25	100	450.25	100
12	4055	105.19	93.67	89	60.91	58
13	4202	75.98	55.53	73	48.07	63
14	4217	176.09	162.62	92	160.86	91
15	4225	204.20	193.26	95	169.07	83
16	4701	85.97	64.75	75	49.35	57

स्रोतः अभिश्रव स्तर कंप्यूट्राइजेशन डाटाबेश

यह देखा गया कि राज्य बजट द्वारा प्रमुख शीर्षों "2810" – ऊर्जा का अपरंपरागत श्रोत नये एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए" 3053– सिविल ऊर्जा विमानन प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए' और "3075– यातायात, जनजातीय क्षेत्र उप–योजनाओं के तहत रेलवे को लाभांश राहत एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए "उपलब्ध करायी गई, सम्पूर्ण निधियों का व्यय मार्च 2012 में किया गया।

2.5 विभागीय आँकड़ों का असमायोजन

बिहार वित्तीय नियमावली जिसे झारखण्ड राज्य द्वारा अपनाया गया, के वित्तीय नियम 475 (viii) विनिर्दिष्ट करती है कि विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर कारगर नियंत्रण तथा इसे बजटीय अनुदान के भीतर रखने एवं लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी बही में अंकित सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही में अंकित प्रविष्टियों से समाशोधित किया जाना चाहिए।

यद्यपि विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार इंगित किया जाता है फिर भी नियंत्रक–अधिकारियों द्वारा असमाशोधन, वर्ष 2011–12 के दौरान भी बना रहा। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 22,444 करोड़ के प्राप्तियों के विरुद्ध कुल ₹ 9,822 करोड़ (44 *प्रतिशत*) का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय ₹ 24,368 करोड़ में से 25 नियंत्रक– अधिकारियों द्वारा ₹ 20,101 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान, प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक कुल ₹ 16,038 करोड़ का असमाशोधित व्यय तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: नियंत्रक पदाधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय असमाशोधित रही (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नियंत्री पदाधिकारीगण / विभागों	असमासोधित राशि
1	2	3
1	विधि सचिव	142.61
2	चुनावी आयुक्त	18.14
3	व्यावसायिक कर सचिव	40.15
4	वित्त राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव	2267.07
5	सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार बोर्ड	322.43
6	अपर सचिव गृह (पुलिस) आयुक्त, उत्तर छोटानगापुर मंडल हजारीबाग आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर मंडल	2203.57
7	गृह (कारा) महानिरीक्षक	10.35
8	वित्त सचिव	2296.68
9	उप–सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	3980.56
10	उप–सचिव, उच्च शिक्षा	75.97
11	उप–सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा मामले	29.47
12	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	293.98
13	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	69.08
14	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	264.56
15	सचिव, आवास (हाउसिंग)	23.11
16	सचिव, नगर विकास	182.90
17	सचिव, कल्याण, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	577.01
18	श्रम आयुक्त, निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	106.44
19	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा	233.11
20	कृषि सचिव	600.61
21	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, सहकारी	215.71
22	आयुक्त–सह–सचिव, ग्रामीण विकास	189.44
23	उप–सचिव, ग्रामीण विकास	232.83
24	निदेशक, पंचायती राज संस्थान	1581.15
25	उद्योग निदेशक	81.15
	कुल	**16038.08**

विभागीय आँकड़ों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही से असमाशोधन के कारण प्राप्तियों एवं व्ययों के अशुद्ध वर्गीकरण के संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

2.6 लघु शीर्ष '800– अन्य व्यय' के अंतर्गत प्रावधान

लघु शीर्ष 800– अन्य व्यय उन कार्यक्रमों के प्रावधान/व्यय को अन्तर्विष्ट करती है जिसे उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्य वित्त 2011–12 में, ₹ 336.42 करोड़ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 23 प्रमुख शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय में उपलब्ध कराया गया जिसे बजट में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन कार्यक्रमों को उपयुक्त लघु शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 9,998.50 करोड़ की विशाल बचत हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनओं/उपशीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचतें राज्य में विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 420.16 करोड़ उपबंधों से अधिक व्यय हुए जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2001–2011 के दौरान ₹ 8,120.63 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित करना भी अभी शेष है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से जुड़े 9 विभागों में निरंतर बचतें अंकित की गईं। 79 उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,252.83 करोड़ का अभ्यर्पण वर्ष के अंतिम दो दिनों में किया गया जिससे इन निधियों का अन्य विकासपरक उद्देश्यों पर व्यय करने का अवसर नहीं रहा। 16 शीर्षों में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया गया व्यय का वेग बजटीय एवं व्यय संबंधी नियंत्रणों को बाधित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागों के व्ययों (₹ 20,101 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 9,822 करोड़) का समाशोधन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही के साथ नहीं किया गया।

2.8 अनुशंसाएँ

- सभी सरकारी विभागों में खासकर उन विभागों में, जिसमें निरंतर बचतें हुई, बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में भारी व्यय से बचने के लिए उपयुक्त उपाय की जरूरत है।
- 2001–02 के दौरान हुए प्रावधानों से अधिक व्यय का नियमन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।
- नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों को प्रतिमाह महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही के साथ समाशोधित करना चाहिए।

अध्याय 3

अध्याय 3 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का अनुपालन लेखा परीक्षा

पृष्ठभूमि

झारखण्ड में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों के द्वारा कोषागार से अग्रिम निधि का आहरण असामान्य तौर पर ज्यादा रहा है। वर्ष 2000–12 के दौरान 53,548 ए.सी. विपत्रों के द्वारा कुल ₹ 13,543 करोड़ के आहरण में 30 जून 2012 तक 25,611 ए.सी. विपत्रों से संबंधित ₹ 6,861 करोड़ बकाया है। अग्रिम तब तक असमायोजित रहा जब तक कि नियंत्रक अधिकारी (नि. अ.) द्वारा साक्ष्यकारी वाउचर के साथ महालेखाकार (ले. एवं हक.) को विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र नहीं सौंपा गया। फलस्वरूप, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की कुल बकाया राशि वर्ष 2008–09 के अंत में ₹ 4,208 करोड़ से बढ़ते हुए 2011–12 के अंत तक ₹ 6,861 करोड़ हो गई और हमलोग लेखा परीक्षा के अन्तर्गत यह आश्वासन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं कि क्या आहरित अग्रिम उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त हुआ जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया। झारखण्ड में विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए गए निधियों का आहरण भी ए.सी. विपत्र के द्वारा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को अंतरित करने के लिए हुआ।

3.1 परिचय

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) का नियम 290 आकस्मिक व्यय को "सभी आकस्मिक एवं अन्य व्यय जो किसी कार्यालय को कार्यालय के रूप में रखने के लिए प्रबंधन या विभागों के तकनीकि कार्यों के लिए खर्च होते हैं" के रूप में परिभाषित करती है। आकस्मिक व्यय जिस पर भुगतान के बाद नि. अ. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, को बिना कोई सहायक वाउचर (झा. को. सं. के नियम 318) के ए. सी. विपत्र (टी. सी. प्रपत्र 38) के माध्यम से अग्रिम आहरण किया जा सकता है। व्यय को संबंधित सेवा शीर्षों के अन्तर्गत विकलित किया जाता है और नि. अ.[1] द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित साक्ष्यकारी सब–वाउचर के साथ डी.सी. विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 39 में)[2] संबंधित माह के अगले माह के 25 तारीख[3] या उससे पहले महालेखाकार (ले. एवं हक.) को सौंपना आवश्यक है। इस आशय में यह प्रमाणपत्र कि विगत माह में आहरित डी.सी. विपत्र का मासिक विवरणी नि.अ. को प्रति हस्ताक्षरण हेतु सौंप दिया गया है, को प्रत्येक माह के 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत प्रथम ए.सी. विपत्र के साथ संलग्न की जाएगी (झा. को. सं. का नियम 319)।

आगे, झा. को. सं. का नियम 300 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागार में आकस्मिक विपत्र जमा करने के समय आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अ. एवं सं. अ.) को प्रमाणित करना होता है कि विपत्र राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के भीतर कर ली जाएगी और संवितरित नहीं की गई राशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय में डी. सी. विपत्र प्राप्त होने पर सब–वाउचर की संवीक्षा पश्चात् इसे ए.सी. विपत्रों के साथ समायोजित की जाती है और अंतर या नामंजूरी को वसूली हेतु चिन्हित की जाती है और गलत वर्गीकरण होने पर समायोजित किया जाता है। इसके बावजूद, आकस्मिक व्यय पर कारगर नियंत्रण की जवाबदेही मुख्यतः कार्यालय प्रधान पर एवं ए.सी. विपत्र के मामलों में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी पर है।

---

1 यदि नियंत्रक अधिकारी नहीं हो तो इसे कार्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले. एवं हक.) को सीधे भेजा जा सकता है।

2. झा. को सं. के नियम 320

3 झा. को सं. के नियम 322

जुलाई–अगस्त 2012 में 2009–12 की अवधि के लिए ए.सी. विपत्र से निधि के आहरण का अनुपालन लेखा परीक्षा किया गया। उच्च बकाया ए.सी. विपत्र वाले तीन विभागों (गृह, मानव संसाधन विकास एवं ग्रामीण विकास) का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। राज्य में 2009–12 के दौरान ₹ 3,368 करोड़ का आहरण ए.सी. विपत्र के माध्यम से किया गया जिसमें से बकाया राशि ₹ 2,653 करोड़ थी जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है। तीन चयनित विभागों में इस दौरान ₹ 1,731.27 करोड़ का आहरण किया गया जिसमें ₹ 1,456.72 करोड़ बकाया रहा (***परिशिष्ट 3.1***)। इन तीनों विभागों में 30 आ. एवं सं. अ. (डी. डी. ओ.) द्वारा कुल ₹ 1,170.16 करोड़[4] (2009–12 के दौरान कुल ए.सी. विपत्रों का 35 *प्रतिशत*) का 245 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से आहरण का जाँच किया गया।

3.2 ए.सी. विपत्र के आहरण का झुकाव

ए.सी. विपत्र के माध्यम से निधि का आहरण के समय, व्यय संबंधित सेवा शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। अतः ऐसे निधियों के विशिष्ट उद्देश्यों में प्रयुक्ति को निर्धारित समय सीमा[5] के अंदर लेकिन उस वित्तीय वर्ष[6] के 31 मार्च या उससे पहले, सुनिश्चित करना आवश्यक है। डी.सी. विपत्रों को समय पर नहीं जमा करना वित्तीय अनुशासनों का उल्लंघन है और यह दुर्विनियोग के जोखिम को उत्पन्न करती है। 2000–2012 के दौरान ए.सी. विपत्रों के माध्यम से निधि का आहरण सौंपे गए डी.सी. विपत्र एवं बकाया राशि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है :

तालिका 3.1: बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		जमा किया गया डी.सी. विपत्र		बकाया ए.सी. विपत्र		बकाया राशि की प्रतिशतता
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2000-2009	48783	10175	26826	5967	21957	4208	41
2009-2010	2084	997	598	391	1486	606	61
2010-2011	1622	771	420	194	1202	577	75
2011-2012	1059	1600	93	130	966	1470	92
कुल (2009-12)	**4765**	**3368**	**1111**	**715**	**3654**	**2653**	**79**
सकल योग	**53548**	**13543**	**27937**	**6682**	**25611**	**6861**	**51**

कुल स्रोतः वित्त लेखा (2011–12) में लेखा टिप्पणी

उपरोक्त तथ्यों से देखा गया कि कुल बकाया राशि ₹ 6,861 करोड़ में से ₹ 4,208 करोड़ (61 *प्रतिशत*) तीन वर्षों से अधिक पुराना है। 2000–2009 के दौरान बकाया राशि औसतन इस दौरान ए.सी. विपत्र से आहरित कुल राशि का 41 *प्रतिशत* था, जबकि लंबित मामलों में वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में वृद्धि में क्रमशः उस वर्ष में आहरित कुल ए.सी. विपत्रों की राशि का 61 *प्रतिशत*, 75 *प्रतिशत* एवं 92 *प्रतिशत* रहा।

हम लोगों ने देखा कि वर्ष 2010–11 के दौरान ए.सी. विपत्रों से आहरण में पिछले वर्ष से 23 *प्रतिशत* की कमी आई जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान राशि में 108 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि हुई। हम लोगों ने यह भी देखा कि वर्ष 2011–12 के अंत में ए.सी. विपत्र में

4 गृह ₹ 307.54 करोड़ (110 विपत्र), मानव संसाधन विकास ₹ 704.82 करोड़ (52 विपत्र), ग्रामीण विकास/ पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.यो. (विशेष प्रमंडल) ₹ 157.80 करोड़ (83 विपत्र)

5 माह के प्रथम तारीख से अगले माह के 10 तारीख तक नि.अ. को प्रतिहस्ताक्षरण हेतु विस्तृत विपत्र जमाकरने के लिए (झा.को.सं. के नियम 319)

6 झा.को.सं. के नियम 300

बकाया[7] राशि वर्ष 2009–10 (₹ 6,366 करोड़) एवं वर्ष 2010–11 (₹ 6,239 करोड़) के बकाया राशि से अधिक था।

चयनित विभागों में से, मानव संसाधन विकास विभाग में वर्ष 2009–10 में ए.सी. विपत्र से आहरित राशि ₹ 73.24 करोड़ (94 विपत्र) से घटकर वर्ष 2010–11 में ₹ 54.14 करोड़ (54 विपत्र) हो गई पुनः वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर ₹ 678.88 करोड़ (43 विपत्र) हो गई। ए.सी. विपत्र की बकाया राशि वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 70.30 करोड़ (87 विपत्र) से घटकर वर्ष 2010–2011 के दौरान ₹ 43.97 करोड़ (49 विपत्र) एवं वर्ष 2011–12 के दौरान यह बढ़कर रु 665.50 करोड़ (37 विपत्र) हो गई। संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वर्ष 2011–12 के दौरान 6 ए.सी. विपत्रों से आहरित ₹ 607 करोड़ के लिए डी.सी. विपत्र बकाया था।

इसी प्रकार, गृह विभाग में वर्ष 2009–10 के दौरान ए.सी. विपत्र से आहरित राशि ₹ 156.50 करोड़ (291 विपत्र) से घटकर वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 68.96 करोड़ (97 विपत्र) एवं वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर ₹ 242.05 करोड़ (79 विपत्र) हो गई। ए.सी. विपत्र की बकाया राशि वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 90 करोड़ (210 विपत्र) से घटकर वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 15.68 करोड़ (60 विपत्र) हो गई। पुनः यह वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर ₹ 223.15 करोड़ (66 विपत्र) हो गई। चयनित ए.सी. विपत्रों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011–12 के दौरान सात ए.सी. विपत्रों द्वारा आहरित ₹ 208.36 करोड़ पुलिस बल आधुनिकीकरण से संबंधित था जिसका डी.सी. विपत्र जमा नहीं किया गया।

दूसरी तरफ ग्रामीण विकास विभाग में ए.सी. विपत्र से आहरण वर्ष 2009–10 में ₹ 145.81 करोड़ (149 विपत्र) से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 183.46 करोड़ (206 विपत्र) हो गई और पुनः 2011–12 में यह घटकर ₹ 128.23 करोड़ (106 विपत्र) हो गई। ए.सी. विपत्र का बकाया राशि भी वर्ष 2009–10 में ₹ 88.30 करोड़ (140 विपत्र) से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 136.68 करोड़ (192 विपत्र) हो गई और पुनः वर्ष 2011–12 में यह घटकर ₹ 123.14 करोड़ (102 विपत्र) हो गई।

इन विभागों के विषय में विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

3.3 ए.सी. विपत्र से योजना निधि का आहरण

ए.सी. विपत्र से योजना निधि का आहरण अनुमान्य नहीं है क्योंकि यह आकस्मिक प्रकृति का नहीं है। हम लोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2011–12 में राज्य में 1,059 ए.सी. विपत्रों से आहरित कुल ₹ 1,600 करोड़ में से ₹ 1,418 करोड़[8] (89 *प्रतिशत*) योजना निधि था।

- झारखण्ड में वर्ष 2011–12 के अंत तक ए.सी. विपत्रों में बकाया राशि को अन्य चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़) के सापेक्ष विश्लेषण ने दर्शाया कि झारखण्ड में लंबित मामले अन्य राज्यों (बिहार के अलावा) की तुलना में काफी अधिक था जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है, जिसका मुख्य कारण झारखण्ड में ए.सी. विपत्रों से योजना निधि के आहरण है।

तालिका 3.2: ए.सी. विपत्रों की बकाया राशि

वर्ष	झारखण्ड	बिहार	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़
2011-12	6,861	18,798	158	20	शून्य

स्रोतः वित्त लेखा 2011–12 में लेखा टिप्पणी

- आगे, नमूना जाँचित ए.सी. विपत्रों की राशि ₹ 1,170.16 करोड़ (2009–12) में से ₹ 1,033.54 करोड़ (88 *प्रतिशत*) फ्लैगशिप कार्यक्रम (₹ 933.75 करोड़) एवं

7 राज्य वित्त 2009–10 एवं 2010–11 का प्रतिवेदन
8 वित्त लेखे (2011–12) की टिप्पणी के परिशिष्ट 'डी'

राज्य योजना (₹ 99.79 करोड़) से संबंधित था। फ्लैगशिप कार्यक्रम निधि (₹ 607 करोड़) का प्रमुख भाग सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित था जिसे क्रियान्वयन अभिकरण, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को निर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 83.46 करोड़ का योजना व्यय/पूँजीगत व्यय भी ए.सी. विपत्र के माध्यम से निधि का आहरण करके की गई। विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

ए.सी. विपत्रों से आहरण कर योजना/पूँजीगत व्यय संहिता आधारित उपबंधों की अवहेलना है (झा. को. सं. के नियम 318 जो ए.सी. विपत्रों का आहरण केवल आकस्मिक व्ययों के लिए विनिर्दिष्ट करती है)। इसके अतिरिक्त ए.सी. विपत्रों से आहरित योजना निधियों का निर्धारित समय सीमा[9] के भीतर खर्च होने की क्षीण संभावना थी।

- झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2011–12 के 'लेखा टिप्पणी' में बजट उपबंधों के वर्गीकरण के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, इंदिरा आवास योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि के लिए ऑब्जेक्ट शीर्ष (उद्देश्य शीर्ष) '70–राज्यांश' राज्य के अंशों के लिए एवं '69–केन्द्रांश' केन्द्रीय अंशों के लिए था। यद्यपि, निधि का कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता अनुदान (जी. आई. ए.) के रूप में निर्गत किया जाना था, लेकिन राज्य बजट के कार्यक्रम शीर्षों में अन्य पड़ोसी राज्यों[10] की भाँति सहायता अनुदान की तरह फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए निधि का उपबंध नहीं होने के कारण, विभाग सहायता अनुदान विपत्रों में निधि का आहरण नहीं कर पाया। आगे, आहरण अधिकारियों ने निधि निर्गत करते समय कार्यान्वयन अभिकरण को उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जमा करने का निर्देश दिया क्योंकि व्यय आकस्मिक प्रकृति का नहीं था। अन्य तीन राज्यों की तुलना में झारखण्ड में अधिक ए.सी. विपत्रों की राशि का बकाया होने का यह एक कारण था जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

- बिहार वित्त विभाग के दिनांक 17 अप्रैल 1998 के आदेश के कंडिका 15 जिसे झारखण्ड राज्य द्वारा अपनाया गया, के अनुसार किसी प्रशासनिक विभाग के सचिव आ. एवं सं. अ. को केवल वैसे सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम निकासी की अनुमति देगा जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है।

  मानव संसाधन विकास विभाग के ए.सी. विपत्रों के जाँच के दौरान हमलोगों ने देखा कि विभाग सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षर भारत कार्यक्रम का निधि स्वीकृत करते समय वित्त विभाग के तिथि 17 अप्रैल 1998 के आदेश का उद्धरण देते हुए आ. एवं सं. अ. को कार्यक्रम के सम्पूर्ण निधि ₹ 611 करोड़ (***परिशिष्ट 3.2*** के क्रम 1 एवं 3) का अग्रिम निकासी की अनुमति (2011–12) दी। कार्यक्रम के सम्पूर्ण निधि के अग्रिम निकासी की स्वीकृति सरकार के आदेश का उल्लंघन था।

3.4 पूँजीगत कार्यों के लिए ए.सी. विपत्रों से निधि का अनाधिकृत आहरण

झा. को. सं. के नियम 318 के अनुसार ए.सी. विपत्रों से निधि का आहरण केवल आकस्मिक व्यय के लिए किया जा सकता है। इसलिए पूँजीगत कार्यों के लिए ए.सी. विपत्र का आहरण अनुमान्य नहीं है।

---

[9] माह के प्रथम तारीख से अगले माह के 10 तारीख अर्थात् 1 से 40 दिन (झा. को. सं. के नियम 319) लेकिन उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के बाद नहीं (झा. को. सं. के नियम 300)

[10] मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के राज्य बजट में केन्द्रीय योजनाओं के लिए एक अलग उद्देश्य शीर्ष सहायता अनुदान है जो व्यय की प्रकृति को इंगित करती है। निधि के स्रोतों को इंगित करने के लिए उद्देश्य शीर्ष के तहत एक विस्तृत शीर्ष केन्द्रांश/राज्यांश है। दोनों राज्यों में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का आहरण भी निषेध है।

हमलोगों ने अवलोकन किया (जुलाई 2012) कि गृह विभाग के अनुमोदन के आधार पर उप–कारा, चक्रधरपुर में भवन निर्माण हेतु निरीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा ने ₹ 14.38 करोड़ का आहरण (अक्टूबर 2010 से अगस्त 2011) के लिए ए.सी. विपत्र के द्वारा किया और कार्य सम्पादन के लिए राशि को कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल को अंतरित किया। इनमें ₹ 4.96 लाख मिट्टी जाँच पर व्यय हुआ। ₹ 14.33 करोड़ की राशि भू–अधिग्रहण में विलंब की वजह से जुलाई 2012 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। पूँजीगत कार्यों के लिए ए.सी. विपत्र का आहरण और भू–अधिग्रहण से पहले राशि का अंतरण अनियमित थी।

3.5 वित्तीय वर्ष के अंत में ए.सी. विपत्र का आहरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से आहरित राशि का वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग हो जाना चाहिए। आगे, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 के अनुसार कोषागार से कोई भी राशि की निकासी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक इसका तुरंत भुगतान आवश्यक न हो। कोषागार से प्रत्याशित मांगों के लिए अग्रिम आहरण चाहे वह कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिसका सम्पादन में सम्भवतया अधिक समय लग सकता है, या विनियोगों के व्यपगत होने से बचाने के लिए, अनुमान्य नहीं है। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से निधि का आहरण करते समय आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रमाणित करना पड़ता है कि वित्तीय वर्ष के भीतर सभी निधियों का भुगतान कर दिया जाएगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान योजना राशि का ₹ 888.98 करोड़[11] (ए.सी. विपत्र से आहरित कुल योजना निधि का 63 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च 2012 में किया गया। तीन चयनित विभागों में वित्तीय वर्ष के अन्त में ए.सी. विपत्रों (नमूना जाँच मामले) के द्वारा वर्ष 2009–12 के दौरान आहरित राशि ***तालिका 3.3*** में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: वित्तीय वर्ष के अंत में नमूना जाँच परीक्षित ए.सी. विपत्रों का आहरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	राशि		मार्च में आहरित		मार्च के अंतिम सप्ताह में आहरित		31 मार्च को आहरित	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
गृह	110	307.54	66	93.11 (30)	29	42.86 (14)	15	28.16 (9)
मानव संसाधन	52	704.82	37	479.09 (68)	23	48.76 (7)	15	47.79 (7)
ग्रामीण विकास / पंचायती राज रा.ग्रा.रो.गा.यो. (विशेष प्रमंडल)	83	157.80	55	84.43 (54)	40	67.78 (43)	20	40.41 (26)
कुल	**245**	**1170.16**	**158**	**656.63 (56)**	**92**	**159.40 (14)**	**50**	**116.36 (10)**

स्रोतः अभिश्रव स्तर कम्प्यूटराइजेशन डाटाबेस
कोष्टक के आँकड़े ए.सी. विपत्र से आहरित राशि का कुल राशि से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान कुल आहरित ₹ 1,170.16 करोड़ में से ₹ 656.63 करोड़ (56 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च माह में किया गया। इसमें से ₹ 159.40 करोड़ (14 *प्रतिशत*) का आहरण मार्च माह के अंतिम सप्ताह में किया गया। वर्ष के अंतिम दिन का आहरण ₹ 116.36 करोड़ था। मार्च माह में आहरित योजना राशि, खासकर माह के अंतिम सप्ताह का आहरण वित्तीय वर्ष के भीतर प्रयुक्त हो जाना प्रतीत नहीं होता था।

11 वित्त लेखे (2011–12) की 'लेखा टिप्पणी' के परिशिष्ट 'ई'

- मानव संसाधन विकास विभाग के तीन आ. एवं सं. अ[12] के अभिलेख का नमूना जाँच दर्शाता है कि आ. एवं सं. अ. ने ए.सी. विपत्रों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों[13] के कार्यान्वयन के लिए ₹ 14.17 करोड़ का आहरण (मार्च 2010 एवं मार्च 2012) किया। इनमें से ₹ 10.50 करोड़ का संवितरण अगले वित्तीय वर्ष में किया गया और ₹ 3.67 करोड़ उसके पास असंवितरित रह गई (जुलाई/अगस्त 2012)। संवितरित राशि में से कार्यान्वयन अभिकरण ने जुलाई/अगस्त 2012 तक केवल ₹ 7.50 करोड़ का ही उपयोग किया (***परिशिष्ट 3.3***)। अतः ए.सी. विपत्र से ₹ 14.17 करोड़ का आहरण जिसका भुगतान तुरंत अनिवार्य नहीं था, विनियोग अधिनियम एवं झा. को सं. के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.6 ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण की पुनरावृत्ति

हमारे द्वारा नमूना जाँच ए.सी. विपत्रों के संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि 23 आ. एवं सं. अ. (**तालिका 3.4**) ने पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र जमा किए बिना बार–बार आहरण कर झा. को. सं. के नियम 319 एवं 320 का उल्लंघन करते हुए 223 ए.सी. विपत्रों से कुल ₹ 1,109.54 करोड़ का आहरण किया। विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

तालिका 3.4: ए.सी. विपत्रों से निधियों के आहरण की पुनरावृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	आ. एवं सं. अ. की संख्या	विपत्रों की सं.	राशि
1	मानव संसाधन विकास	6	50	700.06
2	गृह	9	108	304.45
3	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.यो. (विशेष प्रमंडल)	8	65	105.03
कुल		**23**	**223**	**1109.54**

स्रोतः भी. एल. सी. डाटाबेस

ए.सी. विपत्र (टी.सी. प्रपत्र 38) के साथ एक प्रमाण पत्र होता है कि चालू माह के पहली तारीख से पहले आहरित सभी आकस्मिक व्यय के लिए डी.सी. विपत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को प्रति हस्ताक्षरण एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रेषण हेतु अग्रसारित कर दी गई। उपरोक्त सभी मामलों में आ. एवं सं. अ. ने कोषागार में ए.सी. विपत्र प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर किए। अतः आ. एवं सं. अ. ने ए.सी. विपत्र आहरण करने के लिए गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए क्योंकि पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र बकाया पाया गया।

3.7 ए.सी. विपत्र के द्वारा आहरित निधि को बैंक खाते में रखना

झा. को सं. प्रावधानों के अनुसार निधि का आहरण तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इसका शीघ्र संवितरण आवश्यक न हो। आगे, वित्तीय नियम सरकारी पैसों को गैर–सरकारी खातों में रखने को निषेध करती है। हमलोगों ने अवलोकन किया कि ए. सी. विपत्रों से आहरित निधि, कार्यान्वयन अभिकरण को अंतरित किया गया, जिसे उनके द्वारा बैंक खाते में रखा गया, जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है।

- वित्त विभाग के एक संकल्प (जनवरी 2007) एवं गृह विभाग के निर्देश (मार्च 2007) के अनुसार बोर्ड/निगमों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त निधियों को व्यक्तिगत बही खातों (पी.एल. अकाउंट्स) में रखी जाएगी। ये देखा गया कि

12 जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद, गोड्डा और पलामू

13 मध्याह्न भोजन के अंतर्गत विद्यालय भवन एवं भंडार–सह–रसोई घर का निर्माण एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए उपसंवाद।

वर्ष 2009–12 के दौरान महा निरीक्षक (आधुनिकीकरण एवं प्रोविजन) ने ए.सी. विपत्र के माध्यम से ₹ 274.96 करोड़[14] (***परिशिष्ट 3.2*** का क्र. 4) का आहरण कर राशि पुलिस भवन निर्माण हेतु झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड[15] (झा. पु. आ. नि. लि.) को अंतरित कर दिया। आगे, पुलिस निरीक्षक, खूँटी ने ₹ 1.09 करोड़ (***परिशिष्ट 3.2*** का क्र. सं. 9 में सम्मिलित) का ए.सी. विपत्र से आहरण किया और राशि, कोबरा कैम्प के लिए पोर्टबल हट्स का निर्माण करने हेतु झा. पु. आ. नि. लि. को अंतरित (नवम्बर 2010) कर दिया। झा. पु. आ. नि. लि. ने ₹ 66.69 करोड़ बचत खाते में रखा। संवीक्षा से पता चला कि झा. पु. आ. नि. लि. ने जुलाई 2012 तक ठेकेदारों के साथ ₹ 119.41 करोड़ मुख्य कार्यों के लिए इकरारनामा किया। इस प्रकार से ₹ 156.64 करोड़ का आहरण बिना शीघ्र भुगतान के उद्देश्य से किया गया जो झा. को. सं. के नियम 300 का उल्लंघन है। आगे, ₹ 66.69 करोड़ (***परिशिष्ट 3.5***) का बचत खाते में रखना, विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है।

- दो प्रखण्डों[16] में प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का आवास निर्माण और प्रखण्ड कैम्पस विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने ₹ 6.20 करोड़ की स्वीकृति (अप्रैल 2010) दी और उपायुक्त, चतरा को ₹ 3.88 करोड़ के अग्रिम आहरण (मई 2010 और फरवरी 2011) की अनुमति प्रदान किया। राशि को ए.सी. विपत्र में आहरित (मार्च 2011) कर बचत खाते में रखा गया जिसमें से ₹ 0.95 करोड़ जून 2012 तक खर्च किया गया एवं ₹ 2.93 करोड़ बचत खाते में पड़ा रहा।

- आगे, ग्रामीण विकास विभाग ने 10 प्रखण्डों के लिए 10 वाहनों की खरीद हेतु उपायुक्त, राँची को जनवरी 2011 में ₹ छः लाख, मार्च 2011 में ₹ 30 लाख एवं मार्च 2012 में ₹ 24 लाख का आवंटन दिया। विभाग ने अग्रिम आहरण की अनुमति आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान हेतु दिया। उपायुक्त, राँची ने ए.सी. विपत्र से राशि का आहरण (मार्च 2011 एवं मार्च 2012) किया और इसे चालू बैंक खाते में रखा। ₹ 36 लाख का भुगतान (अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 के बीच) वाहनों की सुपुर्दगी के पश्चात् किया गया और ₹ 24 लाख बैंक खाते में पड़ा रहा (अगस्त 2012)। बिना शीघ्र भुगतान की आवश्यकता का ए.सी. विपत्र से आहरण एवं राशियों को बैंक खाते में रखना अनियमितता थी।

- 121 पंचायत मुख्यालयों में बुनियादी ढाँचों के अधिष्ठापन के लिए पंचायती राज एवं रा.ग्रा.रो.यो. (विशेष प्रमंडल) विभाग के स्वीकृति (मई 2011) के आधार पर उपायुक्त, राँची ने ए.सी. विपत्र से ₹ 10 करोड़ का आहरण (अक्टूबर 2011) किया और इसे बचत खाते में रख दिया। इनमें से ₹ 9.68 करोड़ मार्च से अप्रैल 2012 में विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची को निर्गत किया गया लेकिन जून 2012 तक राशि का उपयोग नहीं हो सका।

3.8 लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव

ए.सी. विपत्रों की राशि की एक बड़ी राशि का बकाया रहने से संबंधित मुद्दा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से बार–बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड, ने भी सरकार के मुख्य सचिव को ए.सी. विपत्र के आहरण संबंधी विभिन्न अनियमितताओं के बारे में बताया था (मार्च 2010)। उन्होंने योजना शीर्षों के अन्तर्गत ए.सी. विपत्रों का आहरण एवं राज्य के संचित निधि से राशि

14 ₹ 66.60 करोड़ 2009–10 में और रु.. 208.36 करोड़ 2011–12 में

15 झा. पु. आ. नि. लि. की स्थापना राज्य में पुलिस भवनों के निर्माण कार्य का सम्पादन एवं रख–रखाव के लिए गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के एक संकल्प (फरवरी 2002) के तहत किया गया और मार्च 2002 में एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया।

16 कान्हाचट्टी एवं मयूरहंड

का बैंक खातों में अंतरण को बंद करने की भी सिफारिश किए थे। यद्यपि, मुख्य सचिव के द्वारा सभी सचिवों एवं प्रधान सचिवों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के अनुशंसाओं का अनुपालन एवं ए.सी. विपत्र का आहरण एवं डी.सी. विपत्र का प्रस्तुतीकरण के संबंध में झारखण्ड कोषागार संहिता एवं झारखण्ड वित्तीय नियमों के उपबंधों का सख्त अनुपालन के लिए निर्देश (मार्च 2010) जारी किया, फिर भी हम लोगों द्वारा बताए गए अनियमितताएँ चयनित विभागों में जारी थी। आगे, वित्त विभाग एवं तीन चयनित विभागों ने ए.सी. विपत्रों के अनियमित आहरण को रोकने एवं समय पर विस्तृत विपत्रों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने संबंधी मुख्य सचिव के निर्देशों (मार्च 2010) के अनुपालन में लिए गए कदमों को सूचित करने के हमारे आग्रह (3 अक्टूबर 2012) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया।

3.9 निष्कर्ष

झारखण्ड में वर्ष 2000–12 के दौरान बड़ी राशि (₹ 13,543 करोड़) का आहरण संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से हुआ और विस्तृत आकस्मिक विपत्र नहीं जमा करने के कारण विपत्र दीर्घावधि के लिए बकाया (जून 2012 तक ₹ 6,861 करोड़) रहा। ए.सी. विपत्र ऐसे उद्देश्यों के लिए आहरित पाया गया जिसके लिए अग्रिम आहरण अनुमान्य नहीं था। विभागों द्वारा योजना कार्यान्वयन एवं अन्य योजना/पूँजीगत व्यय के लिए भी ए.सी. विपत्र का आहरण किया गया। आ. एवं सं. अ. द्वारा बार–बार ए.सी. विपत्रों का आहरण, पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्र जमा करने के संबंध में गलत प्रमाणपत्र देकर किया गया। हमलोगों ने यह भी अवलोकन किया कि योजना निधि का आहरण ए.सी. विपत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया, जबकि यह शीघ्र भुगतान हेतु आवश्यकता नहीं थी। ए.सी. विपत्रों से आहरित अप्रयुक्त राशि को बैंक खातों में रखा गया और इसे सरकारी खातों में नहीं जमा किया गया। आगे, राज्य बजट में फ्लैगशिप कार्यक्रमों के निधियों का सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप इसका आहरण ए.सी. विपत्रों से हुआ।

3.10 अनुशंसाएँ

- ए.सी. विपत्रों के माध्यम से निधि का आहरण केवल आकस्मिक व्ययों के लिए किया जाना चाहिए। व्यय जो आकस्मिक प्रकृति का नहीं है, के लिए ए.सी. विपत्र के आहरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- फ्लैगशिप कार्यक्रमों के निधि के लिए राज्य बजट में सहायता अनुदान का प्रावधान करना चाहिए एवं ऐसे निधियों का आहरण ए.सी. विपत्र में नहीं करना चाहिए।
- ए.सी. विपत्र से आहरित राशि जिसका व्यय नहीं हो सका, उसे शीघ्र कोषागार में जमा करना चाहिए। अनाधिकृत रूप से बैंक खातों में रखे गए राशि को शीघ्र सरकारी खातों में जमा करना चाहिए।
- कोषागार में आ. एवं सं. अ. द्वारा नए ए.सी. विपत्र आहरित करने से पहले, पूर्व में आहरित ए.सी. विपत्रों के लिए डी.सी. विपत्रों के वास्तविक प्रस्तुतीकरण को जाँचने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

अध्याय 4

अध्याय 4 वित्तीय प्रतिवेदन

एक ठोस आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों-प्रक्रियाओं तथा निदेशों का अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता अच्छे प्रशासन के लक्षणों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को रणनीतिक योजना तथा निर्णयीकरण सहित इसकी मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक होती है। यह अध्याय वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 भुगतित अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

बिहार वित्तीय नियम के नियम 341 (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुसार, जब तक सरकार किसी संदर्भ में अन्यथा निर्देशित न करे, अनुदान की स्वीकृति के प्रत्येक आदेश में उद्देश्य जिसके लिए वह दिया गया और अनुदान से जुड़े सभी शर्त्तों, यदि कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नियमावली के नियम 342 के नीचे टिप्पणी 2 के अनुसार यदि वर्ष के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिए गये हो, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त कर लिया जाना चाहिए एवं जाँचोपरान्त उनकी स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर इसे महालेखाकार (ले.एवं हक.), झारखण्ड को अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए।

ऐसा पाया गया कि 2010-11 तक भुगतित कुल ₹ 6,936.04 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 5732 उ.प्र.प. मार्च 2012 के अन्त तक अप्राप्त थे। इन उ.प्र.प. का बड़ा भाग तीन विभागों उद्योग विभाग (कुल ₹ 1,619.37 करोड़ के 490 उ.प्र.प.), मानव संसाधन विकास विभाग (कुल ₹ 1,247.54 करोड़ के 326 उ.प्र.प.) एवं नगर विकास विभाग (कुल ₹ 936.24 करोड़ के 3645 उ.प्र.प.) के नामे था। बकाया उ.प्र.प. का विभागवार विभाजन ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।

30 सितम्बर 2012 को, बकाया उ.प्र.प. की संख्या और राशि घटकर क्रमशः ₹ 5,232 करोड़ और ₹ 6,836.04 करोड़ रह गई, जैसा **तालिका 4.1** में दिखाया गया है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (30/09/2012 को)

क्र.सं.	वर्ष जिसमें अनुदान वितरित	वर्ष जिनमें उ.प्र.प बकाये थे	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	2007-08 तक	2008-09 तक	1942	2468.28
2	2008-09	2009-10	636	778.28
3	2009-10	2010-11	1230	1139.15
4	2010-11	2011-12	1424	2450.33
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कुल संख्या			**5232**	**6836.04**

स्रोतः झारखण्ड सरकार का वर्ष 2011-12 का वित्त लेखा

वृहत राशि के उ.प्र.प. की अप्राप्ति, अनुदानों के इच्छित उद्देश्य का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में, विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

4.2 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का विलंबित प्रस्तुतीकरण

4.2.1 धारा 14 और 15 के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण

राज्य में (पाँच[1] विभागों से संबंद्ध) 82 स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण थे जिन्हें राज्य सरकार के अनुदान और ऋणों से प्राप्त होता है। सितम्बर 2012 तक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा आठ निकायों और प्राधिकरणों के 2011-12 तक के लेखे प्राप्त किए जा चुके थे।

तालिका 4.2: वर्ष-वार लंबित वार्षिक लेखे

वर्षों की संख्या में विलम्ब	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या
0-1	18
1-3	33
3-5	20
5-7	02
7-9	शून्य
9 एवं अधिक	01
कुल	**74**

जैसा **तालिका 4.2** में दिया गया है, यह देखा जा सकता है कि 51 निकायों और प्राधिकरणों के संबंध में लेखे जमा करने में तीन वर्षों तक विलंबित था, 22 निकायों और प्राधिकरणों के लेखे तीन से सात वर्षों तक विलंबित था जबकि एक स्वायत्त निकाय का लेखा 9 वर्षों से अधिक से विलंबित था। इनके विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिये गये हैं।

सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता की विस्तृत जानकारी, स्वीकृत सहायता का उद्देश्य और कुल व्यय की अप्राप्ति के कारण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन तीन निकायों की लेखापरीक्षा होनी चाहिए, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

4.2.2 धारा 19 और 20 (i) के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण

राज्य में ऐसे दो स्वायत्त निकाय[2] है जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971, के अनुच्छेद 19 और 20 (i) के अन्तर्गत लेन देनों के परीक्षण, प्रचालन गतिविधियाँ और लेखे, लेखा परीक्षा में परीक्षित लेन-देनों के नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा के आयोजन, आन्तरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण का पुनरीक्षण, पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण इत्यादि से संबंद्ध लेखा परीक्षा की जाती है।

---

1 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य; मानव संसाधन विकास; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; ग्रामीण विकास; तथा कल्याण।

2 (1) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (2) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

इन दो संवैधानिक निकायों में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बि.कृ.वि.) ने 2005-06 के लेखों को 2009-10 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को लेखा परीक्षा हेतु सौंपा, जबकि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) ने 2003-04 से 2010-11 के लेखों को 2011-12 में सौंपा। वर्ष 2005-06 के लिए बि.कृ.वि. की लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) अक्टूबर 2010 में जारी कर दिया गया। जे.एस.ई.आर.सी. की लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 तक पूरी कर ली गई थी। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए जे.एस.ई.आर.सी. के एस.ए.आर. मई 2012 में और 2004-05 और 2006-07 के लिए अगस्त 2012 में जारी कर दिये गये थे। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए जे.एस.ई.आर.सी. के एस.ए.आर. जारी करना अभी शेष है।

राज्य विधानमंडल में एस.ए.आर. के प्रस्तुतीकरण की जानकारी नवम्बर, 2012 तक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अप्राप्त थी।

4.3 दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि

झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्तीय नियम का नियम 31 बताता है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, स्टोर या अन्य सम्पति के गबन या अन्य कारणों से हुई क्षति की तत्काल सूचना कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को दी जानी चाहिए।

37 सरकारी कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2011-12 के अन्त तक चार कार्यालयों[3] में चोरी, गबन/दुर्विनियोग, क्षति आदि की कुल छः घटनाएँ दर्ज की गई जिनमें ₹ 41.93 लाख सरकारी राशि निहित थी, जिन पर क्षति की भरपाई के लिए या तो विभागीय कार्रवाई/एक्जीक्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट केस के मामले लंबित थे या फिर मामले न्यायालय में लंबित थे। (सितम्बर, 2012 तक), ₹ 41.93 लाख के निहित राशि के इन मामलों के विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। लंबित मामलों की आवधिक रूप रेखा और प्रत्येक वर्ग-चोरी और दुर्विनियोग, में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 4.3** में दी गई है।

तालिका 4.3: दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि की रूप रेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों के अवधि की रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों की अवधि	मामलों की संख्या	शामिल राशि	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	शामिल राशि
0-5	6	41.93	चोरी	2	5.79
6-10	शून्य	शून्य	दुर्विनियोग/हानि	4	36.14
कुल	**6**	**41.93**	**कुल मामला**	**6**	**41.93**

स्रोतः सरकारी कार्यालयों से प्राप्त आँकड़े

[3] प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुडू; संयुक्त निदेशक (प्रशासन), योजना एवं विकास विभाग; कारखाना निरीक्षक, धनबाद अंचल एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, हजारीबाग।

इसके अलावे, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिन्हित आठ मामलों (₹ 153.11 करोड़) पर "किए गए कार्रवाई का विवरण" प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर, 2012)।

4.4 व्यक्तिगत जमा लेखे

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश दिनांक 19 फरवरी 2003 के अनुसार, कोषाधिकारी को प्रत्येक वर्ष ₹ 100 करोड़ का टोकन राशि रखते हुए तथा महालेखाकार, वित्त विभाग व संबद्ध प्रशासक की जानकारी देते हुए अधिशेष को संबंधित सेवा शीर्ष स्थानातरित करते हुए व्यक्तिगत जमा खाता को बंद कर देना चाहिए।

वित्त लेखों के अनुसार 2011-12 के अन्त में ₹ 68.56 करोड़ के प्रारम्भिक शेष के विरूद्ध ₹ 68.53 करोड़ अधिशेष था। सम्पूर्ण अधिशेष "राज्य अधिवक्ता कल्याण संघ निधि" के व्यक्तिगत जमा खाता से संबंधित था जिसे वित्त वर्ष 2011-12 के अंत तक बंद नहीं किया गया था।

4.5 सहायता अनुदान का संवितरण

झारखण्ड वित्तीय नियम के नियम 340 के अनुसार सहायता अनुदान वैसे व्यक्ति या निकाय को दिया जा सकता है जो सरकार से स्वतंत्र हो। सरकार के एक विभाग द्वारा उसी सरकार के दूसरे विभाग को सहायता अनुदान नहीं दिया जा सकता है।

यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान झारखण्ड के समेकित निधि से भुगतित ₹ 4,530.23 करोड़ के सहायता अनुदानों[4] में से, ₹ 618.68 करोड़ की राशि, अनुदान ग्राही निकायों के बजाय 11[5] सरकारी विभागों के अधिकारियों के पक्ष में आहरित किया गया। ऐसे आहरण संवितरण तो दर्शाते हैं किन्तु वित्तीय वर्ष के भीतर हुए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाते।

4.6 निष्कर्ष

राज्य संस्थानों/निकायों द्वारा ₹ 6,836.04 करोड़ के सहायता अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप राज्य सरकार जबावदेही सुनिश्चितिकरण एवं कार्यदक्षता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने में बाधित हुई। सितम्बर 2012 तक 74 निकायों और प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को प्राप्त नहीं हुए। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक "राज्य अधिवक्ता कल्याण संघ निधि" के व्यक्तिगत जमा खाता में उपलब्ध निधियों को समायोजित नहीं किए गए थे।

---

[4] वित्त लेखे 2011-12 के परिशिष्ट IV

[5] कृषि एवं गन्ना विकास; कला, संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य; सहकारिता; नागर विमानन; मानव संसाधन विकास; उद्योग; कार्मिक, प्रशासनिक एवं राज्य भाषा; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; समाज कल्याण; महिला एवं बाल विकास; शहरी विकास तथा जल संसाधन

4.7 अनुशंसाएँ

- विभाग द्वारा अनुदानग्राही संस्थाओं को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के ससमय प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे नियमित रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड को सौंपे जाने चाहिए।
- स्वायत्त निकायों के "पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" को विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए।

मृदुला सप्रू

राँची
दिनाकः

(मृदुला सप्रू)
प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा),
झारखण्ड, राँची

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांकः

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट- 1.1 पार्ट -ए
(संदर्भ कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय					
ए.	सामान्य आँकड़े				
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा
1	क्षेत्रफल				79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या				
	(ए)	2001 के जनगणना में अनुपात			2.69 करोड़
	(बी)	2010-2011			3.30 करोड़
3	(ए)	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	(बी)	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का अनियमित संख्या* (अखिल भारतीय 27.5 प्रतिशत)				40.4 प्रतिशत
5	(ए)	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत 64.8%)			44 प्रतिशत
	(बी)	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत 74%)			67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) आखिल भारतीय 50 प्रति 1000 जीवित जन्म				41
7	गिनी गुणांक***				
	(ए)	ग्रामीण (पूरे भारत-0. 30)			0.22
	(बी)	शहरी (पूरे भारत - 0.37)			0.35
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2011-12				124160 करोड़
9	स.रा.घ.उ.सी.ए.जी.आर[1] (2002-03 से 2011-12)			झारखण्ड	11.87 प्रतिशत
				अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.09 प्रतिशत
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.सी.ए.जी. आर. (2002-03 से 2011-12)			झारखण्ड	14.07 प्रतिशत
				अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.46 प्रतिशत
11	जन संख्या वृद्धि (2002-03 से 2011-12)			झारखण्ड	19.13 प्रतिशत
				अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.90 प्रतिशत

	ब.	वित्तीय आँकड़ा			
क्र. सं.		विवरण	आँकड़ा (प्रतिशत में)		
		सी.ए.जी.आर.	2002-03 से 2010-11		2002-03 से 2011-12
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	झारखण्ड
1	ए.	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	18.18	18.31
2	बी.	स्वयं के कर राजस्व का	16.74	15.95	16.57
3	सी.	गैर कर राजस्व का	12.84	13.94	13.31
4	डी.	कुल व्यय का	14.58	15.38	15.50
5	ई.	कुल पूँजीगत व्यय	21.25	15.08	15.46
6	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	15.41	17.41	16.17
7	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.00	13.60	14.56
8	एच.	वेतन एवं मजदूरी	13.43	20.81	19.87
9	आई	पेंशन	16.89	18.93	17.95

*सामान्य आँकड़ें का स्त्रोत : बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँक्ड़ा, 61वें दौर) ** शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित है एवं *** गिनी गुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँक्ड़ा का अनौपचारिक आक्लन, 61वें दौर 2004-05 एम.आर.पी.)
गिनी गुणांक जनसंख्या पर आधारित आय के असमानता की माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आंका जाता है, शून्य के नजदीक होने पर असमानता कम तथा एक के नजदीक होने पर असमानता अधिक होगी।

[1] स.रा.घ.उ. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

परिशिष्ट - 1.1 पार्ट -बी

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

भाग खः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचनाः राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैंः (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधिः राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और वाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे 'राज्य सरकार की संचित निधि' कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (I) के तहत गठित होती है ।

भाग II: आकस्मिक निधिः राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चो को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो । इस तरह के खर्चो का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं ।

भाग III: लोक लेखाः कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

पार्ट -सीः वित्त लेखे की अभिन्यास

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिसम्पतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पतियाँ होती है जिनका पूंजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिसम्पतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिसम्पतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती है।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संधारित किए जाते है।
विवरणी सं. 3	यह विवरणी राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार, बाजार ऋण तथा सरकार को दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एव अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष है और जिसके लिए सरकार अभिरक्षक या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उधारकर्त्ता के ग्रूप के अनुसार)जिसे विवरणी 16 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्त्ता संस्थान के ग्रूप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं. 9	सामविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटियों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमय व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों द्वारा गैस-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष 2011-12 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों,अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों,सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2012 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट - 1.2 पार्ट -ए
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली
(संदर्भः कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

खण्ड-'क'

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदण्डों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम **(परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी)** एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत तक मानते हुए, वर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा का प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्पलावक्ता को एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैर्टन आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृति (स.रा.घ.उ.)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपये में)	83950(एफ)	87794(एफ)	96933(क्यू)	110769(ए)	124160(पी)
स.रा.घ.उ. की विकास दर	25.42	4.58	10.41	14.27	12.09
स्त्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्याकण निदेशालय झारखण्ड सरकार					

एफ=अन्तिम अनुमान, क्यू=तीव्र अनुमान, ए=अग्रिम अनुमान, पी=औपबंधिक अनुमान

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/ प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)- 1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ [(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)] * 100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ.वृद्वि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष) /2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजीगत प्राप्तियॉ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व घाटा **घटाव** सभी योजना अनुदान और गैर योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर

परिशिष्ट- 1.2 पार्ट-बी
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 4)

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम के सम्बन्ध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है जो एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2012 के रूप में संशोधित की गई।

- राजस्व घाटे के लिए लक्ष्य: वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के अन्त में शून्य
- राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य: स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत -2011-12 से 2014-15

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
शेष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	28.50%	27.8%	27.3%	26.90%
ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	25.00%	25.00%	25.00%	
स.रा.घ.उ. वृद्धि (ते.वि.आ.)	14.14%	14.50%		
स.रा.घ.उ. वृद्धि (एम.टी.एफ. पी.)	14.00%	14.00%		
स्वयं के कर-स.रा.घ.उ. अनुपात	5.4%	5.4%		
गैर ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात	2.00%	2.00%		
ब्याज भुगतान	शेष उत्तरदायित्व के 10 वर्ष			
स.रा.घ.उ. में पूँजीगत परिव्यय की प्रतिशतता	3.15%	3.5%		

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ : कंडिका 1.1.1, 1.4 एवं 1.8.1; पृष्ठ 1, 8 एवं 29)

(₹ करोड़ में)

	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**12027(86)**	**13213(84)**	**15118(82)**	**18781(88)**	**22420(89)**
(i) कर राजस्व	**3474(29)**	**3753(28)**	**4500(30)**	**5717(30)**	**6954(31)**
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2846(82)	2996(80)	3597(80)	4473(78)	5522(79)
राजस्व उत्पाद	157(5)	205(6)	323(7)	388(7)	457(7)
वाहनों पर कर	136(4)	202(6)	234(5)	312(6)	392(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	156(4)	192(5)	238(5)	328(6)	401(6)
भू-राजस्व	26(1)	53(1)	41(1)	131(2)	53(1)
माल एवं यात्रीयों पर कर	71(2)	54(1)	13	21	41(0)
अन्य कर	82(2)	51(1)	54(2)	64(1)	88 (1)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1601(13)	1952(15)	**2254(15)**	**2803(15)**	**3038(14)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	5110(42)	5392(41)	**5547(37)**	**6154(33)**	**7170(32)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1842(15)	2116(16)	**2817(18)**	**4107(22)**	**5258(23)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	शून्य
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**44**	**19**	**22**	**24**	**24**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1 + 2+ 3)	**12071**	**13232**	**15140**	**18805**	**22444**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**2023(14)**	**2437(16)**	**3369(18)**	**2447(12)**	**2671(11)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	**2009**	**2434**	**3379**	**2315**	**2409**
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	..	--	..	--	229
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14	3	-10	132	33
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**14094**	**15669**	**18509**	**21252**	**25115**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**32**	**-**	**-**	**–**	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**7013**	**8335**	**8242**	**7721**	**10813**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**21139**	**24004**	**26751**	**28973**	**35928**
भाग-ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**10832(77)**	**12877(79)**	**15128(83)**	**17945(86)**	**20992(86)**
योजना	2980(28)	3813(30)	3758(25)	6004(33)	7646(36)
गैर योजना	7852(72)	9064(70)	11370(75)	11941(67)	13346(64)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	4607(43)	4924(38)	6605(44)	6991(39)	7846(37)
सामाजिक सेवाएँ	4257(39)	5385(42)	5610(37)	6707(37)	7287(35)
आर्थिक सेवाएँ	1967(18)	2533 (20)	2913(19)	4247(24)	5859(28)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	-	35	-	-	-
11. पूँजीगत व्यय	**2584(19)**	**3051(19)**	**2703(15)**	**2664(13)**	**3159(13)**
योजना	2558(99)	3015(99)	2682(99)	2621(98)	3111(98)
गैर योजना	26(1)	36(1)	21(1)	43(2)	48(2)
सामान्य सेवाएँ	108(4)	176(6)	112(4)	120(4)	156(5)
सामाजिक सेवाएँ	832(32)	1355(44)	825(31)	682(26)	866(27)

परिशिष्ट - 1.3 क्रमशः...

आर्थिक सेवाएँ	1644(64)	1520(50)	1766(65)	1862(70)	2137(68)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	**598(4)**	**418(3)**	**320(2)**	**308(1)**	**217(1)**
13. कुल (10+11+12)	**14014**	**16346**	**18151**	**20917**	**24368**
14. लोक ऋण का पूनर्भुगतान	**747**	**863**	**1190**	**1299**	**1639**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	572(77)	716(83)	1068(90)	1063(82)	1406(86)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	9(1)	-	-	78(5)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	175(23)	138(16)	123(10)	236(18)	155(9)
15. आकस्मिकता से विनियोजन	-	-	-	-	शून्य
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+ 14 + 15)	**14761**	**17209**	**19341**	**22216**	**26007**
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	6206	7185	7290	7400	9728
19.राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	**20967**	**24394**	**26631**	**29616**	**35735**
भाग- ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)1195	(+)336	(-)10	(+)836	(+)1428
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)1943	(-)3114	(-)3011	(-)2112	(-)1924
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21+23)	(-)185	(-)1227	(-)704	(+)116	(+)343
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	1758	1887	2307	2228	2267
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1266	2366	2333	3122	4530
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	6
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	-	-	-	6
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	शून्य
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	0.03
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) @	83950	87794	96933	110769	124160
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	21615	24084	27165	28655	30664
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	530	500	500	-	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत मे)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक)	25	247	262	167	182
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	1616	1797	1466	1503	573
भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6
स्वयं के कर से भिन्न राजस्व/ स.रा.घ.उ.	1.9	2.2	2.3	2.5	2.4

परिशिष्ट - 1.3 क्रमशः...

केन्द्रीय अंतरण/स.रा.घ.उ.	8.3	8.6	8.6	9.3	10.0
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.7	18.6	18.7	18.9	19.6
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	116.5	123.7	120.1	111.4	108.7
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.3	78.8	83.3	85.8	86.1
सामाजिक सेवा पर व्यय (ऋ. व अ. सहित) /कुल व्यय	40.6	43.8	37.2	36.8	34.3
आर्थिक सेवा पर व्यय(ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	30.0	27.4	27.5	30.7	33.7
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.4	18.7	14.9	12.7	13.0
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	17.7	17.6	14.3	12.2	12.3
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	1.4	0.4	0.0	0.8	1.2
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-2.3	-3.5	-3.1	-1.9	-1.5
प्राथमिक घाटा(आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.2	-1.4	-0.7	*	*
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-61.5	-10.8	*	*	*
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स.रा.घ.उ.	3.5	2.5	2.4	2.8	3.0
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	25.7	27.4	28.0	25.9	23.9
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	179.7	182.3	179.7	152.6	132.2
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	3087.0	-1966.0	-270.0	980.0	1573.0
ऋण निर्मोचन (मूलधन + ब्याज) / कुल ऋण प्राप्ति	-	5.4	3.1	4.3	3.9
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	0.4	1.17
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2890	2625	2077	4014	6855
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	81	84	85	89	95

***राज्य में राजस्व आधिक्य होने के कारण प्रासंगिक नहीं है।**

@ स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

कोष्ठ में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुपात (पूर्णांक) दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए
वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ : कंडिका 1.2; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

भाग क : वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2010-11			2011-12	2010-11		गैर योजना	योजना	कुल	2011-12
	अनुभाग क: राजस्व								
18781.12	I. राजस्व प्राप्तियाँ		**22419.45**	17944.74	**I.** राजस्व व्यय	13345.30	7646.28	20991.58	**20991.58**
5716.63	कर राजस्व	6953.89		6990.80	सामान्य सेवाएं	7399.49	446.07	7845.56	
				6707.30	सामाजिक सेवाएं	3728.14	3558.89	7287.03	
2802.89	कर भिन्न राजस्व	3038.22		3802.26	शिक्षा क्रीड़ा,कला एवं संस्कृति	2782.47	1273.42	4055.89	
				673.92	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	537.00	288.65	825.66	
6154.35	संघीय करों में राज्य के हिस्से	7169.93		437.49	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	225.19	243.54	468.72	
				28.15	सूचना एवं प्रसारण	35.64	12.02	47.66	
1281.40	गैर योजना अनुदान	1550.77		436.33	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	93.24	530.75	623.99	
1826.99	राज्य योजना हेतु अनुदान	2404.61		133.75	श्रम एवं श्रम कल्याण	41.28	85.96	127.44	
				1177.95	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-4.92	1124.55	1119.63	
998.86	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1302.03		17. 5	अन्य	18.04		18.04	
				4246.47	आर्थिक सेवाएं	2217.67	3641.32	5858.99	
				820.99	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप	337.89	642.71	980.60	
				1678.28	ग्रामीण विकास	421.81	1266.80	1688.61	
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				264.10	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	281.92	0.16	282.08	
				535.17	ऊर्जा	751.94	107.89	859.83	
				125.81	उद्योग एवं खनिज	42.17	168.99	211.16	
				202.27	परिवहन	316.90	513.08	829.98	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

				-	विज्ञान, तकनीकि एवं पर्यावरण				
				619.85	सामान्य आर्थिक सेवाएं	65.04	941.69	1006.73	
				0.17	सहायता अनुदान एवं अंशदान				
				17944.74	**कुल**	13345.30	7646.28	20991.58	20991.58
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			836.38	**II** खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				1427.87
18781.12	**कुल**	22419.45		18781.12	**कुल**				22419.45
	अनुभाग ख								
640.91	**III** आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित				**III** रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट				
	IV विविध पूंजीगत प्राप्तियां			2664.30	**IV** पूंजीगत परिव्यय	47.88	3111.49	3159.37	3159.37
				120.04	सामान्य सेवाएं	47.83	107.73	155.56	
				681.88	सामाजिक सेवाएं		866.31	866.31	
				54.20	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		75.98	75.98	
				142.68	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		163.53	163.53	
				297.48	जलापूर्ति स्वच्छता,आवास और नगर विकास		422.61	422.61	
				-	सूचना एवं प्रसारण				
				187.52	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण		204.20	204.20	
	अनुभाग ख अन्य (क्रमशः)								
				-	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार				
				-	अन्य				
				1862.38	आर्थिक सेवाएं	0.05	2137.44	2137.49	
				22.64	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप		55.28	55.28	
				593.87	ग्रामीण विकास		849.88	849.88	
				-	विशेष क्षेत्र कायक्रम				
				267.79	सिंचाई एवं बाढ़		399.31	399.31	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

					नियंत्रण				
				-	ऊर्जा				
				1.10	उद्योग एवं खनिज				
				971.93	परिवहन		799.85	799.85	
				5.05	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.05	33.13	33.18	
				2664.30	कुल	47.88	3111.49	3159.37	
24.12	**V** ऋण एवं अग्रिम का वसूली		23.42	307.56	**V** ऋण एवं अग्रिम का संवितरण		217.10	217.10	
	विद्युत परियोजना से			275.43	विद्युत परियोजना को		164.95	164.95	
20.79	सरकारी सेवको से	21.83		11.63	सरकारी सेवको को		18.11	18.11	
3.33	अन्य से	1.59		20.50	अन्य को		34.04	34.04	
836.38	**VI** नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		1427.87	-	**VI** नीचे लाया गया राजस्व घाटा				
2446.51	**VII लोक** ऋण प्राप्तियाँ		2671.23	1299.43	**VII** लोक ऋण पुर्नभुगतान				1639.01
	वाह्य ऋण	-	-	-	वाह्य ऋण				
2314.56	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	2409.51		1063.17	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			1406.36	
	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		8.86	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन			151.25	
	ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-							
131.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	32.53		236.26	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णभुगतान			154.71	
-	VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग		-	-	VIII आकस्मिकता नीधि विनियोग				
-	**IX** आकस्मिकता नीधि में स्थानान्तरित राशि			-	**IX** आकस्मिकता नीधि से व्यय				
7721.42	**X** लोक लेखा प्राप्ति		10813.40	7399.85	**X** लोक लेखा संवितरण				9727.77
571.73	लघु बचत एवं भविष्य निधि	613.38		467.08	लघु बचत एवं भविष्य निधि			543.74	
0.31	रक्षित निधि	138.58		223.50	रक्षित निधि			243.71	
181.39	उचन्त एवं विविध	305.76		211.63	उचन्त एवं विविध			231.63	
3298.20	प्रेषण	4520.03		3291.70	प्रेषण			4502.89	
3669.79	जमा एवं अग्रिम	5235.65		3205.94	जमा एवं अग्रिम			4205.80	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-ए क्रमशः...

1.39	अन्तर्राज्यीय समायोजन				अन्तर्राज्यीय समायोजन				75.40
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			(-)0.41	**XI** वर्ष के अंत का रोकड़ शेष				116.85
				-	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				
				(-)891.38	रिर्जव बैंक में जमा			93.85	
				11.78	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			18.59	
				-	चिन्हित निधि का निवेश				
				879.19	रोकड का निवेश			4.41	
30451.85	**कुल**		**37354.96**	**30451.85**	**कुल**				**37354.96**

परिशिष्ट 1.4 पार्ट-बी

31 मार्च 2012 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ : कंडिका 1.8.1 पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 को	दायित्व		31.03.2012 को
21131.39	**आन्तरिक ऋण**		**22285.78**
7845.07	ब्याज वाले बाजार ऋण	8630.39	
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.17	
6.30	भारत के जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30	
3223.35	अन्य संस्थाओं से ऋण	3513.94	
-	अर्थोपाय अग्रिम	151.25	
10056.50	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	9983.73	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	
2167.20	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2024.41**
1.33	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण		
12.06	गैर योजना ऋण	8.79	
2118.67	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2015.62	
1.24	केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण		
19.36	केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण		
14.54	अन्य अर्थोपाय अग्रिम		
1.39	अन्तर्राज्यीय समायोजन		
150.00	**आकस्मिकता निधि**		**150.00**
1458.06	**लघु बचत भविष्य निधि**		**1527.70**
3350.17	**जमा**		**4382.78**
548.22	**रक्षित निधि**		**443.10**
-	**अंतरण शेष**		
4.33	**उचंत एवं विविध शेष**		**78.47**
28810.76	**कुल**		**30892.24**
	सम्पति		
18371.55	**अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**21530.92**
54.07#	कंम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	101.86	
18317.48	**अन्य पूँजीगत परिव्यय**	21429.06	
	अन्तर्राज्यीय समायोजन		**75.40**
6996.47	**ऋण एवं अग्रिम**		**7190.15**
6418.56	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	6583.51	
579.71	अन्य विकास ऋण	612.17	

परिशिष्ट - 1.4 पार्ट-बी क्रमशः...

(-)1.80	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-5.53	
9.38	**अग्रिम**		**12.14**
-	**उचंत एवं विविध शेष**		
(-)0.41	**नगद**		**116.85**
	कोषागार में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण	-	
(-)891.39	रिर्जव बैंक में जमा	93.85	
-	जमा निधि का निवेश		
11.79	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	18.59	
879.19	नगद शेष निवेश	4.41	
287.30	**प्रेषण शेष**		**270.17**
3146.47	**सरकारी लेखे में घाटा**		**1696.61**
836.38	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा	1427.87	
-	(ii) विविध घाटा		
3982.85	वर्ष के शुरूआत में संचय घाटा/आधिक्य	3124.48	
28810.76			**30892.24**

निगम के खातों में ₹ 5.75 करोड़ उनके स्रोत की अनुपलब्धता के कारण छोड़कर बताया गया है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्त्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है । सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है । तदन्तर , भुगतेय या प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मदें इत्यादि लेखे में चित्रित नहीं है । उचन्त और विविध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है । लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और ' रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़े जो समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 214.42 करोड़ (निवल खाता) का अंतर था ।

परिशिष्ट 1.5

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों के कार्यों का विवरण

(संदर्भ : कंडिका 1.5.7 पृष्ठ 20)

क्र. सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़क एवं पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशामक सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण, और पारिस्थितीकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों के हितों का संरक्षण
10	गंदी बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्नयन
12	शहरी सुविधाओं जैसे उद्यानों, बगानों और खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य से संबंधित पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; श्माशान एवं श्मशान घाट तथा विद्युतीय शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, जानवरों पर अत्याचार से संरक्षण
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	पथ-प्रकाश, पड़ाव-स्थल, बस पड़ाव एवं लोक परिवहन सहित लोक सुविधायें
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट- 2.1

₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों विनियोग की विवरणी

(संदर्भ कंडिका 2.4.1 पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुमान विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		राजस्व			
1	1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	651.93	228.82	35
2	2	पशुपालन विभाग	139.61	31.53	23
3	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	31.34	10.80	34
4	12	वित्त विभाग	47.07	10.06	21
5	20	स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	1094.23	277.93	25
6	23	उद्योग विभाग	353.13	157.41	45
7	26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	851.70	193.07	23
8	27	विधि विभाग	207.96	44.23	21
9	35	योजना एवं विकास विभाग	499.32	291.79	58
10	39	आपदा प्रबंधन विभाग	487.61	266.88	55
11	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	328.98	79.15	24
12	42	ग्रामीण विकास विभाग	836.59	217.00	26
13	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	94.94	40.29	42
14	45	सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	67.37	54.65	81
15	47	परिवहन विभाग	823.75	331.74	40
16	48	नगर विकास विभाग	359.55	94.66	26
17	49	जल संसाधन विभाग	308.42	83.77	27
18	50	लघु सिचाई विभाग	81.05	19.04	23
19	51	कल्याण विभाग	935.19	309.14	33
20	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	72.26	38.38	53
21	54	डेयरी	82.70	21.88	26
22	56	पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	1412.40	310.24	22
23	58	माध्यमिक शिक्षा	675.25	199.75	30
24	59	प्राथमिक एवं जन शिक्षा	3841.91	802.81	21
25	60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	825.19	230.47	28
		पूँजी			
26	3	भवन निर्माण विभाग	75.70	26.12	35
27	10	ऊर्जा विभाग	1295.00	1130.05	87
28	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.00	10.00	67
29	20	स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	341.25	177.72	52
30	30	अल्पसंख्यक कल्याण	160.43	89.97	56
31	41	पथ निर्माण विभाग	1696.60	899.94	53

परिशिष्ट - 2.1 क्रमशः...

32	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	85.48	52.27	61
33	47	परिवहन विभाग	15.63	12.44	80
34	48	नगर विकास विभाग	1003.56	816.06	81
35	49	जल संसाधन विभाग	911.30	714.70	78
36	50	लघु सिचाई विभाग	656.70	438.93	67
37	51	कल्याण विभाग	168.10	34.36	20
38	58	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	35.00	18.00	51
कुल			**21569.20**	**8766.05**	

परिशिष्ट- 2.2

वर्ष 2011-12 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹ 10 करोड. एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण

संदर्भ कंडिका 2.4.1 पृष्ठ 41)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
1	1-कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401-00-796-19	25.20	25.16	सूचना अप्राप्त
2		2401-00-796-28	45.90	45.90	सूचना अप्राप्त
3		2401-00-796-59	10.00	10.00	सूचना अप्राप्त
4	10 ऊर्जा विभाग	2801-01-796-02	38.50	38.50	सूचना अप्राप्त
5		2801-01-800-02	61.60	61.60	सूचना अप्राप्त
6		2801-80-800-05	130.00	130.00	सूचना अप्राप्त
7		2801-80-800-09	10.00	10.00	सूचना अप्राप्त
8		6801-00-789-03	13.50	13.26	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
9		6801-00-796-03	52.50	51.55	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
10		6801-00-800-01	36.40	15.54	निधि का अधिक प्रावधान
11		6801-00-800-03	84.00	82.50	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण
12		6801-00-789-07	40.50	40.50	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
13		6801-00-796-07	157.50	157.50	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
14		6801-00-800	150.00	150.00	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
15		6801-00-800-07	252.00	252.00	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से रोड मैप अप्राप्त
16		6801-00-800-12	350.00	350.00	तकनीकि स्वीकृत प्राक्कलन एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से डी पी आर अप्राप्त
17	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-08	17.00	17.00	सूचना अप्राप्त
18		4210-02-103-07	12.00	11.65	सूचना अप्राप्त
19		4210-02-796-35	15.00	14.87	सूचना अप्राप्त
20		4210-02-796-36	15.00	12.39	सूचना अप्राप्त
21	22 गृह विभाग	2055-00-115-67	201.65	85.99	सूचना अप्राप्त
22	23 उद्योग विभाग	2851-00-796-29	14.00	12.22	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
23		2852-80-102-03.	14.00	12.00	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
24		2852-80-796-10	46.00	42.17	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन
25		2852-80-796-52	15.00	12.83	गलत प्राथमिक इकाई में निधि का आवंटन

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
26	35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-796-11	51.73	50.00	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
27		2235-02-102-01	54.44	43.79	सूचना अप्राप्त
28		2235-02-796-01	54.00	40.90	सूचना अप्राप्त
29		3454-02-800-11	84.33	84.33	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
30		3454-02-800-15	12.50	12.50	योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण
31	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-102-02	105.00	32.39	सूचना अप्राप्त
32		2245-02-101-02	25.50	24.72	सूचना अप्राप्त
33		2245-05-101-05	204.32	102.16	सूचना अप्राप्त
34		2245-05-101-06	68.10	34.05	सूचना अप्राप्त
35		2245-01-101-01.	10.00	10.00	जिलों से माँग अप्राप्त
36		2245-01-101-02	20.00	20.00	जिलों से माँग अप्राप्त
37	41 पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-01	29.00	16.29	सूचना अप्राप्त
38		5054-03-337-01	444.00	326.96	सूचना अप्राप्त
39		5054-03-796-01	865.60	458.83	सूचना अप्राप्त
40		5054-03-337-08	85.00	44.45	सूचना अप्राप्त
41		5054-03-796-03	45.00	32.11	सूचना अप्राप्त
42		5054-03-796-08	215.00	157.47	सूचना अप्राप्त
43	42 ग्रामीण विकास विभाग	2515-06-796-01	34.43	22.08	सूचना अप्राप्त
44		2515-00-800-04.	21.39	15.63	सूचना अप्राप्त
45		2505-01-702-02	54.00	12.48	सूचना अप्राप्त
46		2505-01-796-02	69.00	24.78	सूचना अप्राप्त
47		2505-01-796-04	71.00	11.46	सूचना अप्राप्त
48		2515-00-102-29	14.40	14.35	सूचना अप्राप्त
49		2515-00-796-29	18.40	18.05	सूचना अप्राप्त
50		4515-00-103-10	118.09	13.38	सूचना अप्राप्त
51		4515-00-796-10	159.78	19.24	सूचना अप्राप्त
52	47 परिवहन विभाग	3075-60-101-02	80.00	80.00	सूचना अप्राप्त
53		3075-60-796-02	120.00	120.00	सूचना अप्राप्त
54		3055-00-109-01	62.23	26.38	सूचना अप्राप्त
55		3075-60-796-01	332.15	100.00	योजना उदव्यय में कटौती
56	48 नगर विकास विभाग	2217-80-191-29.	10.00	10.00	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त
57		2217-80-192-08	25.95	25.95	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त
58		2217-80-193-08.	10.00	10.00	केन्द्र सरकार से निधि अप्राप्त केन्द्रांश
59		4217-60-190-31	16.35	15.61	केन्द्रांश का कम आवंटन
60		4217-60-191-19	20.00	20.00	योजना उदव्यय में कटौती
61		4217-60-191-20	20.00	20.00	योजना उदव्यय में कटौती

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
62	48 नगर विकास विभाग	4217-60-190-21	47.00	47.00	सूचना अप्राप्त
63		4217-60-190-07	47.00	47.00	सूचना अप्राप्त
64		4217-60-796-30	100.00	94.37	योजना उदव्यय में कटौती
65		4217-60-796-36	110.00	79.94	योजना उदव्यय में कटौती
66		4217-60-191-14	463.00	375.00	योजना उदव्यय में कटौती
67		4217-60-191-23	70.00	51.83	केन्द्र सरकार द्वारा योजना की संस्वीकृति अप्राप्त
68		4217-60-789-33	20.00	10.49	योजना की संस्वीकृति अप्राप्त
69	49 जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	120.81	21.46	सूचना अप्राप्त
70		2700-03-001-06	53.82	12.66	सूचना अप्राप्त
71		2700-03-001-07	89.88	15.76	सूचना अप्राप्त
72		2700-03-001-08	24.67	24.67	सूचना अप्राप्त
73		4700-80-796-10	300.00	241.07	सूचना अप्राप्त
74		4701-789-69	14.10	14.10	सूचना अप्राप्त
75		4701-80-796-73	90.90	86.31	सूचना अप्राप्त
76		4700-80-789-10	240.00	240.00	सूचना अप्राप्त
77		4701-80-800-70	31.40	31.40	सूचना अप्राप्त
78	50 लघु सिचाई विभाग	4702-00-101-28	25.00	20.15	सूचना अप्राप्त
79		4702-00-101-33	250.00	186.71	सूचना अप्राप्त
80		4702-00-796-28	25.00	25.00	सूचना अप्राप्त
81		4702-00-101-30	250.00	133.41	सूचना अप्राप्त
82		4702-00-789-29	37.70	37.70	सूचना अप्राप्त
83	51 कल्याण विभाग	2225-01-796-01	207.34	115.48	सूचना अप्राप्त
84		4225-02-796-08	125.40	12.76	सूचना अप्राप्त
85	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-109-01	108.49	35.94	सूचना अप्राप्त
86		2515-00-196-03	11.20	11.20	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
87		2515-00-101-15	142.45	70.03	योजना उदव्यय में कटौती
88		2515-00-197-03.	11.20	11.20	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
89		2215-00-198-02	21.00	21.00	केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृति अप्राप्त/अविमुक्त
90		2215-00-198-03	33.59	33.59	पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती
91		2215-00-789-15	51.69	16.25	योजना उदव्यय में कटौती
92		2215-00-796-15	149.42	72.65	योजना उदव्यय में कटौती
93		2215-00-796-28	80.00	15.00	निधि का अधिक प्रावधान
94	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	366.80	87.18	सूचना अप्राप्त
95		2202-02-109-35	10.53	10.53	सूचना अप्राप्त
96		2202-02-109-36	15.44	15.44	सूचना अप्राप्त

परिशिष्ट - 2.2 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	बचत राशि (₹ करोड. में)	विनियोग लेखे के अनुसार विभागों द्वारा दिये गये कारण
97	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-796-35	11.60	11.60	सूचना अप्राप्त
98		2202-02-796-36	10.56	10.56	सूचना अप्राप्त
99		4202-01-796-03.	11.00	11.00	सूचना अप्राप्त
100	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	2095.13	283.93	निधि का अधिक प्रावधान
101		2202-01-101-03	167.10	71.97	सूचना अप्राप्त
102		2202-01-101-05 (सी.एस.एस)	78.00	59.45	सूचना अप्राप्त
103		2202-01-101-05 (योजना)	27.90	27.18	सूचना अप्राप्त
104		2202-01-789-03 (सी.एस.एस)	68.70	51.10	सूचना अप्राप्त
105		2202-01-789-03 (योजना)	22.90	12.58	सूचना अप्राप्त
106		2202-01-796-04	157.20	56.44	सूचना अप्राप्त
107		2202-01-796-05 (सी.एस.एस)	83.85	56.59	सूचना अप्राप्त
108		2202-01-796-27	40.00	18.88	सूचना अप्राप्त
109		2202-01-789-25	72.00	72.00	सूचना अप्राप्त
110		2202-01-796-05 (योजना)	26.00	26.00	सूचना अप्राप्त
111	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-102-51	81.00	19.14	निधि का अधिक प्रावधान
112		2235-02-796-51	90.00	22.15	सूचना अप्राप्त
113		2235-02-103-59	47.70	47.70	निधि का आहरण नहीं
114		2235-02-796-59	60.30	60.30	निधि का आहरण नहीं
		कुल	**12333.71**	**6968.32**	

परिशिष्ट- 2.3

पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ कंडिका 2.4.4 पृष्ठ 43)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़.में)
2001-02	3	भवन निर्माण विभाग	*
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	**
2001-02	32	विधायिका	0.04
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00
2002-03	13	ब्याज संदाय	472.46
2002-03	14	ऋण की वापसी/अदायगी	761.96
2002-03	32	विधायिका	0.08
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63
2003-04	13	ब्याज संदाय	191.28
2003-04	14	ऋण की वापसी/अदायगी	674.72
2003-04	39	सहायक और पुर्नवास विभाग	61.33
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	13	ब्याज संदाय	365.80
2004-05	14	ऋण की वापसी/अदायगी	133.44
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49
2004-05	39	सहायक और पुनर्नवास विभाग	69.34
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94
2005-06	13	ब्याज संदाय	492.53
2005-06	29	खनन एवं भूतत्व विभाग	#
2006-07	13	ब्याज संदाय	833.58
2006-07	14	ऋण की वापसी/अदायगी	412.28
2006-07	38	निबंधन विभाग	$
2007-08	14	ऋण की वापसी/अदायगी	229.64
2007-08	15	पेंशन	104.80
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13
2008-09	14	ऋण की वापसी/अदायगी	91.76
2009-10	14	ऋण की वापसी/अदायगी	116.71
2010-11	13	ब्याज संदाय	67.35
2010-11	15	पेंशन	250.95
2010-11	32	विधायिका	0.10
कुल			**8120.63**

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

* नियमितीकरण आवश्यक नहीं क्योंकि यह विनियोग अधिनियम एवं माँग अनुसूची के पूँजीगत खण्ड के प्रावधानों के अधीन अन्तर्निहित की गई जो भूलवश राजस्व खण्ड में सन्निहित कर दी गई थी।

* केवल ₹ 8,807 आधिक्य राशि थी।

@ केवल ₹ 1,072 आधिक्य राशि थी।

\# केवल ₹ 49,670 आधिक्य राशि थी।

$ केवल ₹ 81,665 आधिक्य राशि थी।

परिशिष्ट 2.4

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ कंडिका 2.4.5; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	क - राजस्व (भारित)				
1	5 राज्यपाल सचिवालय	618.85	589.98	28.87	87.76
2	13 ब्याज संदाय	239486.66	226707.67	12778.99	925.68
3	16 राष्ट्रीय बचत	255.62	237.18	18.44	21.53
4	34 झारखण्ड लोक सेवा आयोग	484.20	438.67	45.53	130.00
5	28 झारखण्ड का उच्च न्यायालय	3747.54	3686.28	61.26	469.82
कुल राजस्व (भारित)		**244592.87**	**231659.78**	**12933.09**	**1634.79**
	राजस्व (दत्तमत)				
6	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	62560.35	42310.54	20249.81	2632.17
7	2-पशुपालन विभाग	13098.95	10809.30	2289.65	862.26
8	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2111.29	2054.57	56.72	1022.85
9	10-ऊर्जा विभाग	107418.31	87688.73	19729.58	280.50
10	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	1742.03	1639.13	102.90	136.85
11	12 वित्त विभाग	4245.70	3701.09	544.61	461.46
12	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5617.83	5073.16	544.67	580.05
13	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	24696.82	22020.28	2676.54	2543.72
14	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	108602.23	81629.79	26972.44	820.85
15	23- उद्योग विभाग	22690.45	19572.08	3118.37	12622.94
16	25 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	384.09	151.85	232.24	10.65
17	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	82104.43	65862.58	16241.85	3065.35
18	27 विधि विभाग	17694.46	16372.47	1321.99	3101.37
19	29 खनन एवं भूतत्व विभाग	2626.40	1848.42	777.98	43.83
20	33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1371.76	1229.41	142.35	180.34
21	35- योजना एवं विकास विभाग	23061.20	20753.63	2307.57	26870.98
22	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	19099.80	18681.59	418.21	288.97
23	38 निबंधन विभाग	1830.94	1136.34	694.60	253.00
24	39 आपदा प्रबंधन विभाग	36260.89	22072.42	14188.47	12500.00
25	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31785.13	24982.22	6802.91	1112.52
26	42 ग्रामीण विकास विभाग	83637.42	61958.94	21678.48	21.52
27	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7129.24	5465.16	1664.08	2364.49
28	45 सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	6180.50	1272.18	4908.32	556.29
29	46 पर्यटन विभाग	878.50	802.09	76.41	160.75
30	47- परिवहन विभाग	51365.64	49200.30	2165.34	31009.00
31	48 नगर विकास विभाग	30702.36	26488.65	4213.71	5252.52
32	49- जल संसाधन विभाग	30753.24	22464.88	8288.36	88.89
33	50 लघु सिचाई विभाग	8090.96	6201.72	1889.24	14.40
34	51- कल्याण विभाग	75097.65	62604.86	12492.79	18421.56
35	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	6483.41	3388.45	3094.96	743.02
36	54 डेयरी	8243.19	6081.93	2161.26	26.50
37	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	127229.76	110216.29	17013.47	14010.18
38	58 माध्यमिक शिक्षा	62916.37	47549.82	15366.55	4608.39

परिशिष्ट - 2.4 क्रमशः...

39	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	80557.11	59472.31	21084.80	1962.05
कुल राजस्व (दत्तमत)		**1148268.41**	**912757.18**	**235511.23**	**148630.22**
	कुल राजस्व	**1392861.28**	**1144416.96**	**248444.32**	**150265.01**
	पूंजी (दत्तमत)				
40	22 गृह विभाग	11835.20	10623.53	1211.67	342.10
41	30 अल्पसंख्यक कल्याण	10850.11	7045.65	3804.46	5192.93
42	41- पथ निर्माण विभाग	169160.00	79666.21	89493.79	500.00
43	43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7567.00	3320.45	4246.55	980.86
44	46 पर्यटन विभाग	1890.00	1842.20	47.80	87.00
45	47 परिवहन विभाग	1475.00	318.96	1156.04	88.00
कुल पूंजी (दत्तमत)		**202777.31**	**102817.00**	**99960.31**	**7190.89**
कुल पूंजी		**202777.31**	**102817.00**	**99960.31**	**7190.89**
सकल योग		**1595638.59**	**1247233.96**	**348404.63**	**157455.90**

परिशिष्ट - 2.5
निधि का अधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनयोग
(संदर्भः कंडिका - 2.4.6; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनयोग	कमी पुनर्विनयोग	बचत (-)/ अधिक्य (+)
1	10 ऊर्जा विभाग	3451-00-090-13	2	1.5	-5.72
2	11 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-04	0.65	0	-13.26
3	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040-00-101-02	25	30	-45.13
4	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2251-00-090-07	22.39	0	-4.62
5	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-04	118.39	0	-21.07
6	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-80-102-01	250	0	-2.8
7	41 पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-02	8	0	-21.65
8		3054-80-001-08	3	0	-6.31
9	46 पर्यटन विभाग	3452-80-001-01	1.5	8	-1.11
10	56 पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-196-01	280	0	-207.67
11		2515-198-01	839.75	0	-165.59
			1550.68	**39.5**	**-494.93**
12	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-05	0	236.61	188.08
13		2235-03-101-06	0	150.12	15.61
14		2235-03-796-04	0	53.38	66.72
15		2235-03-796-05	0	747.48	99.63
16	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-02	9.05	90.2	2.25
17		2215-01-101-01	0	9.65	11.6
18		2215-01-102-02	0.2	2	58.62
19		2215-02-105-01	0	25	4.2
20	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3451-00-090-11	0	1.9	4.03
			9.25	**1316.34**	**450.74**
21	13 ब्याज संदाय	2049-60-701-01	285.00	0	13.46
22	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2235-03-101-03	386.72	0	42.69
23		2235-03-489-03	50.00	0	9.48
24		2235-03-796-03	973.26	0	46.95
25	5 राज्यपाल सचिवालय	2012-03-090-01	5.57	0	34.62
			1700.55	**0**	**147.20**

परिशिष्ट- 2.6

वास्तविक बचत से अधिक राशि (प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख अधिक)

(संदर्भ कंडिका 2.4.7 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विर्निमाण	बचत	अस्मर्पित राशि	आधिक्य आपूर्तित राशि
	राजस्व दत्तमत				
1	***5** राज्यपाल सचिवालय*	*7.07*	*1.17*	*1.31*	*0.14*
	कुल राजस्व दत्तमत	**7.07**	**1.17**	**1.31**	**0.14**
	राजस्व मतदेय				
2	10 ऊर्जा विभाग	1076.99	200.10	200.63	0.53
3	23 उद्योग विभाग	353.13	157.41	157.91	0.50
4	27 विधि विभाग	207.96	44.23	44.54	0.31
5	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	193.89	7.07	7.24	0.17
	कुल राजस्व मतदेय	**1831.97**	**408.81**	**410.32**	**1.51**
	कुल राजस्व	**1839.04**	**409.98**	**411.63**	**1.65**
	पूँजी मतदेय				
6	41 पथ निर्माण विभाग	1696.60	899.94	912.14	12.20
	कुल पूँजी मतदेय	**1696.60**	**899.94**	**912.14**	**12.20**
	सकल कुल(राजस्व एवं पूँजी)	**3535.64**	**1309.92**	**1323.77**	**13.85**

परिशिष्ट- 2.7

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी

(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.या	बचत	अभ्यर्पण	बचत को अभ्यर्पित नहीं हुई
1	2	3	4	5
	राजस्व			
1	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	228.82	48.62	180.20
2	2 पशुपालन विभाग	31.52	8.04	23.48
3	13 ब्याज संदाय	137.05	33.12	103.93
4	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	168.01	139.23	28.78
5	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93	238.21	39.72
6	22 गृह विभाग	256.17	188.44	67.73
7	26 श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	193.07	188.59	4.48
8	29 खनन एवं भूतत्व विभाग	8.22	2.46	5.76
9	35 योजना एवं विकास विभाग	291.79	281.62	10.17
10	38 निबंधन विभाग	9.48	3.45	6.03
11	39 आपदा प्रबंधन विभाग	266.88	126.23	140.65
12	40 राजस्व एव भूमि सुधार विभाग	79.15	75.35	3.80
13	41 पथ निर्माण विभाग	18.02	10.56	7.46
14	42 ग्रामीण विकास विभाग	217.00	188.14	28.86
15	47 परिवहन विभाग	331.74	330.35	1.39
16	48 शहरी विकास विभाग	94.66	90.03	4.63
17	49 जल संसाधन विभाग	83.77	75.56	8.21
18	50 लघु सिंचाई विभाग	19.04	17.02	2.02
19	51 कल्याण विभाग	309.14	67.81	241.33
20	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	38.38	36.28	2.10
21	56 पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	310.24	299.17	11.07
22	57 आवास विभाग	1.55	0.23	1.32
23	58 माध्यमिक शिक्षा	199.75	150.10	49.65
24	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	802.81	164.14	638.67
25	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	230.47	202.37	28.10
	पूँजी			
1	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	1.00	0.00	1.00
2	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	177.72	172.41	5.31
3	22 गृह विभाग	15.54	11.79	3.75
4	30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	89.97	80.48	9.49
5	42 ग्रामीण विकास विभाग	47.71	40.77	6.94
6	46 पर्यटन विभाग	1.35	0.75	0.60
7	48 शहरी विकास विभाग	816.06	674.20	141.86
8	49 जल संसाधन विभाग	714.70	620.80	93.90
9	50 लघु सिंचाई विभाग	438.93	417.22	21.71
10	51 कल्याण विभाग	34.36	17.26	17.10
11	55 ग्रामीण कार्य विभाग	48.33	33.96	14.37
	कुल	**6990.33**	**5034.76**	**1955.57**

परिशिष्ट- 2.8

30 और 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की अभ्यर्पित राशि के मामले

(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	लेखा -शीर्ष	राशि
1	10 ऊर्जा विभाग	2801-80-800-07	97.50
2		2801-01-796-02	28.88
3		2801-01-800-02	46.20
4		6801-00-800-12	350.00
5		6801-00-800-05	150.00
6		6801-00-789-03	13.26
7		6801-00-796-03	51.56
8		6801-00-800-03	82.50
9		6801-00-789-07	40.50
10		6801-00-796-07	157.50
11		6801-00-800-07	252.00
12		6801-00-800-01	15.54
13	13 ब्याज संदाय	2049-01-200-02	11.85
14	14 ऋण की वापसी/अदायगी	6003-00-109-08	10.81
15	18 खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-796-02	11.87
16		3456-00-796-19	14.25
17	19 वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-105-38	12.15
18	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-08	17.00
19		2211-00-101-01	122.64
20		4210-02-796-48	24.10
21		4210-02-796-36	12.39
22		4210-02-796-35	14.88
23		4210-02-110-31	11.65
24	21 उच्च शिक्षा	2202-03-102-15	13.68
25	22 गृह विभाग	2055-00-109-01	96.22
26		2055-00-104-02	16.05
27	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-03-101-02	13.52
28	27 विधि विभाग	2014-00-105-05	16.52
29	30 अल्पसंख्यक कल्याण	4225-80-796-12	17.32
30		4225-80-796-08	46.46
31	35 योजना एवं विकास विभाग	2053-00-800-15	12.50
32		2053-00-800-11	84.33
33		2053-00-796-11	50.00
34		2235-02-796-01	39.18
35		2235-02-102-01	43.79
36	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-102-02	13.64
37	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-02	24.73
38		2245-01-102-02	32.40

परिशिष्ट - 2.8 क्रमशः...

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	लेखा -शीर्ष	राशि
39	39 आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-02	20.00
40	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-15	11.05
41	42 ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-800-01	14.79
42		2501-06-796-01	18.83
43		2505-02-796-04	11.46
44		2505-01-796-02	24.78
45		2505-01-702-02	12.48
46		2515-00-796-29	18.05
47		2515-00-102-29	14.35
48		4515-00-796-10	18.28
49		4515-00-103-10	11.56
50	47 परिवहन विभाग	3055-00-190-01	26.38
51		3075-60-796-02	120.00
52		3075-60-101-02	80.00
53	48 नगर विकास विभाग	2217-80-193-08	10.00
54		2217-80-192-08	25.96
55		2217-80-191-29	10.00
56		4217-60-796-36	14.94
57		4217-60-796-30	38.32
58		4217-60-789-33	10.49
59		4217-60-190-31	15.61
60	49 जल संसाधन विभाग	4701-80-796-73	47.26
61		4700-80-796-10	26.88
62		2701-03-001-08	24.67
63		2701-03-001-07	12.23
64		2701-03-001-06	11.62
65		2700-01-001-02	19.35
66	50 लघु सिचाई विभाग	4702-00-796-30	32.22
67		4702-00-101-33	16.69
68	56 पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग	2515-00-001-03	35.28
69		2515-00-198-02	21.00
70		2515-00-198-03	25.19
71	58 माध्यमिक शिक्षा	2202-02-109-01	40.39
72		4202-01-796-03	11.00
73	59 प्राथमिक एवं जन शिक्षा	2202-01-101-01	157.60
74	60 समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-796-59	60.30
75		2235-02-796-51	13.21
76		2235-02-103-59	47.70
77		2235-02-102-51	19.15
78		2236-02-789-02	13.64
79		2236-02-101-02	20.75
कुल			**3252.83**

परिशिष्ट- 2.9

वर्ष के अंत में व्यय की वेग

(संदर्भ कंडिका 2.4.9 पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	लेखे शीर्ष	जनवरी से मार्च 2012 तक व्यय	मार्च 2012 में व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत सकल	
						जनवरी से मार्च 2012	मार्च 2012
1	17 वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	2040	26.15	20.48	50.2	52	41
2	37 राजभाषा विभाग	2053	237.77	190.32	331.57	72	57
3	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2204	22.28	19.74	29.48	76	67
4	24 सूचना और जन संपर्क विभाग	2220	30.52	25.00	47.66	64	52
5	51 कल्याण विभाग	2225	397.79	336.03	623.99	64	54
6	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	88.97	78.26	127.44	70	61
7	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2401	211.34	165.14	303.7	70	54
8	54 डेयरी	2404	50.32	35.12	60.82	83	58
9	53 मत्यस्य	2405	26.61	22.61	37.56	71	60
10	1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	2415	60.83	34.69	84.75	72	41
11	9 सहकारिता विभाग	2425	104.06	96.16	138.48	75	69
12	42 ग्रामीण विकास विभाग	2505	122.01	95.23	232.83	52	41
13	42 ग्रामीण विकास विभाग	2515	889.36	778.33	1389.17	64	56
14	10 ऊर्जा विभाग	2810	35.00	35.00	35.00	100	100
15	23 उद्योग विभाग	2851	66.24	43.61	107.46	62	41
16	23 उद्योग विभाग	2852	57.8	54.64	86.34	67	63
17	8 नागर विमानन विभाग	3053	66.47	66.43	66.67	100	100
18	47 परिवहन विभाग	3075	450.25	450.25	450.25	100	100
19	22 गृह विभाग	4055	93.67	60.91	105.19	89	58
20	52 कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	4202	55.53	48.07	75.98	73	63
21	20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4210	101.72	70.22	163.53	62	43
22	48 नगर विकास विभाग	4217	162.62	160.86	176.09	92	91
23	30 अल्पसंख्यक कल्याण	4225	193.26	169.07	204.2	95	83
24	9 सहकारिता विभाग	4425	20.03	20.03	26.08	77	77
25	49 जल संसाधन विभाग	4701	64.75	49.35	85.97	75	57
26	41 पथ निर्माण विभाग	5054	532.05	359.17	796.66	67	45

परिशिष्ट- 2.10

लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत कार्यक्रम निधियों का बजट

(संदर्भ कंडिका 2.6 पृष्ठ 46)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना/ गैर योजना/ सी एस एस/ सी पी एस	वर्गीकरण	उप-शीर्ष/उद्देश्य	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)
1	1	योजना	2401-800-09	विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास	109-किसानों का प्रशिक्षण एवं विस्तारीकरण	6.65
2	10	योजना	2801-01-800-10	ग्राम विद्युतीकरण	001- प्रशासन एवं निर्देशन के अर्न्तगत 06-ग्राम विद्युतीकरण	5.60
3	10	योजना	2801-80-800-07	परामर्शदाता एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) जेएसईबी के अनुगामी कंपनी को सहायता के लिए अनुदान	004-शोध एवं विकास	130.00
4	10	योजना	2801-80-800-08	परामर्शदाता एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) ऊर्जा दक्षता संरक्षण/परामर्शदाता	004- शोध एवं विकास	4.50
5	19	योजना	2406-01-800-13	नगर विकास एवं सडक किनारे वृक्षारोपण	102-सामाजिक एवं वाणिज्यिक फार्म	17.97
6	20	योजना	2210-03-800-14	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	110- औषधालय	5.00
7	20	योजना	2210-03-800-15	एन आर एच एम (राज्यांश)	110- औषधालय	90.00
8	20	योजना	4210-02-800-03	आयुष कार्यक्रम हेतु भवन निर्माण	110- औषधालय	0.34
9	42	योजना	2053-00-800-10	मुख्यमंत्री विकास योजना	094- अन्य स्थापना	24.64
10	42	योजना	2501-06-800-01	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101-एस जी एस वाइ	21.39
11	42	योजना	2501-06-800-04	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	9.60
12	42	योजना	2501-06-800-05	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	19.80
13	42	योजना	2501-06-800-06	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	101- एस जी एस वाइ	0.48
14	43	योजना	2203-00-800-46	राज्य शिक्षा परिषद्	103- आई टी आई	0.03
15	58	योजना	2202-02-800-04	सैनिक स्कूल, तिलैया	110- गैर-सरकारी विद्यालय	0.42
कुल						**336.42**

परिशिष्ट- 3.1

चयनित विभागों में बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए सी विपत्र)

(संदर्भ कंडिका 3.1 एवं 3.2 पृष्ठ 50 एवं 51)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मानव संसाधन विकास		गृह		ग्रामीण विकास		चयनित विभागों का कुल	
	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि	ए सी विपत्र की राशि	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	(2+4+6)	(3+5+7)
2009-10	73.24 (94)	70.30 (87)	156.50 (291)	90.00 (210)	145.81 (149)	88.30 (140)	375.55 (534)	248.60 (437)
2010-11	54.14 (54)	43.97 (49)	68.96 (97)	15.68 (60)	183.46 (206)	136.68 (192)	306.56 (357)	196.33 (301)
2011-12	678.88 (43)	665.50 (37)	242.05 (79)	223.15 (66)	128.23 (106)	123.14 (102)	1049.16 (228)	1011.79 (205)
कुल	**806.26 (191)**	**779.77 (173)**	**467.51 (467)**	**328.83 (336)**	**457.50 (461)**	**348.12 (434)**	**1731.27 (1119)**	**1456.72 (943)**

स्रोत: वी.एल.सी.डाटाबेस (10 सितम्बर, 2012 को बकाया स्थिति)

** कोष्टक में आँकड़े ए.सी. विपत्र की संख्या को प्रदर्शित करता है।*

परिशिष्ट- 3.2

वर्ष 2009-12 के दौरान ए सी विपत्र (नमूना जॉच) से निधियों का आहरण

(संदर्भ कंडिका 3.3 एवं 3.7 पृष्ठ 52 एवं 55)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम	विभाग	क्रम सं.	उद्देश्य/योजना	विपत्रों की संख्या	राशि
फ्लैगशीप कार्यक्रम	**मानव संसाधन विकास**	1	सर्व शिक्षा अभियान*	6	607.00
	मानव संसाधन विकास	2	मध्याह्न भोजन योजना	24	47.79
	मानव संसाधन विकास	3	साक्षर भारत कार्यक्रम	1	4.00
	गृह	4	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	15	274.96
कुल (क)				**46**	**933.75**
राज्य योजना	**मानव संसाधन विकास**	5	विद्यालय स्वास्थ्य एंव स्वच्छता कार्यक्रम	1	0.03
	ग्रामीण विकास	6	एम एल ए - एल ए डी योजना	54	99.76
कुल (ख)				**55**	**99.79**
अन्य योजना/पूँजीगत व्यय	**ग्रामीण विकास**	7	इन्दिरा आवास योजना, हरिजन बस्ती इत्यादि के अर्न्तगत निर्माण कराये गये मकानों का मरम्मत,	3	0.43
	ग्रामीण विकास	8	प्रखण्डों के लिये वाहनों की खरीद	3	0.60
	गृह	9	कारागार में निर्माण कार्य एवं पुलिस बल को बुनियादी सुविधा प्रदान करने हेतु योजना	87	32.31
	मानव संसाधन विकास	10	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूलभूत ढ़ाँचा के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु भवन निर्माण	9	12.88
	मानव संसाधन विकास	11	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सामान्य एवं पिछडी जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें	3	8.00
	मानव संसाधन विकास	12	राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय का स्थापना लागत	3	25.00
	मानव संसाधन विकास	13	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को पुरस्कार	3	0.04
	मानव संसाधन विकास	14	शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु संगोष्ठी एवं परिसंवाद	1	0.01
	ग्रामीण विकास	15	पंचायत भवन का निर्माण	3	0.14
	ग्रामीण विकास	16	प्रखण्ड भवन का मरम्मत एवं निर्माण	4	4.05
कुल (ग)				**119**	**83.46**
कोषागारों द्वारा ए सी विपत्र के रूप में अंकित किये गये अनुदान	**मानव संसाधन विकास**	17	*निर्धनता सह मेघा छात्रवृति योजना*	1	0.07
	ग्रामीण विकास	18	आदर्श ग्राम योजना	6	9.03
	ग्रामीण विकास	19	बी आर एफ जी, आइ ए पी, विद्युतीकरण	6	41.48
	ग्रामीण विकास	20	जिला परिषद् को वेतन	1	0.09
कुल (घ)				**14**	**50.67**
आकस्मिक प्रकृति	**ग्रामीण विकास**	21	पंचायत चुनाव	3	2.22

परिशिष्ट - 3.2 क्रमशः...

के व्यय	**गृह**	22	विभिन्न पुलिस थानों को स्थायी अग्रिम	2	0.08
	गृह	23	निर्वाचन कार्य	2	0.14
	गृह	24	बाजार समिति मे सी आर पी एफ के ठहराव हेतु किराया व्यय	1	0.01
	गृह	25	दूरभाष विपत्र एवं वाहन तेल व्यय	3	0.04
कुल (ड.)				**11**	**2.49**
कुल योग				**245**	**1170.16**

मानव संसाधन विकास: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा एन.आर.ई.पी.(विशेष शाखा)

* कस्तुरबा गाँधी बालमिकि विद्यालय (के.जी.बी.भी.) तथा प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा(एन पी ई जी ई एल)

परिशिष्ट- 3.3

आवंटन को व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का नाम	उद्देश्य	विपत्र संख्या	आहरण की तिथि	राशि	आ.एवं सं.अ. द्वारा संवितरण		आ. एवं सं. अ. के पास शेष राशि	संवितरित राशि में से क्रियान्वयन अभिकरण (क्रि.अ.) द्वारा वापस की गई राशि	क्रि.अ. द्वारा प्राप्त राशि में से अनुपयोगित राशि	क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा न्यून उपयोगिताओं के कारण
					तिथि	राशि				
जि. शि. अ., धनबाद	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूलभूत ढाँचा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए भवन निर्माण	78/09-10	31.03.10	13.50	मई 10 से जुलाई 10	13.50	शून्य			जमीन की अनुपलब्धता एवं ग्रा. शि. स. द्वारा पुराने आकलित दर पर वर्ग कक्ष का निर्माण से इन्कार
		76/09-10	31.03.10	423.00	मई 10 से जुलाई 10	229.50	193.50	76.50	67.50	
		77/09-10	31.03.10	157.50	मई 10 से जुलाई 10	157.50	शून्य			
जि.शि. अ., धनबाद	मध्याह्न भोजन के तहत् भंडार सह किचन शेड का निर्माण	119/11-12	31.03.12	193.20	जून 12	190.80	2.40			कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।
जि. शि. अ., पलामू	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूलभूत ढाँचा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए भवन निर्माण	276/09-10	03.03.10	13.35	अप्रैल 10 एवं मई 10	13.35	शून्य	4.45	151.30	जमीन की अनुपलब्धता एवं बढ़ती मूल्य इत्यादि के कारण
		277/09-10	31.03.10	445.00	अप्रैल 10 एवं मई 10	445.00	शून्य			
जि. शि. अ., गोड्डा	मध्याह्न भोजन	88/11-12	31.03.12	118.44	संवितरित नहीं की गई	शून्य	118.44			जि. शि. अधी. द्वारा सम्पूर्ण राशि बैंक खातों में रखा गया ।
	मध्याह्न भोजन के तहत् भंडार सह किचन शेड का निर्माण	86/11-12	31.03.12	51.78	संवितरित नहीं की गई	शून्य	51.78			
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए पुरस्कार	83/11-12	29.03.12	0.55	संवितरित नहीं की गई	शून्य	0.55			
	शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु परिसंवाद एवं शिक्षा गोष्ठी	81/11-12	29.03.12	1.00	संवितरित नहीं की गई	शून्य	1.00			
कुल				1417.32		1049.65	367.67	80.95	218.80	

परिशिष्ट- 3.4
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से निधियों के आहरण की पुनरावृति
(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	विपत्र आहरण की अवधि	आहरित विपत्र की संख्या	राशि
अ.	मानव संसाधन विकास विभाग			
1	जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद	31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	12	2124.71
2	जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा	12 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2012	12	1019.26
3	जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा	30 मार्च 2010 से 03 मार्च 2011	7	469.41
4	जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू	03 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011	5	1985.13
5	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राँची	02 अक्टूबर 2011 से 12 मार्च 2012	10	61900.00
6	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राँची	13 अक्टूबर 2009 से 31 मार्च 2012	4	2507.00
	कुल(अ)		**50**	**70005.51**
ब.	गृह विभाग			
1	पुलिस उपाधीक्षक, लोहरदगा	24 नवम्बर 2009 से 22 नवम्बर 2011	9	113.11
2	पुलिस उपाधीक्षक, राँची	12 नवम्बर 2009 से 04 नवम्बर 2011	10	66.28
3	आकलन अधिकारी, आर.डी.एस., सरायकेला	23 फरवरी 2010 से 05 मार्च 2010	2	99.61
4	महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण एवं प्रावधानिकीकरण, राँची	06 फरवरी 2010 से 14 मार्च 2012	15	27495.73
5	अधीक्षक, मंडल कारा, गढ़वा	06 मार्च 2010 से अक्टूबर 2011	10	187.30
6	अधीक्षक, एल.एन.जे.पी.एन., केन्द्रीय कारा, हजारीबाग	31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	7	581.80
7	अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा	25 जनवरी 2010 से 19 मार्च 2012	27	310.01
8	अधीक्षक, बी.एम.सी.जे., राँची	14 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012	16	174.03
9	अधीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा	26 फरवरी 2010 से 27 दिसम्बर 2011	12	1417.48
	कुल (ब)		**108**	**30445.35**
स.	ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी.(विशेष प्रमंडल) विभाग			
1	उपायुक्त, चतरा	30 मार्च 2010 से 30 मार्च 2011	2	398.08
2	उप-विकास आयुक्त, दुमका	28 मार्च 2011 से 01 मार्च 2012	9	1600.00
3	उप-विकास आयुक्त, गुमला	13 मार्च 2010 से 17 मार्च 2012	13	1800.00

परिशिष्ट - 3.4 क्रमशः...

4	उप-विकास आयुक्त, हजारीबाग	31 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2011	9	2304.00
5	उप-विकास आयुक्त, जमशेदपुर	09 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011	7	1344.00
6	उप-विकास आयुक्त, राँची	01 अक्टूबर 2010 से 29 नवम्बर 2011	11	1642.00
7	उपायुक्त, राँची	03 मार्च 2011 से 29 मार्च 2012	9	128.27
8	उप-विकास आयुक्त, चाईबासा	11 फरवरी 2010 से 04 फरवरी 2012	5	1286.52
कुल(स)			**65**	**10502.87**
सकल योग(अ+ब+स)			**223**	**110953.73**

परिशिष्ट- 3.5
झा.पु.आ.नि.सि. द्वारा बचत खाते में रखी गई निधियाँ
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निधियाँ जिसके द्वारा हस्तांतरित की गई	उद्देश्य	बैंक का नाम जिसमें राशि रखी गई	बैंक में जमा करने की तारीख	राशि
1	महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण एवं प्रावधानिकीकरण)	पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा में एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों और पुलिस लाइन का निर्माण	पंजाब नेशनल बैंक, राँची	16.03.2012	20.00
		पी.टी.सी., हजारीबाग में विभिन्न कार्य	भारतीय स्टेट बैंक, हटिया	15.02.2010	2.00
		लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह तथा कोडरमा में पुलिस लाइन का निर्माण	-वही-	15.02.2010	8.00
		गृह रक्षा वाहिनी(फेज 1) के लिये केन्दीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	-वही-	15.02.2010	0.55
		गृह रक्षा वाहिनी(फेज 1) के लिये केन्दीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	-वही-	15.02.2010	0.15
		केन्द्रीय पुलिस अस्पताल में प्रशिक्षण के लिये मूलभूत सुविधाओं नये थाना भवन में एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	15.02.2010	7.65
		-वही-	-वही-	15.02.2010	7.25
		एल.एस/यू.एस. क्वार्टरों का निर्माण	-वही-	25.02.2010	10.00
		-वही-	-वही-	25.02.2010	10.00
	कुल				**65.60**
2	पुलिस अधीक्षक, खूँटी	खूँटी जिला में कोबरा कैम्प के लिये दो इकाई पोर्टेबल हट्स का निर्माण	पंजाब नेशनल बैंक, राँची	11/2010	1.09
सकल कुल					**66.69**

परिशिष्ट- 4.1

(संदर्भ कंडिका 4.1 पृष्ठ 57)

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

विभाग	वर्ष 2010-11 तक (2009-10 तक अनुमोदित की जी.आई.ए)		2011-12 के दौरान (2010-11 तक अनुमोदित जी.आई.ए.)		बकाया उ.प्र.प. की संख्या	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उद्योग	441	1057.45	49	561.92	490	1619.37
मानव संसाधन	277	1127.20	49	120.34	326	1247.54
सहकारिता	63	139.42	63	123.01	126	262.43
पशुपालन	65	21.70	8	7.97	73	29.67
स्वास्थ्य	9	76.55	3	50.67	12	127.22
कल्याण	96	84.16	32	100.28	128	184.44
कृषि	61	50.56	4	8.70	65	59.26
भू-राजस्व	2	0.63	0	0.00	2	0.63
शहरी विकास	2808	700.78	837	235.46	3645	936.24
अन्य	486	1227.26	379	1241.98	865	2469.24
कुल	**4308**	**4485.71**	**1424**	**2450.33**	**5732**	**6936.04**

परिशिष्ट- 4.2

(संदर्भ कंडिका 4.2.1 पृष्ठ 58)

सी.ए.जी. डी.पी.सी. अधिनियम के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित किये गये इकाईयों की सूची

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
1	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति(रा.खे.आ.स.), मोराबादी, रॉची	रॉची	वार्षिक	2009-10
2	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	बोकारो	वार्षिक	2006-07
3	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	चाईबासा	वार्षिक	2011-12
4	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	चतरा	वार्षिक	2006-07
5	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	डालटेनगंज	वार्षिक	2011-12
6	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	देवघर	वार्षिक	2010-11
7	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	धनबाद	वार्षिक	2006-07
8	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	दुमका	वार्षिक	2008-09
9	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गढ़वा	वार्षिक	2006-07
10	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गोड्डा	वार्षिक	2011-12
11	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गुमला	वार्षिक	2006-07
12	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	हजारीबाग	वार्षिक	2007-08
13	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	जमशेदपुर	वार्षिक	2011-12
14	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	जामताड़ा	वार्षिक	2006-07
15	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	खूँटी	वार्षिक	2006-07
16	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	कोडरमा	वार्षिक	2006-07
17	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	लातेहार	वार्षिक	2006-07
18	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	लोहरदगा	वार्षिक	2011-12
19	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	पाकुड़	वार्षिक	2008-09
20	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	रामगढ़	वार्षिक	2011-12
21	मानव संसाधन विकास	निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, परिषद्	रॉची	वार्षिक	2007-08
22	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	रॉची	वार्षिक	2006-07
23	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	साहेबगंज	वार्षिक	2006-07
24	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	सरायकेला	वार्षिक	2006-07
25	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	सिमडेगा	वार्षिक	2009-10
26	मानव संसाधन विकास	जिला योजना पदाधिकारी, एस.एस.ए.	गिरिडीह	वार्षिक	2006-07
27	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	बोकारो	वार्षिक	2008-09
28	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	चतरा	वार्षिक	2008-09
29	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	देवघर	वार्षिक	2011-12
30	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	धनबाद	वार्षिक	2011-12
31	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	दुमका	वार्षिक	2011-12
32	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पूर्वी सिंहभूम	वार्षिक	2011-12
33	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गढ़वा	वार्षिक	2008-09
34	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गिरिडीह	वार्षिक	2011-12
35	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गोड्डा	वार्षिक	2008-09

परिशिष्ट - 4.2 क्रमशः...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
36	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	गुमला	वार्षिक	2011-12
37	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	हजारीबाग	वार्षिक	2008-09
38	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	जामताड़ा	वार्षिक	2008-09
39	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	खूँटी	वार्षिक	2008-09
40	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	कोडरमा	वार्षिक	2008-09
41	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लातेहार	वार्षिक	2008-09
42	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	लोहरदगा	वार्षिक	शून्य*
43	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पाकुड़	वार्षिक	2008-09
44	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पलामू	वार्षिक	2008-09
45	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	राँची	वार्षिक	2009-10
47	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची	राँची	वार्षिक	2011-12
48	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सरायकेला-खरसावाँ	वार्षिक	2008-09
49	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	सिमडेगा	वार्षिक	2008-09
50	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति (प्रजनन शिशु स्वास्थ्य समिति)	पश्चिमी सिंहभूम	वार्षिक	2008-09
51	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	प्राचार्य, रिनपास, काँके	राँची	वार्षिक	2006-07
52	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	झारखण्ड एड्स नियंत्रण समिति, राँची	राँची	वार्षिक	2001-02
53	कल्याण	निदेशक, भारत सेवा श्रम संघ, घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम	वार्षिक	2011-12
54	कल्याण	निदेशक, भारत सेवा श्रम संघ, सोनारी	जमशेदपुर	वार्षिक	2007-08
55	कल्याण	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	वार्षिक	2006-07
56	कल्याण	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	वार्षिक	2009-10
57	कल्याण	झारखण्ड महिला समाख्या समिति(जे.एम.एस.एस.), कडरू, राँची	राँची	वार्षिक	2006-07
58	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान	राँची	वार्षिक	शून्य*

परिशिष्ट - 4.2 क्रमशः...

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	लेखापरीक्षा की अवधि	तिथि से बकाया लेखा
59	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	बोकारो	वार्षिक	शून्य*
60	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चतरा	वार्षिक	2010-11
61	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	देवघर	वार्षिक	2009-10
62	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	धनबाद	वार्षिक	शून्य*
63	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	दुमका	वार्षिक	2010-11
64	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	वार्षिक	2011-12
65	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	वार्षिक	2011-12
66	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	वार्षिक	शून्य*
67	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	वार्षिक	2008-09
68	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	गुमला	वार्षिक	2010-11
69	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	वार्षिक	2008-09
70	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	वार्षिक	2011-12
71	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	वार्षिक	शून्य*
72	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	वार्षिक	शून्य*
73	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	पलामू	वार्षिक	2010-11
74	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	राँची	वार्षिक	2005-06
75	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	वार्षिक	2005-06
76	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	वार्षिक	2009-10
77	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	वार्षिक	2011-12
78	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	वार्षिक	शून्य*
79	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	वार्षिक	2010-11
80	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	लातेहार	वार्षिक	2010-11
81	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	वार्षिक	2010-11
82	ग्रामीण विकास	प्रबंध निदेशक, डी.आर.डी.ए.	खूँटी	वार्षिक	2007-08

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के कार्यालय में धारित स्थाई लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

**2011-12 तक सौंपे गये लेखे*

परिशिष्ट- 4.3

हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के मामलों का विभागवार ब्यौरा

(संदर्भ कंडिका 4.3. पृष्ठ 59)

क्र.सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	ग्रामीण विकास विभाग	2	0	2	21.90
2	मत्स्य	2	0	2	14.24
3	उद्योग विभाग	1	0	1	1.21
4	योजना एवं विकास विभाग	1	0	1	4.58
	कुल	**6**	0	**6**	**41.93**

परिशिष्ट -5.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (y) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/प्राचल की वृद्धि दर (y)
वृद्धि की दर (बृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/ गत वर्ष की राशि) -1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्रप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय।
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अत: चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिरूपनी की प्रचूरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था का वृद्धि पर ब्याज दर या लोक ऋण लोक उधार से अधिक हो इससे, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य हो धनात्मक हो या औसत रूप से ऋणात्मक हो। दिया गया है कि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुण दर विस्तार) ऋण स्थिरीकरण के शर्त के अनुसार अगर मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जायेगा। दूसरी तरफ अगर प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात बढता रहेगा और अगर घनात्मक हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. स्थिर रहेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रयाप्ता	राज्य का बढा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ बढ़े हुए ब्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुऐ ब्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने सक्षम हो ।

परिशिष्ट - 5.1 क्रमशः...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन +ब्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरूद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानों या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानों से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायो	स्वायत्त निकायों (साधारणत: पंजीकृत समितियों एवं सांविधिक निगमों) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वाहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के दखलन्दाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते है।
वचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्त्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मण्डल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है एवं समय-समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मण्डल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग है जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि) , शामिल है।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋणदाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है जिसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्त्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आह्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5 वें भाग तथा संभावित आह्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।

परिशिष्ट - 5.1 क्रमशः...

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगो से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उदग्रहित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि मे जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक ईकाई के विर्नियोग से अन्य इस प्रकार के ईर्काई में निधियों के स्थान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानो का अर्भ्यपण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानो एवं विनियोगो ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष मे उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नही रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के उपबन्धो के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उचन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदे जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नही लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचन्त लेखा, क्षेत्र में उचन्त एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मागदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचन्त लेखे शीर्ष में नही लेना चाहिए लेकिन "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वितीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो समीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी. ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ.एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियॉ
एस.एण्ड डब्ल्यू.	वेतन और मजदूरियॉ
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	तेरहवें वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर